मई, 2014

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान-संपादक

अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक

डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 84 –
विकृत चित्तता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों
तथा अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने के पूर्ववर्ती और
पश्चात्वर्ती समय के आचरण, की गहनतापूर्वक संवीक्षा से
यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त, वह कार्य जो वह कर
रहा है की प्रकृति दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है,
जानने में असमर्थ है, वहां अभियुक्त विकृत चित्तता का
फायदा पाने का दायी होगा ।

सीताराम हीरामन जोपाले बनाम महाराष्ट्र राज्य 721

संसद् के अधिनियम

भविष्य निधि अधिनियम, 1925 का हिन्दी में
प्राधिकृत पाठ (1) – (10) क्रमशः

पृष्ठ संख्या 593 – 744

(2014) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दंडिक निर्णय पत्रिका – मई, 2014 (पृष्ठ संख्या 593 – 744)

उच्च न्यायालय दंडिक निर्णय पत्रिका

मई, 2014

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	593
परवेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	662
विजय वासंत सावंत (श्रीमती) बनाम सुश्री शुभांगी शिवलिंग परब और अन्य	686
सचिन विट्ठल बोरहडे और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य	691
सरस्मिथा शर्मा (श्रीमती) बनाम राजस्थान राज्य	733
सीताराम हीरामन जोपाले बनाम महाराष्ट्र राज्य	721
हबीब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य	647

संसद् के अधिनियम

भविष्य निधि अधिनियम, 1925 का हिन्दी में प्राधिकृत
पाठ

(1) – (10) क्रमशः

संपादक-मंडल

श्री प्रेम कुमार मल्होत्रा, सचिव, विधायी विभाग	श्री लालजी प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधान संपादक, वि.सा.प्र.
श्रीमती शारदा जैन, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग	श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.
डा. विजय नारायण मणि, अधिवक्ता, (पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.	श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय, प्रधान संपादक
प्रो. डा. वैभव गोयल, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड)	श्री महमूद अली खां, संपादक
डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल, विधि विभाग, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	श्री जुगल किशोर, संपादक
डा. ऋषि पाल सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड	डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय, संपादक

सहायक संपादक	: सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान
उप-संपादक	: सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 12

वार्षिक : ₹ 135

© 2014 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग),
भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है। इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है। तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटोरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

**विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधि अधिनियम,
2005 (2005 का 43)**

– धारा 19 – संरक्षण आदेश – जहां परिवादी-पत्नी द्वारा अपने पति और सास-ससुर के विरुद्ध उत्पीड़न और दहेज मांग से संबंधित अभिकथन वर्ष 2008 में पति द्वारा विवाह-विच्छेद अर्जी फाइल करने के पश्चात् किए गए तथा पत्नी के सभी अभिकथन सितंबर, 2004 जब से वह अपने ससुराल में नहीं रह रही है, से चार वर्ष पूर्व के हैं और अस्पष्ट तथा सतही हैं तथा समस्त दृष्टांत वर्ष 2004 का है जबकि अधिनियम, 2006 में प्रवर्तित हुआ, वहां परिवादी द्वारा फाइल किया गया परिवाद अस्वीकार किए जाने योग्य है।

**विजय वासंत सावंत (श्रीमती) बनाम सुश्री शुभांगी
शिवलिंग परब और अन्य 686**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2)

– धारा 256(2), 258 और 302 – परिवादी की मृत्यु – मात्र परिवादी की मृत्यु पर परिवादी द्वारा फाइल की गई आपराधिक कार्यवाहियां स्वतः समाप्त नहीं हो जाती बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति या अभियोजन अभिकरण द्वारा कार्यवाही संचालित करने की अनुज्ञा देने की शक्ति प्राप्त है।

हबीब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

647

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 84 – विकृत चित्तता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियुक्त द्वारा अपराध किए

(ii)

जाने के पूर्ववर्ती और पश्चात्वर्ती समय के आचरण, की गहनतापूर्वक संवीक्षा से यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त, वह कार्य जो वह कर रहा है की प्रकृति दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, वहां अभियुक्त विकृत चित्तता का फायदा पाने का दायी होगा ।

सीताराम हीरामन जोपाले बनाम महाराष्ट्र राज्य

721

– धारा 300 – हत्या – वध करने के आशय से अचानक झगड़ा किया जाना – मृतका के पति द्वारा मृतका के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट किया जाना – उसके द्वारा किसी पराए व्यक्ति के घर में आने-जाने का प्रकटीकरण और यह घोषणा किया जाना कि वह मृतका के गर्भस्थ शिशु का पिता नहीं है – अभियुक्तों द्वारा मृतका की हत्या अकस्मात् प्रकोपनवश नहीं बल्कि सुनियोजित थी ।

सचिन विट्ठल बोरहडे और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

691

– धारा 300 और 376 – बलात्संग और हत्या – जहां अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य तथा पारिस्थितिक तथ्यों और साक्ष्यों से एकमात्र यह निष्कर्ष निकलता हो कि अभियुक्त ने मृतका को अकेला पाकर वासना से वशीभूत होकर गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया और बलात्संग के पश्चात् उसकी हत्या कर दी वहां मामला विरल से विरलतम की कोटि में न आने के कारण अभियुक्त को बलात्संग और हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा ।

गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

593

– धारा 302 और 307 – हत्या और हत्या का प्रयास – क्षतिग्रस्त साक्षियों और मृतक के शरीर पर पहुंची क्षतियों की प्रकृति हेतु अभियुक्त की गिरफ्तारी, हथियार की बरामदगी और अभियुक्त के प्रकटन कथन से युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन कथन साबित होने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने किसी भी कीमत पर आक्रामक प्रक्रम पर हत्या कारित की, अतः अभियुक्त हत्या और हत्या के प्रयास के अपराध का दायी है ।

परवेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

662

– धारा 406, 498-क और 323 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 468] – यदि मामले में परिसीमा की अवधि समाप्त हो गई है तो उस मामले का संज्ञान लेना वर्जित है – मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406 व 323 के अधीन अपराध हेतु अधिकतम सजा तीन वर्ष है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में उपबंधित परिसीमा की दृष्टि से इन अपराधों के लिए संज्ञान तीन वर्ष समाप्ति के पश्चात् नहीं लिया जा सकता है अतः लिया गया संज्ञान परिसीमा से परे होने के कारण अपास्त किया जाता है ।

सरस्मिथा शर्मा (श्रीमती) बनाम राजस्थान राज्य

733

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – मृतका का यह कथन कि दोनों अभियुक्तों ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ोला और आग लगा दी और मृतका द्वारा अपनी माता को किया गया मौखिक मृत्युकालिक कथन कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और सास ने उसकी मृत्यु कारित की,

कथन को सत्य, भरोसेमंद और स्वैच्छिक पाते हुए, अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायोचित और तर्कसंगत है ।

**सचिन विट्ठल बोरहडे और एक अन्य बनाम
महाराष्ट्र राज्य**

691

– धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – मृतका द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन में स्पष्ट किया जाना कि उसके पति और ससुर ने उसको जलाया – अन्य साक्षियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किया जाना कि मृतका को निरंतर उत्पीड़न और क्रूरता के अधीन रखा गया – यह सोचसमझकर किया गया अपराध है – विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को आजीवन कारावास द्वारा दंडित किया जाना उचित है ।

**सचिन विट्ठल बोरहडे और एक अन्य बनाम
महाराष्ट्र राज्य**

691

– धारा 106 – सबूत का भार – जब अभियुक्त को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया हो और अभियुक्त हत्या के ठीक पश्चात् घटनास्थल से भाग गया तथा मृतक के रक्त के धब्बे अभियुक्त के कपड़ों पर पाए गए हों तो उक्त धारा के अधीन अपनी निर्दोषिता सिद्ध न कर पाने की दशा में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित और तर्क संगत है ।

सीताराम हीरामन जोपाले बनाम महाराष्ट्र राज्य

721

(2014) 1 दा. नि. प. 593

इलाहाबाद

गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार*

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 13 अगस्त, 2013

न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति बच्चू लाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 और 376 – बलात्संग और हत्या – जहां अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य तथा पारिस्थितिक तथ्यों और साक्ष्यों से एकमात्र यह निष्कर्ष निकलता हो कि अभियुक्त ने मृतका को अकेला पाकर वासना से वशीभूत होकर गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया और बलात्संग के पश्चात् उसकी हत्या कर दी वहां मामला विरल से विरलतम की कोटि में न आने के कारण अभियुक्त को बलात्संग और हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा ।

अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू ने दिनांक 30.1.2007 को समय 18.10 बजे थाना भुता, जिला बरेली में एक तहरीर संजू भटनागर से लिखवाकर इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आज दिनांक 30.1.2007 को लगभग 2.00 बजे उसकी लड़की कुमारी सोनी उम्र लगभग चौदह वर्ष, उसकी मां श्रीमती रामश्री, उसका लड़का नितिन, लड़की ईलू एवं कंचन के साथ खेत में पुआल लेने गई थी । उसकी मां ने सोनी को पुआल लेकर घर भेज दिया । थोड़ी देर बाद उसकी मां, उसका लड़का नितिन व लड़कियां ईलू एवं कंचन पुआल लेकर अपने खेत से वापस जब घर आ रही थी तभी रास्ते में राम गुलाम के गन्ने के खेत से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी एवं पुआल की गठरी गन्ने के खेत के कोने पर पड़ी थी । चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां व उसके बच्चे आवाज की तरफ गए तो देखा कि गुड्डू गंगवार पुत्र राम गुलाम निवासी ग्राम गजनेरा थाना भुता, जिला

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

बरेली गन्ने के खेत से निकलकर भाग रहा था, अन्दर जाकर देखा तो सोनी खून से लथपथ गन्ने के खेत में पड़ी थी । यह घटना दिन के करीब साढ़े तीन बजे की है । उसकी मां ने व बच्चों ने घर आकर उसकी पत्नी को बताया । सूचना मिलने पर वह घर एवं मौके पर पहुंचा, जहां गांव के काफी लोग एकत्र थे । उसकी लड़की की लाश मौके पर पड़ी है । उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें । वादी मुकदमा कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू के द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर थाना भुता पर अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू गंगवार के विरुद्ध अपराध संख्या 37 वर्ष 2007 के अन्तर्गत धारा 302 भा. द. स. के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया । मामले की विवेचना की गई । अभियोजन साक्षी मोहम्मद याकूब खां, उप-निरीक्षक ने थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार यादव के निर्देशन में मृतका कुमारी सोनी के शव का पंचायतनामा तैयार किया तथा उससे संबंधित संलग्नक प्रपत्र चालान लाश, फोटो नाश, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी क्रमशः प्रदर्श क-7 लगायत प्रदर्श क-10 हैं । मृतका के शव को सर्व मोहर हालत में शव विच्छेदन हेतु भिजवाया गया । मौके पर पड़ी मृतका की चप्पल को कब्जा पुलिस में लेकर मृतका की मां के सुपुर्दगी में देकर उसकी फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार की गई । ढददददददद 31-1.2007 को मुखबिर की सूचना पर अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार को समय 16.00 बजे वीसलपुर बरेली रोड पर तिराहे के पास सड़क के दक्षिणी किनारे पर गिरफ्तार किया गया तथा उसके निशानदेही पर उसके खेत के मध्य में बने पुराने कुंए के पास झाड़ी के अंदर से मृतका की हत्या में प्रयुक्त हंसिया (आला कत्ल) बरामद किया गया । बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी है । विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी कब्जा पुलिस में लेकर सर्व मोहर कर उसकी फर्द तैयार की तथा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया । विद्वान् अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा उभय पक्ष को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार को धारा 376, 302 भा. द. स. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए धारा 376 भा. द. स. के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 15,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में वह तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा एवं धारा 302 भा. द. स. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह अपील योजित की है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले में कथित घटना के दिन, दिन में 2.00 बजे मृतका कुमारी सोनी अपनी दादी रामश्री, बहन ईलू, कंचन व भाई नितिन के साथ पुआल लेने खेत पर गई थी। अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री ने सबसे पहले पुआल का गट्टर बांधकर सोनी को घर वापस भेज दिया था। उसके बाद अभियोजन साक्षी ईलू, कंचन, नितिन व स्वयं पताई का गट्टर लेकर घर वापस आ रही थी तो उन्हें रास्ते में राम गुलाम के गन्ने के खेत से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी वहीं रास्ते में चकरोड पर मृतका की पुआल का गट्टर भी पड़ा हुआ था। चीखने-चिल्लाने की आवाज की ओर जाने पर उपरोक्त साक्षी ने यह देखा कि अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू **उर्फ** जितेन्द्र हाथ में हंसिया लेकर मृतका के शव के पास से भाग रहा था। अभियोजन साक्षी ईलू ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू **उर्फ** जितेन्द्र हाथ में खून से सना हंसिया लेकर लाश के पास से भाग रहा था। उसने लाश के पास जाकर देखा तो वहां पर सोनी मरी हुई पड़ी थी। मृतका कुमारी सोनी के शरीर पर पोस्टमार्टम के समय कटे हुए घाव पाए गए हैं जिन्हें डाक्टर ने हंसिया से आना सम्भव कहा है। ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया जाता है तथा प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से एक तर्क यह भी रखा गया है कि अभियोजन साक्षी ईलू तथा अभियोजन साक्षी रामश्री ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि जब वे खेत से गट्टर लेकर चली तो उन्हें सोनी सड़क पर चलती दिखाई दे रही थी। इसके बाद फिर मोड़ आ गया वह नहीं दिखी। इन साक्षियों ने जिस स्थान से सोनी को जाते हुए देखने का उल्लेख किया है उस स्थान से घटनास्थल वाला खेत इतनी दूरी पर नहीं है कि अपीलार्थी/अभियुक्त कुमारी सोनी को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने व बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दे। इतने कम समय में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ बलात्कार करने व उसके बाद उसकी हत्या कर देना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है। हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर अभियोजन साक्षी ईलू तथा अभियोजन साक्षी रामश्री की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभियोजन साक्षी ईलू तथा अभियोजन साक्षी रामश्री बच्ची व महिला है। वे अपने खेत से पताई लेकर आ रही थी और उन्होंने सोनी को पहले ही पुआल का गट्टर लेकर भेज दिया था। ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी ईलू तथा अभियोजन साक्षी रामश्री ने जो राम गुलाम के खेत के पास पहुंचकर चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी और आवाज पर खेत के अंदर जो जाने की बात कही है उस पर अविश्वास करने का कोई

कारण प्रतीत नहीं होता है । चूंकि कुमारी सोनी अभियोजन साक्षी ईलू तथा अभियोजन साक्षी रामश्री के पहले खेत से पुआल की गठरी लेकर घर के लिए चल दी थी । उसके बाद अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री व अन्य बच्चे पताई लेकर वापस घर आ रहे थे और यह घटना वाला खेत रास्ते से लगा हुआ है । ऐसी दशा में उनके द्वारा घटना वाले खेत (राम गुलाम के खेत) के पास पहुंचकर मृतका की चीख-पुकार सुनना व उसके चीखने-चिल्लाने की आवाज पर गन्ने के खेत में जाकर देखना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय हैं । मृतका कुमारी सोनी अभियोजन साक्षी ईलू की बहन थी और अभियोजन साक्षी रामश्री की पोती थी इसलिए इन साक्षियों द्वारा कुमारी सोनी की आवाज को पहचान लेना व उसके चीखने-चिल्लाने की आवाज पर जिस ओर से गन्ने के खेत में से चीखने-चिल्लाने की आवाज आ रही थी वहां पहुंचना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय है । ऐसी दशा में जो उपरोक्त दोनों साक्षियों के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को मृतका के लाश के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया गया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया जाता है । अभियोजन साक्षी ईलू ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र हाथ में खून का सना हंसिया लेकर लाश के पास से भाग रहा था । उक्त हंसिया को अपीलार्थी/अभियुक्त के निशानदेही पर दिनांक 31.1.2007 को पुलिस द्वारा बरामद भी किया गया तथा उक्त हंसिया (आला कत्ल) को रसायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजा गया था । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उक्त हंसिया (आला कत्ल) पर मानव रक्त पाया गया । ऐसी दशा में भी उपरोक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया जाता है । अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि लाश के पास बैठने के बिन्दु पर अभियोजन साक्षी ईलू तथा अभियोजन साक्षी रामश्री के बयानों में विरोधाभास है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू ने अपने बयान में यह बताया है कि घटनास्थल से वह उसकी दादी, भाई, बहन घर पर आए और अपनी मम्मी को घटना के बारे में जानकारी दी जबकि अभियोजन साक्षी रामश्री ने मौके पर ही रुके रहने का कथन किया है और अपने पोता, पोती (कंचन व नितिन) को घर भेजकर घटना की खबर देने की बात कही है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर उपरोक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य को पूर्णतः अविश्वसनीय मान लेना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । खासकर उस स्थिति में जब उपरोक्त दोनों साक्षियों की मौके पर उपस्थिति सिद्ध है । उक्त दोनों साक्षियों की सम्पूर्ण साक्ष्य से यही सिद्ध है कि उनके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखा गया है । हंसिया

पर खून लगा था । ऐसी दशा में मात्र उपरोक्त विसंगति के आधार पर अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है । उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है । अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में हंसिया का कोई उल्लेख नहीं है । अभियोजन साक्षी ईलू तथा अभियोजन साक्षी रामश्री द्वारा अपने बयान के अन्तर्गत धारा 161 द. प्र. स. में भी अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथ में हंसिया होने का उल्लेख नहीं किया गया है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी ईलू तथा अभियोजन साक्षी रामश्री का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और जो उन्होंने अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथ में हंसिया होने की बात कही है वह विचार-विमर्श के बाद कही है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथ में हंसिया होने या उसके द्वारा हंसिया से मृतका की हत्या कारित करना सिद्ध नहीं है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर अभियोजन साक्षी ईलू तथा अभियोजन साक्षी के साक्ष्य को पूर्णतः अविश्वसनीय मान लेना न्यायोचित नहीं है । उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अपने बयानों में अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है । अभियोजन साक्षी ईलू ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त खून से सना हंसिया लेकर मृतका के शव के पास से भाग रहा था और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कथित बरामद हंसिया (आला कत्ल) पर मानव रक्त पाया गया है । ऐसी दशा में साक्षियों ने जो अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के लाश के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि विवेचनाधिकारी ने अभियोजन साक्षी ईलू का बयान घटना के करीब 13 दिन बाद दिनांक 13.2.2007 को अंकित किया है । हमारे विचार से यदि विवेचनाधिकारी ने अभियोजन साक्षी ईलू का बयान विलम्ब से अंकित किया है तो मात्र उक्त आधार पर अभियोजन साक्षी ईलू की साक्ष्य को अविश्वसनीय मान लेने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यही साबित है कि कथित घटना के दिन अभियोजन साक्षी ईलू अपनी दादी रामश्री, मृतका कुमारी सोनी, भाई नितिन, व बहन कंचन के साथ पताई और पुआल लेने खेत पर गई थी । अभियोजन साक्षी रामश्री ने भी कथित घटना के दिन अभियोजन साक्षी ईलू को अपने साथ खेत पर पताई व पुआल लेने जाने की बात कही है और लौटते समय राम गुलाम के खेत से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर गन्ने के खेत में जिधर से चीखने-चिल्लाने की आवाज आ रही थी उस तरफ जाने का उल्लेख किया है

और अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को मृतका कुमारी सोनी के लाश के पास से हंसिया लेकर खेत से निकलकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है । ऐसी दशा में यही साबित है कि कथित घटना के समय ईलू भी अपनी दादी अभियोजन साक्षी रामश्री व भाई नितिन तथा बहन कंचन के साथ मौजूद थी और उसने भी चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर ईख के खेत में जाकर मृतका के शव के पास से अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को खून से सना हंसिया लेकर भागते हुए देखा गया है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी ईलू की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया जाता है और उपरोक्त के संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है । अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि अभियोजन साक्षी ईलू का आचरण स्वाभाविक नहीं है क्योंकि उसने मृतका के लाश के पास से कई बार घर जाने व उसके बाद पुनः घर से लाश के पास वापस आने का कथन किया है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर इस साक्षी की साक्ष्य को अविश्वसनीय मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस साक्षी ने अपने बयान में अपनी आयु 15 साल बताई है । उसका बयान दिनांक 11.2.2009 को अंकित किया गया है । यह घटना दिनांक 30.1.2007 की है । इससे यही जाहिर होता है कि घटना के समय इस साक्षी की आयु लगभग 13 वर्ष थी । चूंकि इस साक्षी की बहन की हत्या हुई थी इसलिए लाश के पास से उसका अपने घर जाना और घटना की सूचना देकर पुनः अपनी बहन के लाश के पास पहुंचना स्वाभाविक है यदि वह इस दौरान कई बार अपने घर अपनी मृतका बहन के लाश के पास से आई गई है तो उससे इस साक्षी की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त का मकान वादी के मकान के पहले रास्ते में पड़ता है यदि अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतका की हत्या कारित की होती तो वादी तथा उसके परिवार के लोग अपीलार्थी/अभियुक्त के घर पूछताछ करने भी जा सकते थे और जब इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी तो गांव के लोग भी विरोध स्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त के घर जाकर उन्हें क्षति पहुंचा सकते थे । हमारे विचार से अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि घटना के समय साक्षियों ने अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देख लिया था और अपीलार्थी/अभियुक्त को पहचान लिया था । अपीलार्थी/अभियुक्त उनके गांव का रहने वाला भी है । ऐसी दशा में जब अभियुक्त की पहचान हो चुकी थी तो यह आवश्यक नहीं था कि वादी या गवाहान अपीलार्थी/अभियुक्त के घर पूछताछ करने जाते या विरोध जताने जाते । घटना के संबंध में वादी द्वारा विधिक कार्यवाही की गई है तथा

घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ऐसी दशा में घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है और न ही अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना पाई जाती है। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का लेखक संजू भटनागर वादी का सगा बहनोई है जो बरेली कचहरी में मुंशी का कार्य करता है उससे विचार-विमर्श करने के बाद गलत तरीके से अपीलार्थी/अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है। वादी के परिवार में चूंकि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और इस घटना में वादी की लड़की की हत्या हो गई थी इसलिए वादी को अपने रिश्तेदार/बहनोई संजू भटनागर को घटना की सूचना देना स्वाभाविक था और यदि इस घटना की तहरीर वादी के बहनोई संजू भटनागर द्वारा लिखी गई है तो मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। यदि अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा ही फंसाना होता तो वादी अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा मृतका की हत्या करने का भी उल्लेख कर सकता था तथा अभियोजन साक्षी ईलू व अभियोजन साक्षी रामश्री भी अपने बयान में अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के साथ बलात्कार करने व बलात्कार के बाद उसकी हत्या करते हुए देखने का उल्लेख कर सकती थी लेकिन गवाहान द्वारा जितनी घटना देखी गई है उसी का वर्णन किया गया है। ऐसी दशा में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में या घटना के संबंध में संदेह का कोई आधार नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि पंचायतनामा में अपीलार्थी/अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं है तथा न ही हथियार का उल्लेख किया गया है। हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर भी अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त को नामित किया गया है और घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईलू तथा साक्षी संख्या 3 रामश्री द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथ में हंसिया होने का उल्लेख किया गया है और हंसिया लेकर मृतका के शव के पास से भागते हुए देखने का उल्लेख किया गया है। पंचायतनामा में इस मामले के अपराध संख्या व धारा का उल्लेख है। ऐसी दशा में यदि पंचायतनामा में अपीलार्थी/अभियुक्त के नाम व हथियार का उल्लेख नहीं किया गया है तो मात्र उक्त आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल का जो नक्शा-नजरी तैयार किया है वह विश्वसनीय नहीं है। नक्शा-नजरी में

विवेचनाधिकारी ने अपीलार्थी/अभियुक्त को सी. स्थान पर बैठने का उल्लेख किया है और बी. स्थान पर मृतका की गठरी पड़ी होना दिखाया है तथा इसी बी. स्थान से मृतका को अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा पकड़ कर गन्ने के खेत में ए. स्थान पर ले जाने का उल्लेख किया गया है लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को घटना के पहले सी. स्थान पर बैठा देखा गया हो या किसी व्यक्ति ने मृतका को पकड़ कर गेहूं व गन्ने के बीच की मेड़ से खींचते हुए गन्ने के खेत में ले जाते हुए देखा हो । ऐसी दशा में घटनास्थल का जो नक्शा बनाया गया है वह विश्वसनीय नहीं है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में संदेह का कोई आधार नहीं पाया जाता है । कथित घटनास्थल वाला खेत राम गुलाम का है जो अपीलार्थी/अभियुक्त का पिता है और इसी खेत के पास से चकरोड निकलता है तथा इसी चकरोड से मृतका अपने घर जा रही थी व इसी खेत में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका को खींचकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया है और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है । साक्षियों द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखा गया है । ऐसी दशा में मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । बचाव साक्षी रामेश्वर दयाल ने अपने बयान में यह कथन किया है कि उसके गांव में कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू रहते हैं 30 जनवरी, 2007 को शाम 6.00 बजे गांव में खबर फैली कि राम गुलाम के खेत के पास पप्पू की लड़की की लाश पड़ी है । पूरा गांव इकट्ठा हो गया । पप्पू राइस मील पर काम करता था वहां खबर करके बुलवाया गया । पुलिस आ गई उस समय यह जानकारी नहीं हुई कि घटना किसने की है । पुलिस वाले लाश को सील करके ले गए । पप्पू ने अपने बहनोई संजू को बरेली से बुलवाया । संजू कचहरी पर मुंशीगीरी करता है । छः बजे के डेढ़ घण्टे के बाद संजू भटनागर गांव में आए । उस समय तक यह जानकारी नहीं हुई थी कि कौन मार गया । पुलिस वालों ने उस समय गुड्डू गंगवार को नहीं पकड़ा था । बाद में जानकारी हुई कि गुड्डू गंगवार के खिलाफ पुलिस ने वादी के साथ मिलकर झूठा मुकदमा बना दिया । उपरोक्त बचाव साक्षियों की सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उपरोक्त दोनों साक्षियों के साक्ष्य से घटना के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है तथा इस प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । प्रथम यह कि बचाव साक्षी संख्या 1 राम गुलाम स्वयं अभियुक्त का पिता है । यदि इस साक्षी को व उसके लड़के (गुड्डू उर्फ जितेन्द्र) को पुलिस वाले पकड़ कर थाने ले गए थे और उसके उक्त लड़के का चालान इस मुकदमे में कर दिया था तो यह साक्षी छूटने के बाद भी इस

संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा सकता था लेकिन इस साक्षी ने इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि वह थाने से छूटने के बाद अपने लड़के गुड्डू को पकड़ने के बारे में किसी उच्चाधिकारी को सूचना नहीं दी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी स्वीकार किया है कि उसके तीन बेटे हैं उसके दो अन्य बेटों के नाम हरीश कुमार व सुरेन्द्र कुमार है। हमारे विचार से यदि इस घटना में अपीलार्थी/अभियुक्त की भूमिका न होती तो पुलिस इस साक्षी के उक्त पुत्रों से भी पूछताछ कर सकती थी और उन्हें भी थाने ले जा सकती थी लेकिन पुलिस द्वारा इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी दशा में इस साक्षी का कथन स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। बचाव साक्षी रामेश्वर दयाल ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि जितेन्द्र उर्फ गुड्डू उसके ताऊ के लड़के का लड़का है। उसका और जितेन्द्र उर्फ गुड्डू का घर पास-पास में है। चूंकि यह साक्षी भी अपीलार्थी/अभियुक्त के खानदान व परिवार का व्यक्ति है। इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि घटना के संबंध में कोई संदेह व्यक्त किया जा सके। उपरोक्त दोनों बचाव साक्षियों की सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त हम इसी मत के हैं कि उनके साक्ष्य से इस मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया जाना साबित नहीं होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू के साक्ष्य में यह आया है कि मौके पर संजू भटनागर 5.45 बजे शाम को पहुंच गए थे। संजू भटनागर का घर घटनास्थल से लगभग 22 कि.मी. दूर बताया गया है और उसे मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचना बताया गया है। हमारे विचार से घटनास्थल पर संजू भटनागर का 5.45 बजे पहुंचना स्वाभाविक है। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट शाम 6.10 बजे थाने पर दर्ज हो चुकी थी। ऐसी दशा में उपरोक्त दोनों बचाव साक्षियों का यह कहना कि वादी के बहनोई संजू भटनागर मौके पर रात्रि के 7.30 बजे पहुंचे इसमें कोई सत्यता नहीं रह जाती है। साक्ष्य में यह आया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखा गया था और अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद भी किया गया है। ऐसी दशा में उपरोक्त दोनों बचाव साक्षियों का यह कहना कि पुलिस द्वारा मृतका के शव को सील करने तक घटना कारित करने वाले व्यक्ति की जानकारी नहीं थी इसमें कोई वास्तविकता नहीं रह जाती है। अभियोजन साक्षियों के बयान में इस तरह की कोई बात नहीं आई है जिससे अपीलार्थी/अभियुक्त से वादी या उसके परिवार की कोई रंजिश होने की बात स्वीकार की जा सके बल्कि पत्रावली पर जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उससे एक मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि यह घटना अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा ही कारित की

गई थी । ऐसी दशा में प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि मृतका के सलवार पर मल पाए जाने का उल्लेख है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका की सलवार उतारना या उस पर शुक्राणु छोड़ना विश्वसनीय नहीं रह जाता है । हमारे विचार से उपरोक्त तर्क में भी कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मृतका की सलवार पंचायतनामे के समय उसके शव पर पड़ी पाई गई है । मृतका की योनि और हाईमन दोनों फटे हुए पाए गए हैं । इससे भी यही साबित है कि मृतका के साथ बलात्कार किया गया और मृतका की सलवार पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में शुक्राणु भी पाए गए हैं । ऐसी दशा में यदि मृतका की सलवार में मल भी पाया गया है तो मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । उपरोक्त समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों से एकमात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि यह घटना अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा ही कारित की गई थी और उसने ही कथित घटना के समय कुमारी सोनी को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा बलात्कार करने के पश्चात् उसकी हत्या कर दी । इस तरह पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से श्रृंखलाबद्ध तरीके से यह भली भांति सिद्ध है कि कथित घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार ने मृतका के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के पश्चात् उसकी हत्या कर दी । तदनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 376 व 302 भा. द. स. संदेह से परे सिद्ध है । ऐसी स्थिति में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा जो अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 376 व 302 भा. द. स. के अन्तर्गत दोषी पाया गया है उसमें हम कोई विधिक त्रुटि व अनियमितता नहीं पाते हैं । तदनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त की धारा 376 व 302 भा. द. स. के अन्तर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है । जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा विकल्प में यह भी तर्क रखा गया कि यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है । यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है यदि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित की गई है तो वह वासना को नियंत्रित न कर पाने के कारण हुई । ऐसी दशा में यह प्रकरण मृत्यु दण्ड से दण्डित किए जाने योग्य नहीं है । उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतका सोनी की आयु लगभग 14 वर्ष बताई गई है । वह कथित घटना के दिन अपनी दादी रामश्री, बहन ईलू, कंचन तथा भाई नितिन के साथ खेत पर पुआल व पताई लेने गई थी । मृतका की दादी रामश्री ने मृतका सोनी को सबसे पहले पुआल का गट्टर बांधकर घर भेज दिया था और

मृतका पुआल का गटठर लेकर अकेले घर वापस आ रही थी तो कथित घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतका कुमारी सोनी को अकेला पाकर अपने गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा बलात्कार के पश्चात् उसकी हत्या कर दी । अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द. प्र. स. में अपनी आयु 25 वर्ष बताई है तथा उसका उक्त बयान दिनांक 16.7.2010 को अंकित किया गया था । इससे यही जाहिर होता है कि कथित घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त की आयु लगभग साढ़े 21 वर्ष थी तथा अपीलार्थी/अभियुक्त की आयु लगभग साढ़े 21 वर्ष थी । अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतका कुमारी सोनी को अकेला पाकर वासना से वशीभूत होकर मृतका कुमारी सोनी को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी । ऐसी दशा में प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है । यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है । अपीलार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है तथा इस तरह की भी परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं जिससे कि भविष्य में अपीलार्थी/अभियुक्त के जीवन में कोई सुधार न हो सके । अतएव प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त को मृत्यु दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा । (पैरा 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 58, 59, 63, 64, 65, 69, 70, 78 और 79)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[1984]	[1985] 1 उम. नि. प. 995 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 : शरद बिरदीचन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य ।	66
--------	---	----

निर्दिष्ट निर्णय

[2013]	(2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 438 : सुनील क्लीफोर्ड डिनायल बनाम पंजाब राज्य ;	33,71
[2013]	(2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1136 : जगरूप सिंह बनाम पंजाब राज्य ;	33,71
[2012]	ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 786 : कैलाश गौर बनाम असम राज्य ;	31

[2012]	2012 (77) ए. सी. सी. 201 : अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ;	33,71,72
[2012]	(2012) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 970 : उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार ;	33,71
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 37 : राजेन्द्र प्रहालत्रों वाशनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य ;	33,71,75
[2011]	(2011) 2 एस. सी. सी. 764 : रमेश भाई चन्दू भाई राथौड़ बनाम गुजरात राज्य ;	33,71,74
[2010]	2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3289 : निरंजन पांजा बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य ;	29,52
[2007]	ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 132 : अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य ;	76
[2004]	(2004) 6 एस. सी. सी. 158 : विलास पंडुरांग पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य ;	33,71
[2003]	(2003) 8 एस. सी. सी. 93 : अमित उर्फ अम्मू बनाम महाराष्ट्र राज्य ;	77
[2002]	(2002) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 630 : पंजाब राज्य बनाम जुगराज सिंह और अन्य ;	40
[2001]	(2001) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 248 : राज्य एन. सी. टी. बनाम सुनील ;	33,71
[2000]	(2000) 40 ए. सी. सी. 224 : महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश ;	33,71
[1995]	(1995) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 60 : सुरेश चन्द्र बाहरी बनाम बिहार राज्य ।	55,71

कैपिटल दाण्डिक अपील संख्या : 7459 वर्ष 2010.

अपीलार्थी गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार
प्रति

विपक्षी राज्य उत्तर प्रदेश

एवं

संदर्भ संख्या 12 वर्ष 2010

माननीय अमर सरन, न्यायमूर्ति

माननीय बच्चू लाल, न्यायमूर्ति

(माननीय बच्चू लाल, न्यायमूर्ति द्वारा प्रदत्त निर्णय)

1. अपीलार्थी गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार ने यह अपील श्री राजेन्द्र सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 6 बरेली द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 630 वर्ष 2008 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.10.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा उसे धारा 376 भा. द. स. के अन्तर्गत दोषसिद्धि के आधार पर आजीवन कारावास एवं 15,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में वह तीन वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास का दण्ड भुगतेगा तथा धारा 302 भा. द. स. के अन्तर्गत दोषसिद्धि के आधार पर मृत्यु दण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

2. अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा मृत्यु दण्ड के पुष्टि हेतु संदर्भ संख्या 12 वर्ष 2010 प्रेषित किया गया है।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में, इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू ने दिनांक 30.1.2007 को समय 18.10 बजे थाना भुता, जिला बरेली में एक तहरीर संजू भटनागर से लिखवाकर इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आज दिनांक 30.1.2007 को लगभग 2.00 बजे उसकी लड़की कुमारी सोनी उम्र लगभग चौदह वर्ष, उसकी मां श्रीमती रामश्री, उसका लड़का नितिन, लड़की ईलू एवं कंचन के साथ खेत में पुआल लेने गई थी। उसकी मां ने सोनी को पुआल लेकर घर भेज दिया। थोड़ी देर बाद उसकी मां, उसका लड़का नितिन व लड़कियां ईलू एवं कंचन पुआल लेकर अपने खेत से वापस जब घर आ रही थी तभी रास्ते में राम गुलाम के गन्ने के खेत से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी एवं पुआल की गठरी गन्ने के खेत के कोने पर पड़ी थी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां व उसके बच्चे आवाज की तरफ गए तो देखा कि गुड्डू गंगवार पुत्र राम गुलाम निवासी ग्राम गजनेरा, थाना भुता, जिला बरेली गन्ने के खेत से निकलकर भाग रहा था, अन्दर जाकर देखा तो सोनी खून से लथपथ गन्ने के खेत में पड़ी थी। यह घटना दिन के करीब साढ़े तीन बजे की है। उसकी मां ने व बच्चों ने घर आकर

उसकी पत्नी को बताया । सूचना मिलने पर वह घर एवं मौके पर पहुंचा जहां गांव के काफी लोग एकत्र थे । उसकी लड़की की लाश मौके पर पड़ी है । उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें ।

4. वादी मुकदमा कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू के द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना भुता पर अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू गंगवार के विरुद्ध अपराध संख्या 37 वर्ष 2007 अन्तर्गत धारा 302 भा. द. स. के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया । चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 है तथा कायमी मुकदमा से संबंधित जी. डी. की प्रति प्रदर्श क-5 है ।

5. मामले की विवेचना की गई । अभियोजन साक्षी संख्या 7 मोहम्मद याकूब खां, उप-निरीक्षक ने थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार यादव के निर्देश में मृतका कुमारी सोनी के शव का पंचायतनामा प्रदर्श क-6 तैयार किया तथा उससे संबंधित संलग्नक प्रपत्र चालान लाश, फोटो नाश, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी क्रमशः प्रदर्श क-7 लगायत प्रदर्श क-10 है । मृतका के शव को सर्व मोहर हालत में शव विच्छेदन हेतु भिजवाया गया । मौके पर पड़ी मृतका की चप्पल को कब्जा पुलिस में लेकर मृतका की मां के सुपुर्दगी में देकर उसकी फर्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क-12 तैयार की गई ।

6. दिनांक 31.1.2007 को मुखबिर की सूचना पर अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार को समय 16.00 बजे वीसलपुर बरेली रोड पर तिराहे के पास सड़क के दक्षिणी किनारे पर गिरफ्तार किया गया तथा उसके निशानदेही पर उसके खेत के मध्य में बने पुराने कुएं के पास झाड़ी के अंदर से मृतका की हत्या में प्रयुक्त हंसिया (आला कत्ल) बरामद किया गया । जिसकी फर्द प्रदर्श क-2 है तथा बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-14 है । विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी कब्जा पुलिस में लेकर सर्व मोहर कर उसकी फर्द प्रदर्श क-16 तैयार की तथा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी प्रदर्श क-13 तैयार किया ।

7. अभियोजन साक्षी संख्या 5 डाक्टर ए. एन. बोहरा वरिष्ठ परामर्शदाता जिला चिकित्सालय बरेली द्वारा मृतका कुमारी सोनी के शव का शव विच्छेदन दिनांक 31.1.2007 को समय 3.30 पी. एम. पर किया गया । डाक्टर के अनुसार, कुमारी सोनी की आयु 14 वर्ष थी । उसकी मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व हुई प्रतीत होती थी ।

8. वाह्य परीक्षण – मृतका सामान्य कद काठी की थी । आंख और मुंह अध खुला था । मृतका के शरीर के ऊपरी व निचले भाग में अकड़न मौजूद थी, सड़न नहीं थी । मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोटें पाई गई :-

“1. कटा हुआ घाव 5 सेमी. x 1 सेमी. x कार्टलेज एवं मसिल डीप जो गर्दन पर 3 सेमी. ऊपर छाती के हड्डी के ऊपर स्थिति था ।

2. कटा हुआ घाव 4 सेमी. x 1 सेमी. x मांस तक गहरा गर्दन पर दाहिनी ओर चोट नम्बर 1 से 1 सेमी. ऊपर की ओर था ।

3. कटा हुआ घाव 3 सेमी. x 1 सेमी. x ट्रेकिया तक गहरा गर्दन के दाहिनी तरफ चोट नम्बर 2 से 1 सेमी. ऊपर था ।

4. कटा हुआ घाव 3 सेमी. x 1 सेमी. x मांस तक गहरा थायराड प्रामिनेन्स के ऊपर था और चोट नं. 1 से 1 सेमी. ऊपर था ।

5. कटा हुआ घाव 3 सेमी. x 0.5 सेमी. x मांस तक गहरा गर्दन के दाहिनी तरफ चोट नं. 1 से आधा सेमी. नीचे था ।

6. कटा हुआ घाव 3 सेमी. x 0.5 सेमी. x ट्रेकिया तक गहरा चोट नं. 5 से आधा सेमी. नीचे की ओर था ।

7. कटा हुआ घाव 5 सेमी. x 2 सेमी. x केविटी डीप हमलाइकल्स से नीचे की ओर का पेट पर था घाव से आतें बाहर निकली हुई थीं ।

8. कटा हुआ घाव 1 सेमी. x 1/2 सेमी. पेट पर बाई तरफ चोट न. 7 से 1 सेमी. नीचे की ओर था ।

9. एक रगड़ का निशान 1-1/2 सेमी. x 1-1/2 सेमी. बाई अग्रबाहु के पीछे की तरफ कलाई के जोड़ से 1 सेमी. ऊपर की ओर था ।”

9. आन्तरिक परीक्षण – लैरिंग्स और ट्रेकिया कटी हुई थी तथा कैरोटिड आर्टिलीरीज दाहिने ओर कटी हुई थी । पैरोटोनियल कैबिटी में दो लीटर खून मौजूद था । दांत 14/14 थे । आमाशय में 150 ग्राम अधपचा खाना मौजूद था तथा छोटी बड़ी आतें कटी हुई थीं । बड़ी आंत में मल व गैसों थीं व गाल ब्लेडर आफ फुल था । यूट्रस में बच्चा नहीं था । योनि और हाईमन दोनों फटे हुए थे ।

10. मृतका की योनि से दो शीशे की स्लाइड्स पर योनि की गहराई पर स्वाव पर (Swavs) लेकर तैयार की गई थी । जिन्हें एक लिफाफे में रखकर सील किया गया था और इसे शव लाने वाले सिपाही को

पैथालाजिकल जांच हेतु पैथालाजी विभाग में देने हेतु दिया था । मृतका के शरीर से एक कुर्ता एक शमीज, एक सलवार, एक कलाबा एक मैटेलिक सिल्वर कलर की चूड़ी, दो सफेद मैटल के ईयर रिंग, पीले मैटल की नोज पिन एक हेयर क्लिप को कब्जे में लेकर सील करके शव लाने वाले सिपाही के सुपुर्द किया गया था । डाक्टर के अनुसार, मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण रक्त-स्राव व सदमा से हुई थी । डाक्टर ने बरवक्त मुआइना मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 अपने लेख एवं हस्ताक्षर में तैयार किया ।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 10 अजय कुमार यादव, थानाध्यक्ष/विवेचनाधिकारी ने विवेचना संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण करके तथा साक्ष्य संकलित कर अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-15 अन्तर्गत धारा 302/376/511 भा. द. स. न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

12. अपीलार्थी/अभियुक्त का मुकदमा विचारण हेतु मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बरेली के द्वारा दिनांक 24.5.2008 को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया ।

13. विद्वान् अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376/511 व 302 भा. द. स. के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए । तत्पश्चात् धारा 376/511 भा. द. स. के स्थान पर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा. द. स. के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया । अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा आरोपों से इनकार किया गया तथा परीक्षण की मांग की गई ।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में अभियोजन साक्षी संख्या 1 कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू (वादी मुकदमा), अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू (मृतका की बहन), अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री, अभियोजन साक्षी संख्या 4 राम गोपाल, अभियोजन साक्षी संख्या 5 डाक्टर ए. एन. बोहरा, अभियोजन साक्षी संख्या 6 श्री महिपाल वर्मा (आरक्षी), अभियोजन साक्षी संख्या 7 मोहम्मद याकूब खां, उप-निरीक्षक, अभियोजन साक्षी संख्या 8 कन्हैया लाल, उप-निरीक्षक, अभियोजन साक्षी संख्या 9 रजनेश पाल सिंह (आरक्षी) तथा अभियोजन साक्षी संख्या 10 अजय कुमार यादव, थानाध्यक्ष/विवेचनाधिकारी को परीक्षित कराया गया है ।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 1 कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू (वादी मुकदमा)

अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री तथ्य के साक्षी हैं ।

16. अभियोजन साक्षी संख्या 4 राम गोपाल अपीलार्थी/अभियुक्त के निशानदेही पर मृतका की हत्या में प्रयुक्त हंसिया (आला कत्ल) के बरामदगी का साक्षी है । इस साक्षी ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 31.1.2007 को मुलजिम गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को पकड़कर पुलिस ग्राम गजनेरा लाई थी और वहां से उसे व राजीव को पुलिस गिरफ्तार शुदा गुड्डू उर्फ जितेन्द्र के साथ उसके खेत पर लाई । जहां गुड्डू उर्फ जितेन्द्र ने अपने खेत में बने पुराना कुएं के पास झाड़ी में से खून से सना हुआ हंसिया निकाल कर दिया और कहा कि यह वही हंसिया है जिससे उसने सोनी की हत्या 30.1.2007 को की थी । उस दिन, दिन में 5.00 बजे शाम गुड्डू उर्फ जितेन्द्र ने हंसिया निकालकर पुलिस को दिया था । पुलिस ने मौके पर हंसिया कब्जे में लेकर कपड़े में रखकर सील सर्व मुहर किया । नमूना मुहर बनाया फर्द मौके पर दरोगाजी ने बोलकर लिखाई थी और लिख पढ़कर हम लोगों को सुनाई और फर्द पर उसका व गवाहान के दस्तखत कराए थे । फर्द की नकल मुलजिम को दी थी व उसके फर्द पर दस्तखत कराए थे । इस साक्षी ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क-2 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है । इस साक्षी ने हंसिया (आला कत्ल) को वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में साबित किया है । घटना के समय मृतका द्वारा पहने हुए दो कपड़े एक कुर्ता वस्तु प्रदर्श-2, एक शमीज बैंगनी कलर की वस्तु प्रदर्श-3, एक सलवार मैरून रंग की वस्तु प्रदर्श-4, एक डिब्बी मिट्टी खून आलूदा वस्तु प्रदर्श-5 एक और डिब्बी जिसमें मिट्टी सादा वस्तु प्रदर्श-6 व एक लिफाफे में थैली में रखी हुई दो हेयर पिन क्रमशः वस्तु प्रदर्श-7 व 8 तथा एक थैली में कलावा का लाल धागा वस्तु प्रदर्श-9 व एक थैली में कागज में लिपटी हुई नाक की लॉग वस्तु प्रदर्श-10 व एक और थैली में कागज में लिपटी हुई कानों की दो बाली निकली जिन्हें वस्तु प्रदर्श-11 के रूप में साबित किया है ।

17. अभियोजन साक्षी संख्या 5 डाक्टर ए. एन. बोहरा वरिष्ठ परामर्शदाता जिला चिकित्सालय बरेली द्वारा मृतका के शव का शव विच्छेदन किया गया था । इस साक्षी ने मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है तथा यह भी कहा कि मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व आई चोटें साधारणतया मृत्यु कारित होने हेतु पर्याप्त थी । मृतका की मृत्यु दिनांक

30.1.2007 को 3.30 बजे सायं होना सम्भव थी । यह भी कहा कि मृतका के शरीर पर आई चोट संख्या 1 लगायत 8 धारदार हथियार मसलन हंसिया से भी आना सम्भव है । मृतका की चोट संख्या 1 गिरने से सख्त चीज से टकराने से भी आ सकती है ।

18. अभियोजन साक्षी संख्या 6 आरक्षी महिपाल वर्मा ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 30.1.2007 को वह थाना भुता में आरक्षी लिपिक के पद पर तैनात था । उस दिन वादी मुकदमा कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू सक्सेना पुत्र स्व. रघुनन्दन प्रसाद सक्सेना निवासी ग्राम गजनेरा थाना भुता बरेली के द्वारा दाखिल तहरीर पर चिक संख्या 14/2007 पर अपराध संख्या 37/2007 धारा 302 भा. द. स. की चिक अभियुक्त गुड्डू गंगवार के खिलाफ की थी जो उसके लेख एवं हस्ताक्षर में है । इस साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया है तथा यह भी कहा है कि उसी दिन दिनांक 30.1.2007 को समय 18.10 पर जी. डी. की रपट नम्बर 40 पर मुकदमा का खुलासा किया । इस साक्षी ने मुकदमा कायमी से सम्बन्धित जी. डी. की प्रति प्रदर्श क-5 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है ।

19. अभियोजन साक्षी संख्या 7 मोहम्मद याकूब खां, उप-निरीक्षक ने अजय कुमार यादव, थानाध्यक्ष के निर्देशन में मृतका कुमारी सोनी के शव का पंचायतनामा तैयार किया था तथा शव को सर्व मोहर हालत में पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया था । इस साक्षी ने पंचायतनामा तथा उससे सम्बन्धित संलग्नक प्रपत्र चालान लाश, फोटो नाश, पत्र प्रतिसार निरीक्षक, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी तथा नमूना मोहर प्रदर्श क-6 लगायत प्रदर्श क-11 के रूप में साबित किया है । इस साक्षी ने मौके पर पड़ी मृतका की चप्पल को कब्जा पुलिस में लेकर मृतका की मां के सुपुर्दगी में देकर उसकी फर्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क-12 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है ।

20. अभियोजन साक्षी संख्या 8 कन्हैया लाल, उप-निरीक्षक ने अपने बयान में यह बताया है कि वह दिनांक 30.1.2007 को थाना भुता जिला बरेली में उप-निरीक्षक के पद पर तैनात था और उसी दिन थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार यादव अपने हमराहियान के साथ ग्राम गजनेरा गए थे और दिनांक 31.1.2007 को दोपहर में तलवीदा मिला ग्राम गजनेरा और वे लोग वहां से मुलजिम की तलाश में मामूर हो गए तभी ग्राम मिलक गौटिया में

जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम गजनेरा का गुड्डू जिसे वे लोग तलाश कर रहे हैं नहर की पटरी-पटरी वीसलपुर रोड की तरफ गया है । इस सूचना पर विश्वास करके वे लोग वीसलपुर बरेली रोड पर पहुंचे तो पुलिस जीप को देखकर सड़क किनारे खड़ा एक व्यक्ति सकपका कर दक्षिण की ओर भागना चाहा तो उसे तुरन्त घेरकर समय 16.00 बजे सड़क के दक्षिणी किनारे पर पकड़ लिया । पूछने पर उसने अपना नाम गुड्डू **उर्फ** जितेन्द्र बताया जो हाजिर अदालत है । चूंकि यह अपराध संख्या 37/2007 धारा 302/376/511 भा. द. स. में नामजद एवं वांछित था इसलिए उसको उसका अपराध बताकर हिरासत में लिया । पूछताछ पर उसने बताया कि उसने अपने गांव की कुमारी सोनी की हत्या की है और हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल हंसिया हत्या करने के बाद अपने खेत में कुएं के पास झाड़ी में छिपा दिया और चलकर बरामद करा सकता है । गुड्डू **उर्फ** जितेन्द्र को व उम्मीद बरामदगी आला कत्ल लेकर जीप से गजनेरा आए और जनता के गवाह राम गोपाल सक्सेना व राजीव बाबू को साथ लेकर मकसद बताया और चलकर राम पाल गंगवार के खेत के पास पहुंचे वहीं मुलजिम गुड्डू ने जीप को रुकवाया और उतर पड़ा और आगे-आगे चकरोड से चलकर पश्चिम को अपने खेत के उत्तरी पश्चिमी कोने से होता हुआ अपने खेत के मध्य में बने कुएं के पास जहां नीम का पेड़ और झाड़ी वगैरह थी । झाड़ी के पास पहुंचकर बताया कि इसी झाड़ी में उसने हंसिया को हत्या कर भागते समय छिपा दिया था तत्पश्चात् उसने स्वयं अपने हाथ से झाड़ी के अन्दर से एक हंसिया निकालकर थानाध्यक्ष को देते हुए गवाहान के समक्ष यह बताया कि यह वही हंसिया है जिससे चोट पहुंचाकर दिनांक 30.1.2007 को अपने गांव की लड़की कुमारी सोनी की हत्या की थी । हंसिया समय 17.00 बजे वजह सबूत पुलिस ने कब्जे में लेकर देखा तो उसमें खून के दाग धब्बे लगे थे । हंसिया को मौके पर कपड़े में सीलकर नमूना मोहर बनाया और मौके पर ही थानाध्यक्ष के बोलने पर फर्द तैयार की जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है । जिसको पढ़कर व सुनकर थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मियों ने व जनता के गवाहान अपने-अपने हस्ताक्षर किए । फर्द की एक नकल मुलजिम को दी उसने भी अपने हस्ताक्षर किए । इस साक्षी ने फर्द प्रदर्श क-2 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त के निशानदेही पर बरामद हंसिया को वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में साबित किया है ।

21. अभियोजन साक्षी संख्या 9 आरक्षी रजनेश पाल सिंह ने अपने

बयान में यह बताया है कि दिनांक 14.2.2007 को वह थाना भुता में आरक्षी के पद पर तैनात था और उसी दिन थाना मालखाना से एक पुलिन्दा सील बंद जिसमें एक डिब्बा सादा मिट्टी, एक डिब्बा खून आलूदा मिट्टी व एक पुलिन्दा सील पर्चाजात मृतका कुमारी सोनी, एक पुलिन्दा सील हंसिया आला कत्ल मय नमूना मोहर थाना मालखाना से प्राप्त कर दिनांक 15.2.2007 को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा ले गया था और मुकदमाती माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में दिनांक 16.2.2007 को सक्षम अधिकारी को प्राप्त कराकर न्यायालय के आदेश के डौकेट पर प्राप्ति ले ली थी ।

22. अभियोजन साक्षी संख्या 10 अजय कुमार यादव, थानाध्यक्ष इस मुकदमे के विवेचनाधिकारी हैं। उन्होंने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 30.1.2007 को वह थाना भुता में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था और उसी दिन इस मुकदमे की विवेचना उसने प्रारम्भ की केस डायरी में तहरीर रपट नकल रपट करने के उपरान्त एफ. आई. आर. लेखक महिपाल वर्मा, वादी कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू के बयान लिए तथा 31.1.2007 को गवाहान श्रीमती रामश्री व नितिन के निशान देही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया । नक्शा नजरी बनाया । इस साक्षी ने घटनास्थल के नक्शा नजरी को प्रदर्श क-13 के रूप में साबित किया है । यह भी बताया है कि उसके बाद पंचायतनामा व केस डायरी की नकल की तथा पंचायतनामा व फर्द के गवाह रोहित सक्सेना, रामाशंकर गंगवार, रवीन्द्र प्रकाश सक्सेना, राकेश कुमार मिश्रा, मोहित कुमार, संजू भटनागर व श्रीमती रामश्री का बयान लिया तथा दिनांक 31.1.2007 को अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र ने अपने खेत से समय 17.00 बजे हंसिया (आला कत्ल) बरामद कराया । कब्जे में लेकर गवाहान के समक्ष मौके पर ही एस. आई. कन्हैया लाल से फर्द तैयार कराई । इस साक्षी ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क-2 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है तथा यह भी कहा है कि उसने मुलजिम व माल बरामद थाने में दाखिल किया । आला कत्ल बरामदगी घटनास्थल का निरीक्षण किया नक्शा नजरी बनाया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में हैं । इस साक्षी ने बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-14 को साबित किया है तथा यह भी कहा है कि बरामदगी के गवाह राम गोपाल सक्सेना, राजीव सक्सेना व मुलजिम गुड्डू उर्फ जितेन्द्र के बयान लिए तथा दिनांक 4.2.2007 को उप-निरीक्षक याकूब खां, उप-निरीक्षक कन्हैया लाल, आरक्षी टीकाराम के बयान लिए तथा 9.2.2007 को

गवाह राम चन्द्र, रामेश्वर दयाल, हरद्वारी लाल, गया प्रसाद, कु. उर्मिला देवी, कु. सरस्वती, संतोष कुमारी, के बयान लिए तथा दिनांक 13.2.2007 को श्रीमती किशोरी देवी, नितिन व कुमारी ईलू व श्रीमती दुष्यन्ती के बयान लिए और 17.2.2007 को आरक्षी रजनेश पाल का बयान लिया और विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 17.2.2007 को अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । इस साक्षी ने आरोप पत्र प्रदर्श क-16 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है तथा वस्तु प्रदर्श-1 हंसिया को अपीलार्थी/ अभियुक्त के निशानदेही पर बरामद होने की पुष्टि की है । इस साक्षी ने घटनास्थल से सादा मिट्टी, खून आलूदा मिट्टी की फर्द प्रदर्श क-15 को साबित किया है ।

23. अपीलार्थी/अभियुक्त का बयान धारा 313 द. प्र. स. के अन्तर्गत अंकित किया गया । जिसमें उसने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए झूठा फंसाया जाना बताया है तथा यह भी कहा है कि उसने कोई घटना नहीं की है। उसे वादी ने अपने परिवार वालों की मदद से झूठी रिपोर्ट लिखवाकर बंद करवा दिया है। उसने कोई हंसिया बरामद नहीं कराई है । पुलिस ने उसके विरुद्ध फर्जी कार्यवाही कर झूठा साक्ष्य गढ़ा है ।

24. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी सफाई में बचाव साक्षी संख्या 1 राम गुलाम तथा बचाव साक्षी संख्या 2 रामेश्वर दयाल को परीक्षित कराया गया है ।

25. विद्वान् अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा उभय पक्ष को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार को धारा 376, 302 भा. द. स. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए धारा 376 भा. द. स. के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 15,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में वह तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा एवं धारा 302 भा. द. स. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह अपील योजित की है ।

26. हमने अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतीश त्रिवेदी तथा उनके सहायक के रूप में श्री शेषिद्र त्रिवेदी व राज्य की ओर से विद्वान् शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह तथा उनके सहायक के रूप

में विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आनन्द तिवारी व कुमारी मीना को सुना । पत्रावली तथा प्रश्नगत निर्णय व आदेश का भली-भांति अवलोकन किया तथा पक्षकारों की ओर से दाखिल लिखित बहस का भी भली-भांति अवलोकन किया ।

27. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है । पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से श्रृंखलाबद्ध तरीके से यह साबित नहीं है कि कथित घटना अपीलार्थी/अभियुक्त ने कारित की हो । यह भी तर्क रखा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या करने का कोई उल्लेख नहीं है तथा इस तरह का भी कोई उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतका के साथ बलात्कार किया हो या बलात्कार करने का प्रयास किया हो । प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी हथियार का भी उल्लेख नहीं है । वादी ने सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचने का उल्लेख किया है लेकिन वादी द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में बलात्कार का प्रयास करने अथवा बलात्कार के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है जब वादी ने मृतका की सलवार अलग पड़ी हुई देख लिया था तो निश्चित रूप से वह मृतका के साथ बलात्कार करने अथवा बलात्कार करने के प्रयास का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में कर सकता था लेकिन इस तरह का भी कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं पाया जाता है । यह भी तर्क रखा गया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी टाइम की गई है । इस तरह घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के ही दिन दिनांक 30.1.2007 को समय 6.10 बजे थाने पर अंकित करना बताया जाता है लेकिन अभियोजन साक्षी संख्या 1 वादी कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि वह गन्ने के खेत से थाने के लिए 6.30 बजे के बाद चला था । उसके खेत पर चलने से पहले पुलिस वाले खेत पर आ गए थे । पुलिस वाले जीप से आए थे । उपरोक्त से भी यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन के अनुसार, समय 6.10 बजे शाम घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर अंकित नहीं कराई गई थी और इससे यही जाहिर होता है कि देर रात्रि तक अपराधी के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी थी ।

28. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि

अपीलार्थी/अभियुक्त का घर वादी के घर से 70-75 कदम की दूरी पर था लेकिन घटना के बाद वादी व गांव का कोई व्यक्ति पूछताछ करने अभियुक्त के घर नहीं गया। पंचायतनामा में मृतका के साथ बलात्कार होने या बलात्कार के प्रयास के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त के नाम का भी उल्लेख नहीं है। यह भी तर्क रखा गया कि विवेचनाधिकारी द्वारा जो घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया है वह विश्वसनीय नहीं है। नक्शा नजरी में गवाहान के खड़े होने के स्थान को नहीं दर्शाया गया है तथा इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि किस स्थान से गवाहान ने अपीलार्थी/अभियुक्त को अंतिम बार देखा। विवेचनाधिकारी ने नक्शा नजरी में घटना के पूर्व अपीलार्थी/अभियुक्त को सी. स्थान पर बैठने का उल्लेख किया है और यह भी उल्लेख किया है कि जब मृतका सी. स्थान के पास पहुंची तभी अभियुक्त ने मृतका का हाथ पकड़ कर रोका जिससे उसकी गठरी बी. स्थान पर गिर पड़ी तथा बी. स्थान से अभियुक्त, मृतका को गेहूं व गन्ने के मध्य वाली मेड़ पर रास्ते के दक्षिण ओर खींचता हुआ ले गया तथा गन्ने के दक्षिण-पश्चिम कोने से मुड़कर पूरब के. स्थान पर गन्ने के खेत में ले जाकर ए. स्थान पर ले गया और ए. स्थान पर ही अभियुक्त द्वारा मृतका से बलात्कार करने का प्रयास किया गया और असफल रहने की दशा में ए. स्थान पर मृतका की हत्या कर लाश छोड़ दिया और पश्चिम की ओर अपने कुएं की तरफ होते हुए भाग गया लेकिन अभियोजन साक्ष्य में इस तरह का कोई तथ्य नहीं आया है कि गवाहान ने अभियुक्त को घटना के पहले सी. स्थान पर बैठे हुए देखा हो और उन्होंने सी. स्थान से मृतका को खींचकर गन्ने के खेत में ले जाते हुए देखा हो बल्कि गवाहान ने अपीलार्थी/अभियुक्त को गन्ने के खेत से निकलकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है। ऐसी दशा में विवेचनाधिकारी ने जो घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया है वह विश्वसनीय नहीं है।

29. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर यह भी तर्क रखा गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त से जो हंसिया (आला कत्ल) की बरामदगी दिखाई गई है वह गलत एवं फर्जी है तथा अभियुक्त ने किसी भी प्रकार की कोई हंसिया (आला कत्ल) बरामद नहीं कराया है। बरामदगी के पूर्व अपीलार्थी/अभियुक्त का कोई कनफेंशनल स्टेटमेंट व डिस्कोलोजर स्टेटमेंट अंकित नहीं किया गया है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क-2 बरामदगी के बाद तैयार करना बताया गया है। ऐसी दशा में कथित बरामदगी विश्वसनीय नहीं रह जाती है। अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तर्क

के समर्थन में **निरंजन पांजा** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**¹ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत किया है तथा यह भी तर्क रखा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी व कथित बरामदगी के संबंध में कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है । बरामदगी के जो दो साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या 4 राम गोपाल सक्सेना तथा राजीव बाबू सक्सेना बताए जाते हैं उनमें से अभियोजन साक्षी संख्या 4 राम गोपाल सक्सेना वादी का साला है और राजीव बाबू सक्सेना वादी के सादू का लड़का है । राम गोपाल सक्सेना बरेली का तथा राजीव बाबू सक्सेना शाहजहांपुर के रहने वाले हैं जिनका निवास ग्राम गजनेरा से 15 तथा 25-30 किमी. की दूरी पर है इसलिए कथित बरामदगी के समय उनका मौके पर रहना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है जिसके कारण बरामदगी की कहानी बनावटी एवं फर्जी प्रतीत होती है ।

30. पोस्टमार्टम के समय मृतका के शरीर पर कटा हुआ घाव तथा घिसने के निशान पाए गए हैं । कथित घटना के समय मृतका को हंसिया से चोट पहुंचाने की बात कही गई है लेकिन चोट की प्रकृति को देखते हुए कथित चोट हंसिया से पहुंचाया जाना साबित नहीं होता है । हंसिया घुमावदार होती है और उससे प्रहार करने पर सर्वप्रथम भोंका हुआ घाव एवं उसके बाद कटा हुआ घाव पाए जाने की सम्भावना रहती है लेकिन मृतका के चोटों में इस तरह के लक्षण नहीं पाए जाते हैं । ऐसी दशा में घटना के समय मृतका की हत्या में हंसिया का प्रयोग किया जाना संदेह से परे सिद्ध नहीं है । यह भी तर्क रखा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 कुमारी ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री का कथन विश्वसनीय नहीं है । उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी बताया है कि मृतका कुमारी सोनी उनसे आगे चल रही थी और मोड़ के बाद जब वह दिखाई नहीं दी तब वह तेज-तेज चलने लगी । राम गुलाम के गन्ने के खेत के पास पहुंचने पर कुमारी सोनी के चीखने की आवाज सुनने का उल्लेख किया है । इतने कम समय में अपीलार्थी/अभियुक्त चकरोड से मृतका को पकड़ कर अन्दर खेत में ले जाए और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करे । बलात्कार में असफल होने पर उसकी हत्या कर दे यह स्वाभाविक नहीं लगता है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू व अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री की साक्ष्य घटना के संबंध में विश्वसनीय नहीं है और उनकी साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित करना संदेह से परे सिद्ध नहीं है ।

¹ 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3289.

31. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू का बयान विवेचनाधिकारी ने काफी विलम्ब से अर्थात् 12 दिन बाद अंकित किया है। उपरोक्त अभियोजन साक्षी संख्या 2 तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 के बयानों में विरोधाभास भी है तथा उनकी साक्ष्य इस प्रकृति की नहीं है कि उन पर सहजता से विश्वास किया जा सके। यह भी तर्क रखा गया कि वादी तथा पुलिस के मौके पर पहुंचना तथा शव के पास उपस्थिति के संबंध में अभियोजन साक्षी संख्या 1, 2 तथा 3 के बयानों में आपस में विरोधाभास है। इस तरह गवाहान के घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू ने सूचना मिलने पर लक्ष्मी राइस मिल पड़ौली से घर आने तथा घर से घटनास्थल पर पहुंचने का उल्लेख किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि उसका लड़का वादी घटनास्थल पर 2-3 मिनट बाद आ गया था। ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 1 का कथन विश्वसनीय नहीं रह जाता है। यह भी तर्क रखा गया कि घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी की फर्द दिनांक 31.7.2007 को तैयार की गई है। इससे यही प्रकट होता है कि मृतका का शव दिनांक 31.1.2007 तक मौके पर पड़ा रहा है जिससे घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी टाइम करने की पुष्टि होती है। यह भी तर्क रखा कि **कैलाश गौर** बनाम **असम राज्य**¹ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दोष पूर्ण विवेचना का लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा अभियोजन को नहीं। यह भी तर्क रखा गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका के सलवार पर शुक्राणु पाए जाने का उल्लेख किया गया है और मृतका के द्वारा सलवार में ही मल त्यागने की बात कही गई है। ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका का सलवार उतारना या उस पर अपीलार्थी/अभियुक्त का शुक्राणु पाया जाना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और उपरोक्त परिस्थितियों में बलात्कार की कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियोजन पक्ष अपने कथन को सिद्ध करने में असफल रहा है तथा प्रस्तुत मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य से यह शृंखलाबद्ध तरीके से साबित नहीं है कि कथित अपराध अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा किया गया हो। ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त दोष मुक्त किए जाने योग्य है तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश निरस्त होने योग्य है।

¹ ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 786.

32. इसके विपरीत विद्वान् शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह द्वारा यह तर्क रखा गया कि प्रस्तुत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तथा प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से शृंखलाबद्ध तरीके से यह भली-भांति साबित है कि कथित अपराध अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री ने अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार को मृतका के शव के पास से खून से सना हुआ हंसिया लेकर भागते हुए देखा गया है तथा उक्त हंसिया अपीलार्थी/अभियुक्त के निशानदेही पर बरामद भी की गई है जिस पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, मानव रक्त पाया गया है । इस हंसिया पर मानव रक्त कहां से आया इसका कोई स्पष्टीकरण अभियुक्त की ओर से नहीं दिया गया । यह भी तर्क रखा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री के बयानों में इस तरह का कोई विरोधाभास नहीं पाया जाता है जिससे उनके साक्ष्य को गलत या अविश्वसनीय माना जा सके । यह एक गांव देहात का मामला है यदि गवाहान के बयानों में मामूली विरोधाभास आया है तो मात्र उक्त आधार पर गवाहान के सम्पूर्ण साक्ष्य को गलत या अविश्वसनीय मान लेना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । साक्ष्य में यह आया है कि मृतका कुमारी सोनी पुआल की गठरी लेकर खेत से पहले चली आई थी और उसके पीछे अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री व अन्य बच्चे भी पुआल की गठरी लेकर पीछे-पीछे आ रहे थे । यह घटना वाला खेत वहीं रास्ते के बीच में पड़ता है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 2 तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 द्वारा जो घटना देखने की बात कही गई है और मौके पर उपस्थित होने की बात कही गई है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अपीलार्थी/अभियुक्त को खून से सना हुआ हंसिया लेकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है और मृतका के शरीर पर पोस्टमार्टम के समय कटे हुए घाव पाए गए हैं जिन्हें डाक्टर ने हंसिया से आना सम्भव कहा है ।

33. उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है । यह भी तर्क रखा गया कि यदि विवेचनाधिकारी द्वारा बरामदगी के पूर्व अपीलार्थी/अभियुक्त का कोई पृथक् से डिस्कोलोजर स्टेटमेंट तैयार नहीं किया गया या उसका कंफेशनल स्टेटमेंट किसी

निष्पक्ष साक्षी के समक्ष अंकित नहीं किया गया है तो मात्र उक्त आधार पर बरामदगी के संबंध में संदेह का कोई आधार नहीं पाया जाता है । पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से अपीलार्थी/अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हंसिया (आला कत्ल) की बरामदगी सिद्ध है । विद्वान् शासकीय अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टांत **सुरेश चन्द्र बाहरी बनाम बिहार राज्य¹, राज्य एन. सी. टी. बनाम सुनील²** प्रस्तुत किया है । यह भी तर्क रखा कि बरामद हंसिया (आला कत्ल) पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मानव रक्त पाया गया है तथा मृतका की सलवार पर भी शुक्राणु पाए गए हैं यदि रक्त के वर्ग का निर्धारण नहीं हो सका है तो मात्र उक्त आधार पर कथित बरामदगी अविश्वसनीय नहीं है । विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टांत **जगरूप सिंह बनाम पंजाब राज्य³, महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश⁴** तथा **सुनील क्लीफोर्ड डिनायल बनाम पंजाब राज्य⁵** उद्धरित किया गया है । यह भी तर्क रखा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई विलम्ब नहीं है । प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के अनुसार, समय पर दर्ज कराया जाना साबित है तथा प्रस्तुत मामले में समस्त परिस्थितियां शृंखलाबद्ध तरीके से साबित हैं । कथित अपराध अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है । अपने तर्क के समर्थन में **विलास पंडुरांग पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य⁶** भी प्रस्तुत किया है । अंत में यह तर्क रखा गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपनी हवस पूरी करने के लिए एक नाबालिग लड़की को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया है और निर्ममता पूर्वक हंसिया से घातक चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी है । यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में आता है । ऐसी दशा में विद्वान् अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं है । विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में **अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य⁷, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार⁸, रमेश भाई चन्दू भाई राथौड़ बनाम**

¹ (1995) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 60.

² (2001) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 248.

³ (2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1136.

⁴ (2000) 40 ए. सी. सी. 224.

⁵ (2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 438.

⁶ (2004) 6 एस. सी. सी. 158.

⁷ (2012) 77 ए. सी. सी. 201.

⁸ (2012) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 970.

गुजरात राज्य¹ तथा राजेन्द्र प्रहालत्रों वाशनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य² उद्धृत किया है ।

34. अब विचारणीय पश्चिम यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने कथानक को संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से शृंखलाबद्ध तरीके से यह साबित है कि कथित घटना के समय अपीलार्थी गुड्डू उर्फ जितेन्द्र ने मृतका कुमारी सोनी के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के पश्चात् उसकी हत्या कर दी । यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है । घटना के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या 1 कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू (वादी मुकदमा) तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू व अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री को परीक्षित कराया गया है ।

35. अभियोजन साक्षी संख्या 1 कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 30.1.2007 की घटना है । घटना वाले दिन में 2.00 बजे करीब उसकी मां रामश्री उसका लड़का नितिन, उसकी लड़की सोनी, ईलू व कंचन खेत पर पुआल लेने गई थी । उसकी मां ने पुआल का गट्टा बांध कर सोनी को पहले घर पर भेज दिया बाद में उसकी मां रामश्री, नितिन, ईलू व कंचन अपने खेत से पताई लेकर घर वापस आ रहे थे तभी रास्ते में राम गुलाम के गन्ने के खेत के पास पहुंचे तभी उन्हें चीखने-चिल्लाने की आवाज गन्ने के खेत से सुनाई दी एवं गन्ने के खेत के कोने पर पुआल की गड्डी पड़ी देखी । चीखने- चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां रामश्री, उसके बच्चे आवाज की तरफ गए तो देखा कि हाजिर अदालत मुलजिम गुड्डू गंगवार हाथ में खून का सना हंसिया लेकर भाग रहा था । हंसिया लेकर लाश के पास से भाग रहा था और सोनी खून से लथपथ उसी गन्ने के खेत में पड़ी थी । सलवार निकली पड़ी थी । घटना दिन में 3.30 बजे के करीब हुई थी । घटना के समय वह मील पर काम कर रहा था । इस घटना की सूचना उसकी मां व बच्चों ने घर आकर उसकी पत्नी को दी तब उन्होंने उसके लड़के नितिन से उसे घटना की सूचना दी जिस पर वह आया तब उसे उसकी मां बच्चों व पत्नी ने घटना के बारे में बताया इस पर वह मौके पर पहुंचा और वहां सोनी की लाश खून से लथपथ पड़ी देखी तब उसने घटना की तहरीर संजू भटनागर से बोलकर लिखाई जो उसने बोला वह उन्होंने लिखा था

¹ (2011) 2 एस. सी. सी. 764.

² (2012) 4 एस. सी. सी. 37.

लिखकर पढ़कर सुनाने पर उसने उस पर अपना दस्तखत किया था । इस साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क-1 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है तथा यह कहा है कि यह तहरीर थाने ले जाकर देकर घटना की सूचना दी और रिपोर्ट लिखाई । दरोगाजी ने उसका बयान नहीं लिया था पूछताछ की थी । मुलजिम ने उसकी लड़की के साथ बलात्कार करने के प्रयास में असफल रहने पर उसकी लड़की की हत्या कर दी ।

36. अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू ने अपने बयान में यह बताया है कि घटना दिनांक 30 जनवरी, 2007 की है । उस दिन वह, उसकी दादी रामश्री, भाई नितिन, बहन सोनी व कंचन के साथ अपने खेत पर पुआल व पताई लेने गई थी । उसकी दादी रामश्री व उसने पुआल का गट्टा बांधकर उठवाकर घर भेज दिया था । थोड़ी ही देर बाद वह व उसकी दादी, भाई नितिन व बहन कंचन पताई लेकर घर आ रहे थे जब वे लोग राम गुलाम के गन्ने के खेत के पास आए तो गन्ने के खेत में से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और चकरोड़ पर ईख के खेत के कोने पर पुआल का गट्टा पड़ा था इस पर वह व उसकी दादी, भाई, बहन भागकर गन्ने के खेत में जिधर से आवाज आ रही थी गए तो वहां देखा कि हाजिर अदालत मुलजिम गुड्डू उर्फ जितेन्द्र हाथ में खून का सना हंसिया लेकर लाश के पास से भाग रहा था और सोनी खून से लथपथ वहां मरी पड़ी थी । उसकी आंते बाहर निकली हुई थीं और सलवार अलग निकली हुई थी । इसके बाद वह, उसकी दादी, भाई, बहन घर पर आए और अपनी मम्मी को घटना के बारे में जानकारी दी । इस पर उसकी मम्मी ने उसके भाई नितिन को उसके पापा को बुलाने पड़ौली मील भेजा जहां से पापा के आने पर उन्हें सारी बात बताई । मुलजिम की नियत खराब हो गई थी और उसकी बहन सोनी के साथ बुरा काम न कर पाने के कारण उसकी पेट फाड़कर हत्या कर दी । घटना दिन में 3.30 बजे की है । दिन की रोशनी में उसने मुलजिम को अच्छी तरह देखा व पहचाना था मुलजिम उसके ही गांव का है ।

37. अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री वादी की मां है तथा मृतका कुमारी सोनी की दादी है । इस साक्षी ने अपने बयान में यह कहा है कि दिनांक 30 जनवरी, 2007 की घटना है । घटना वाले दिन वह उसकी पोती सोनी, ईलू, कंचन व पोता नितिन दिन में लगभग 2.00 बजे खेत में पुआल लेने गई थी । उसने सोनी को पुआल का गट्टर बांधकर देकर घर भेज दिया और थोड़ी देर बाद वह ईलू, कंचन व नितिन के साथ पताई के गट्टे लेकर घर वापस आ रही थी तभी रास्ते में राम गुलाम के

गन्ने के खेत से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और गन्ने के खेत के कोने पर सोनी के पुआल का गट्टर पड़ा था फिर चीखने-चिल्लाने की आवाज की तरफ वह व बाकी बच्चे उधर गए तब उसने अपने गांव के गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को लाश के पास से हाथ में हंसिया लिए खेत से निकलकर भागते देखा और अंदर जाकर गन्ने के खेत में देखा कि सोनी खून से लथपथ खेत में पड़ी थी और गला कटा हुआ था । यह घटना दिन में 3.30 बजे करीब की है । दिन की रोशनी में उसने हाजिर अदालत मुलजिम को घटना करते भागते देखा । फिर इसकी सूचना उसने अपने पोते, पोती, कंचन व नितिन को घर भेजकर घटना की खबर की जिस पर उसके लड़के की बहू ने पड़ौरी मील पर उसके पोते नितिन को भेजकर उसके लड़के को खबर कराई जिस पर उसका लड़का कृष्ण कान्त घर पर आकर मौके पर पहुंचा था जहां उसने उसे सभी बात बताई । उसकी पोती सोनी की हत्या हाजिर अदालत मुलजिम गुड्डू उर्फ जितेन्द्र ने इसलिए की क्योंकि वह बुरा काम नहीं कर पाया । इसलिए उसकी पोती की हत्या कर दी ।

38. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त साक्षीगण एक ही घर एवं परिवार के सदस्य हैं तथा हितबद्ध साक्षी हैं । घटना के संबंध में किसी निष्पक्ष साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है । ऐसी दशा में उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य संदेह से परे विश्वसनीय नहीं है । हमारे विचार से मात्र संबंधों के आधार पर किसी भी साक्षी की साक्ष्य को प्रथमदृष्ट्या अविश्वसनीय मान लेना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री घटना के दिन मृतका कुमारी सोनी के साथ खेत पर पुआल व पताई लेने गई थी । अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री (जोकि मृतका की दादी है) ने सबसे पहले पुआल का गट्टर बांधकर सोनी को घर भेज दिया था । उसके थोड़ी देर बाद वह तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू व अन्य बच्चे कंचन व नितिन पताई लेकर घर आ रहे थे जब वे राम गुलाम के गन्ने के खेत के पास पहुंचे तो उन्हें चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और चकरोड पर ईख के खेत के कोने पर सोनी के पुआल का गट्टा पड़ा था जिधर से चीखने-चिल्लाने की आवाज आ रही थी उस तरफ जाकर देखा तो अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र सोनी के लाश के पास से खून से सना हंसिया लेकर भाग रहा था । चूंकि उस समय वहां पर गांव का कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था मात्र अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू

अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री व बच्चे नितिन तथा कंचन ही मौजूद थे और उन्होंने चीख पुकार की आवाज पर गन्ने के खेत में जाकर देखा तो वहां पर सोनी की लाश खून से लथपथ पड़ी थी तथा अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र खून से सना हंसिया लेकर भाग रहा था । ऐसी दशा में यदि इस घटना के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तो मात्र उक्त आधार पर अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । एक परिस्थिति यह भी है कि उपरोक्त दानों साक्षियों ने मृतका कुमारी सोनी की लाश के पास से अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को हंसिया लेकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि जब वह, उसकी दादी, भाई, बहन भागकर गन्ने के खेत में जिधर से आवाज आ रही थी गए तो वहां देखा कि हाजिर अदालत मुलजिम गुड्डू उर्फ जितेन्द्र हाथ में खून से सना हंसिया लेकर लाश के पास से भाग रहा था और सोनी खून से लथपथ वहां मरी हुई पड़ी थी । उसकी आंते बाहर निकली हुई थीं और सलवार अलग निकली हुई थी । उल्लेखनीय है कि मृतका कुमारी सोनी का पोस्टमार्टम दिनांक 31.1.2007 को समय 3.30 पी. एम. पर डाक्टर ए. एन. बोहरा द्वारा किया गया था । डाक्टर ने बरवक्त मुआइना पोस्टमार्टम मृतका के शरीर पर आठ कटे हुए घाव तथा एक रगड़ का निशान पाया है । डाक्टर ने अपने बयान में यह भी बताया है कि चोट संख्या 1 लगायत 8 धारदार हथियार मसलन हंसिया से भी आना सम्भव है । मृतका की चोट संख्या 1 गिरने से सख्त चीज से टकराने से भी आ सकती है । ऐसी दशा में स्पष्ट है कि मृतका की चोटों को डाक्टर ने हंसिया से भी आना सम्भव कहा है । उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है । ऐसी दशा में उपरोक्त साक्षियों का कथन चिकित्सीय साक्ष्य से भी सम्पुष्ट होता है । ऐसी दशा में भी कथित घटना के समय उपरोक्त साक्षियों की मौके पर उपस्थिति के संबंध में संदेह का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

39. यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि यह एक गांव की घटना है छुट्टियों के दिन बच्चे अक्सर अपने घर के बड़े-बूढ़ों के साथ खेतों पर काम करने चले जाते हैं । अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री के साक्ष्य में यह आया है कि घटना के दिन चेहल्लुम का अवकाश था । ऐसी

दशा में उपरोक्त साक्षियों ने जो घटना के दिन खेत पर पताई व पुआल लेने जाने की बात कही है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त दोनों अभियोजन साक्षियों (अभियोजन साक्षी संख्या 2 एवं अभियोजन साक्षी संख्या 3) ने अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को कथित घटना के समय मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है तथा मृतका के शव पर कटे हुए घाव पाए गए हैं जिन्हें डाक्टर ने हंसिया से भी आना सम्भव कहा है । ऐसी दशा में कथित घटना के समय उपरोक्त साक्षीगण की उपस्थिति भी साबित है ।

40. **पंजाब राज्य बनाम जुगराज सिंह और अन्य¹** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी साक्षी की साक्ष्य को मात्र संबंधी होने के आधार पर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है । ऐसे साक्षियों का साक्ष्य जिनकी उपस्थिति घटना के समय स्वाभाविक है तथा उनका साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्ट है, को स्वीकार किया जा सकता है ।

41. एक अन्य प्रकरण **अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य²** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि “कोई भी साक्षी केवल संबंधी होने मात्र से हितबद्ध साक्षी नहीं हो जाता । जब तक साक्षी का झूठा फंसाने में हित सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक केवल संबंधी साक्षी को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता ।”

42. प्रस्तुत मामले में कथित घटना के दिन, दिन में 2.00 बजे मृतका कुमारी सोनी अपनी दादी रामश्री, बहन ईलू, कंचन व भाई नितिन के साथ पुआल लेने खेत पर गई थी । अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री ने सबसे पहले पुआल का गट्टर बांधकर सोनी को घर वापस भेज दिया था । उसके बाद अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू, कंचन, नितिन व स्वयं पताई का गट्टर लेकर घर वापस आ रही थी तो उन्हें रास्ते में राम गुलाम के गन्ने के खेत से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी वहीं रास्ते में चकरोड़ पर मृतका की पुआल का गट्टा भी पड़ा हुआ था । चीखने चिल्लाने की आवाज की ओर जाने पर उपरोक्त साक्षी ने यह देखा कि अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र हाथ में हंसिया लेकर मृतका के

¹ (2002) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 630.

² 2012 (1) जे. सी. आर. सी. 703.

शव के पास से भाग रहा था । अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र हाथ में खून से सना हंसिया लेकर लाश के पास से भाग रहा था । उसने लाश के पास जाकर देखा तो वहां पर सोनी मरी हुई पड़ी थी । मृतका कुमार सोनी के शरीर पर पोस्टमार्टम के समय कटे हुए घाव पाए गए हैं जिन्हें डाक्टर ने हंसिया से आना सम्भव कहा है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया जाता है तथा प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है ।

43. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से एक तर्क यह भी रखा गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि जब वे खेत से गट्ठर लेकर चली तो उन्हें सोनी सड़क पर चलती दिखाई दे रही थी । इसके बाद फिर मोड़ आ गया वह नहीं दिखी । इन साक्षियों ने जिस स्थान से सोनी को जाते हुए देखने का उल्लेख किया है उस स्थान से घटनास्थल वाला खेत इतनी दूरी पर नहीं है कि अपीलार्थी/अभियुक्त कुमारी सोनी को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर ले व बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दे । इतने कम समय में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ बलात्कार करने व उसके बाद उसकी हत्या कर देना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री बच्ची व महिला है । वे अपने खेत से पताई लेकर आ रही थी और उन्होंने सोनी को पहले ही पुआल का गट्ठर लेकर भेज दिया था । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री ने जो राम गुलाम के खेत के पास पहुंचकर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी और आवाज पर खेत के अंदर जो जाने की बात कही है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । चूंकि कुमारी सोनी अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री के पहले खेत से पुआल की गठरी लेकर घर के लिए चल दी थी । उसके बाद अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3

रामश्री व अन्य बच्चे पताई लेकर वापस घर आ रहे थे और यह घटना वाला खेत रास्ते से लगा हुआ है । ऐसी दशा में उनके द्वारा घटना वाले खेत (राम गुलाम के खेत) के पास पहुंचकर मृतका की चीख पुकार सुनना व उसके चीखने चिल्लाने की आवाज पर गन्ने के खेत में जाकर देखना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय हैं । मृतका कुमारी सोनी अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू की बहन थी और अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री की पोती थी इसलिए इन साक्षियों द्वारा कुमारी सोनी की आवाज को पहचान लेना व उसके चीखने चिल्लाने की आवाज पर जिस ओर से गन्ने के खेत में से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी वहां पहुंचना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय है । ऐसी दशा में जो उपरोक्त दोनों साक्षियों के द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को मृतका के लाश के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया गया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया जाता है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र हाथ में खून का सना हंसिया लेकर लाश के पास से भाग रहा था । उक्त हंसिया को अपीलार्थी/अभियुक्त के निशानदेही पर दिनांक 31.1.2007 को पुलिस द्वारा बरामद भी किया गया तथा उक्त हंसिया (आला कत्ल) को रसायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजा गया था । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उक्त हंसिया (आला कत्ल) पर मानव रक्त पाया गया । ऐसी दशा में भी उपरोक्त दोनों साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया जाता है ।

44. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि लाश के पास बैठने के बिन्दु पर अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री के बयानों में विरोधाभास है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू ने अपने बयान में यह बताया है कि घटनास्थल से वह उसकी दादी, भाई, बहन घर पर आए और अपनी मम्मी को घटना के बारे में जानकारी दी जब कि अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री ने मौके पर ही रुके रहने का कथन किया है और अपने पोता, पोती (कंचन व नितिन) को घर भेजकर घटना की खबर देने की बात कही है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर उपरोक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य को पूर्णतः अविश्वसनीय मान लेना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । खासकर उस स्थिति में जब उपरोक्त दोनों साक्षियों की मौके पर

उपस्थिति सिद्ध है । उक्त दोनों साक्षियों की सम्पूर्ण साक्ष्य से यही सिद्ध है कि उनके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखा गया है । हंसिया पर खून लगा था । ऐसी दशा में मात्र उपरोक्त विसंगति के आधार पर अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है । उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है ।

45. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में हंसिया का कोई उल्लेख नहीं है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री द्वारा अपने बयान के अन्तर्गत धारा 161 द. प्र. स. में भी अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथ में हंसिया होने का उल्लेख नहीं किया गया है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और जो उन्होंने अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथ में हंसिया होने की बात कही है वह विचार-विमर्श के बाद कही है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथ में हंसिया होने या उसके द्वारा हंसिया से मृतका की हत्या कारित करना सिद्ध नहीं है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 की साक्ष्य को पूर्णतः अविश्वसनीय मान लेना न्यायोचित नहीं है । उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अपने बयानों में अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त खून से सना हंसिया लेकर मृतका के शव के पास से भाग रहा था और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कथित बरामद हंसिया (आला कत्ल) पर मानव रक्त पाया गया है । ऐसी दशा में साक्षियों ने जो अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के लाश के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है ।

46. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि विवेचनाधिकारी ने अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू का बयान घटना के करीब – 13 दिन बाद दिनांक 13.2.2007 को अंकित किया है । हमारे विचार से यदि विवेचनाधिकारी ने अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू का

बयान विलम्ब से अंकित किया है तो मात्र उक्त आधार पर अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू की साक्ष्य को अविश्वसनीय मान लेने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यही साबित है कि कथित घटना के दिन अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू अपनी दादी रामश्री, मृतका कुमारी सोनी, भाई नितिन, व बहन कंचन के साथ पताई और पुआल लेने खेत पर गई थी । अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री ने भी कथित घटना के दिन अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू को अपने साथ खेत पर पताई व पुआल लेने जाने की बात कही है और लौटते समय राम गुलाम के खेत से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर गन्ने के खेत में जिधर से चीखने-चिल्लाने की आवाज आ रही थी उस तरफ जाने का उल्लेख किया है और अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को मृतका कुमारी सोनी के लाश के पास से हंसिया लेकर खेत से निकलकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है । ऐसी दशा में यही साबित है कि कथित घटना के समय ईलू भी अपनी दादी अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री व भाई नितिन तथा बहन कंचन के साथ मौजूद थी और उसने भी चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर ईख के खेत में जाकर मृतका के शव के पास से अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को खून से सना हंसिया लेकर भागते हुए देखा गया है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया जाता है और उपरोक्त के संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है ।

47. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू का आचरण स्वाभाविक नहीं है क्योंकि उसने मृतका के लाश के पास से कई बार घर जाने व उसके बाद पुनः घर से लाश के पास वापस आने का कथन किया है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर इस साक्षी की साक्ष्य को अविश्वसनीय मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस साक्षी ने अपने बयान में अपनी आयु 15 साल बताई है । उसका बयान दिनांक 11.2.2009 को अंकित किया गया है । यह घटना दिनांक 30.1.12007 की है । इससे यही जाहिर होता है कि घटना के समय इस साक्षी की आयु लगभग 13 वर्ष थी । चूंकि इस साक्षी की बहन की हत्या हुई थी इसलिए लाश के पास से उसका अपने घर जाना और घटना की सूचना देकर पुनः अपनी बहन के लाश के पास पहुंचना स्वाभाविक है यदि वह इस दौरान कई बार अपने घर अपनी

मृतका बहन के लाश के पास से आई गई है तो उससे इस साक्षी की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

48. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी टाइम की गई है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू वादी मुकदमा है उसने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल (गन्ने के खेत) से थाने के लिए 6.30 बजे चला था जब कि इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 6.10 बजे शाम के दर्ज होना बताया गया है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । अभियोजन साक्षी संख्या 6 आरक्षी महिपाल वर्मा द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई थी । इस साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया है तथा यह बताया है कि उसने उसी दिन दिनांक 30.1.2007 को समय 18.10 बजे पर जी. डी. की रपट नम्बर 40 पर मुकदमा का खुलासा किया था । इस साक्षी ने मुकदमा कायमी से सम्बन्धित जी. डी. की प्रति को प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया है । इस साक्षी के प्रतिपृच्छा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट को एंटी टाइम किए जाने की बात स्वीकार किया जा सके बल्कि पत्रावली पर जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उससे यही साबित है कि इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के कथनानुसार दिनांक 30.1.2007 को समय 6.10 बजे शाम थाने पर अंकित करा दी गई थी । ऐसी दशा में उपरोक्त संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है ।

49. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा मृतका की हत्या करने का उल्लेख नहीं है तथा मृतका के साथ बलात्कार करने व बलात्कार के प्रयास के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है । यदि वादी कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू (अभियोजन साक्षी संख्या 1) ने मृतका की सलवार अलग पड़ी हुई देखा था तो वह मृतका के साथ बलात्कार करने व बलात्कार के प्रयास का भी उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में कर सकता था । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि वादी कृष्ण

कान्त उर्फ पप्पू (अभियोजन साक्षी संख्या 1) स्वीकृत रूप से घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । उसने अपनी मां तथा अपने बच्चों के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई है । ऐसी दशा में यदि वादी ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा मृतका की हत्या करने या उसके साथ बलात्कार करने व बलात्कार के प्रयास के बारे में उल्लेख नहीं किया है तो मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री द्वारा कथित घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को मृतका की लाश के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखा गया है । पोस्टमार्टम के समय मृतका के शरीर पर कटे हुए घाव पाए गए हैं और डाक्टर ने मृतका की चोटों को हंसिया से आना सम्भव बताया है । अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित हंसिया (आला कत्ल) बरामद भी कराया गया था जिस पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की रिपोर्ट में मानव रक्त पाया गया है । पंचायतनामा के समय मृतका की सलवार शव पर पड़ी पाई गई है तथा पोस्टमार्टम के समय मृतका की योनि व हाईमन दोनों फटे पाए गए हैं । मृतका की सलवार विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजी गई थी जिस पर शुक्राणु पाए जाने का उल्लेख किया गया है । उपरोक्त समस्त साक्ष्यों से यही सिद्ध है कि कथित घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतका के साथ बलात्कार किया है और अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसकी हत्या कर दी । ऐसी दशा में उक्त संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है ।

50. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त का मकान वादी के मकान के पहले रास्ते में पड़ता है यदि अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतका की हत्या कारित की होती तो वादी तथा उसके परिवार के लोग अपीलार्थी/अभियुक्त के घर पूछताछ करने भी जा सकते थे और जब इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी तो गांव के लोग भी विरोध स्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त के घर जाकर उन्हें क्षति पहुंचा सकते थे । हमारे विचार से अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि घटना के समय साक्षियों ने अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देख लिया था और अपीलार्थी/अभियुक्त को पहचान लिया था ।

अपीलार्थी/अभियुक्त उनके गांव का रहने वाला भी है । ऐसी दशा में जब अभियुक्त की पहचान हो चुकी थी तो यह आवश्यक नहीं था कि वादी या गवाहान अपीलार्थी/अभियुक्त के घर पूछताछ करने जाते या विरोध जताने जाते । घटना के संबंध में वादी द्वारा विधिक कार्यवाही की गई है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । ऐसी दशा में घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है और न ही अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना पाई जाती है ।

51. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का लेखक संजू भटनागर वादी का सगा बहनोई है जो बरेली कचहरी में मुंशी का कार्य करता है उससे विचार-विमर्श करने के बाद गलत तरीके से अपीलार्थी/अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है । वादी के परिवार में चूंकि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और इस घटना में वादी की लड़की की हत्या हो गई थी इसलिए वादी को अपने रिश्तेदार/बहनोई संजू भटनागर को घटना की सूचना देना स्वाभाविक था और यदि इस घटना की तहरीर वादी के बहनोई संजू भटनागर द्वारा लिखी गई है तो मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में सन्देह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । यदि अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा ही फंसाना होता तो वादी अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा मृतका की हत्या करने का भी उल्लेख कर सकता था तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू व अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री भी अपने बयान में अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के साथ बलात्कार करने व बलात्कार के बाद उसकी हत्या करते हुए देखने का उल्लेख कर सकती थी लेकिन गवाहान द्वारा जितनी घटना देखी गई है उसी का वर्णन किया गया है । ऐसी दशा में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में या घटना के संबंध में संदेह का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

52. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से हंसिया (आला कत्ल) की जो बरामदगी दिखाई गई है वह गलत है तथा अभियुक्त ने किसी भी प्रकार की कोई हंसिया (आला कत्ल) बरामद नहीं कराया है । बरामदगी के पूर्व अपीलार्थी/अभियुक्त का कोई कनफेशनल स्टेटमेंट व डिस्कोलोजर स्टेटमेंट अंकित नहीं किया गया है । ऐसी दशा में कथित बरामदगी विश्वसनीय नहीं रह जाती है । अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने तर्क के समर्थन

में निरंजन पांजा प्रति राज्य वेस्ट बंगाल¹ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत की गई है ।

53. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या 4 राम गोपाल (जो जन साक्षी है) तथा अभियोजन साक्षी संख्या 8 कन्हैया लाल, उप-निरीक्षक व अभियोजन साक्षी संख्या 10 अजय कुमार, थानाध्यक्ष/विवेचनाधिकारी को परीक्षित कराया गया है । उपरोक्त साक्षियों ने अपीलार्थी/अभियुक्त के निशानदेही पर दिनांक 31.1.2007 को समय 17.00 बजे उसके खेत के पुराना कुएं के पास झाड़ी में से एक अदद हंसिया (आला कत्ल) बरामद होने की पुष्टि की है । अभियोजन साक्षी संख्या 4 राम गोपाल ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि दिनांक 31.1.2007 को अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को पकड़कर पुलिस ग्राम गजनेरा लाई थी और वहां से उसे व राजीव को पुलिस गिरफ्तार शुदा गुड्डू उर्फ जितेन्द्र के साथ उसके खेत पर लाई जहां गुड्डू उर्फ जितेन्द्र ने अपने खेत में बने पुराना कुएं के पास झाड़ी में से खून से सना हुआ हंसिया निकाल कर दिया और कहा कि यह वही हंसिया है जिससे उसने सोनी की हत्या दिनांक 30.1.2007 को की थी । यह बरामदगी शाम को 5.00 बजे हुई थी ।

54. अभियोजन साक्षी संख्या 8 कन्हैया लाल, उप-निरीक्षक ने भी यह बताया है कि मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके बीसलपुर बरेली रोड पर पहुंचे तो पुलिस की जीप को देखकर सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति सकपका कर दक्षिण की ओर भागना चाहा तो उसे तुरन्त घेरकर समय 16.00 बजे सड़क के दक्षिणी किनारे पर पकड़ लिया पूछने पर उसने अपना नाम गुड्डू उर्फ जितेन्द्र बताया और कहा कि उसने अपने गांव की कुमारी सोनी की हत्या की है और हत्या में प्रयुक्त हंसिया (आला कत्ल) हत्या करने के बाद अपने खेत में कुएं के पास झाड़ी में छिपा दिया है और चलकर बरामद करा सकता है । गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को बउम्मीद बरामदगी आला कत्ल, लेकर जीप से गजनेरा आए और जनता के गवाह राम गोपाल सक्सेना व राजीव बाबू को साथ लेकर मकसद बताया और चलकर राम पाल गंगवार के खेत के पास पहुंचे वहीं मुलजिम गुड्डू ने जीप को रुकवाया और उतर पड़ा और आगे-आगे चकरोड से चलकर पश्चिम को अपने खेत के उत्तरी पश्चिमी कोने से होता हुआ अपने खेत के मध्य में बने कुएं के पास जहां नीम का पेड़ और झाड़ी वगैरह थी झाड़ी

¹ 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3289.

के पास पहुंचकर बताया कि इसी झाड़ी में उसने हंसिया (आला कत्ल) को हत्या कर भागते समय छिपा दिया था तत्पश्चात् उसने स्वयं अपने हाथों से झाड़ी के अंदर से एक हंसिया निकाल कर एस. ओ. साहब को देते हुए गवाहान के समक्ष यह बतलाया कि यह वही हंसिया है जिससे चोट पहुंचाकर दिनांक 30.1.2007 को अपने गांव की लड़की कुमारी सोनी की हत्या की थी। इस साक्षी ने उक्त बरामदगी के संबंध में फर्द प्रदर्श क-2 तैयार किया था तथा बरामद शुदा हंसिया को न्यायालय के समक्ष वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में साबित भी किया है।

55. अभियोजन साक्षी संख्या 10 अजय कुमार, थानाध्यक्ष (विवेचनाधिकारी) भी बरामदगी के साक्षी हैं। इस साक्षी ने अपीलार्थी/अभियुक्त के निशानदेही पर मृतका की हत्या में प्रयुक्त हंसिया (आला कत्ल) की बरामदगी की पुष्टि की है। उपरोक्त साक्षियों के प्रतिपृच्छा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि कथित बरामदगी के संबंध में कोई संदेह व्यक्त किया जा सके बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से यही साबित है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या में प्रयुक्त हंसिया (आला कत्ल) बरामद कराया गया है। निरंजन पांजा प्रति राज्य वेस्ट बंगाल के मामले में आला कत्ल शूली व कटारी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उक्त आला कत्ल शूली व कटारी पर मानव रक्त पाए जाने का भी उल्लेख नहीं था। मात्र रक्त पाए जाने का उल्लेख था लेकिन प्रस्तुत मामले में मृतका की हत्या में प्रयुक्त हंसिया (आला कत्ल) को साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उसे वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में साबित भी किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्श क-17 है जिसमें हंसिया पर मानव रक्त पाया गया है। ऐसी दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई उपरोक्त विधि व्यवस्था का कोई लाभ अपीलार्थी/अभियुक्त को प्राप्त नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से यही साबित है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या में प्रयुक्त हंसिया (आला कत्ल) बरामद कराया गया। **सुरेश चन्द्र बाहरी बनाम बिहार राज्य**¹ वाले मामले में बरामदगी के पूर्व विवेचनाधिकारी ने अभियुक्त का डिस्कोलोजर स्टेटमेंट तैयार नहीं किया था। उक्त प्रकरण में डिस्कोलोजर स्टेटमेंट के अभाव में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बरामदगी को असत्य नहीं पाया गया।

56. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क रखा गया है कि

¹ 1995 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 60.

बरामदगी के गवाह राम गोपाल वादी का साला है व राजीव साढू का लड़का है जिनके निवास क्रमशः 15 व 25-30 किमी. की दूरी पर है इसलिए बरामदगी के समय उनकी उपस्थिति विश्वसनीय नहीं है । हमारे विचार से उक्त तर्क में कोई बल नहीं है क्योंकि यह बरामदगी घटना के दूसरे दिन दिनांक 31.1.2007 की है इसलिए घटना की सूचना पर गवाहान का वादी के घर ग्राम गजनेरा आना स्वाभाविक है फिर उनके आवास की दूरी इतनी अधिक नहीं है कि वे बरामदगी के समय ग्राम गजनेरा न पहुंच सकते हों । ऐसी दुखद घटना की सूचना पाकर वादी के रिश्तेदारों का उसके घर आना स्वाभाविक है । ऐसी दशा में यदि बरामदगी के साक्षी वादी के रिश्तेदार हैं तो उक्त आधार पर बरामदगी के संबंध में संदेह का कोई आधार नहीं पाया जाता है बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल (हंसिया) की बरामदगी सिद्ध है ।

57. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा गिरफ्तारी के बाद मृतका की हत्या में प्रयुक्त हंसिया बरामद कराई गई है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की रिपोर्ट में उक्त हंसिया पर मानव रक्त पाया गया है । हंसिया पर मानव रक्त कहां से आया इसका कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से नहीं दिया गया है । उपरोक्त परिस्थितियों में कथित बरामदगी के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से अपीलार्थी/अभियुक्त के निशानदेही पर मृतका की हत्या में प्रयुक्त हंसिया (आला कत्ल) बरामद कराया जाना सिद्ध है ।

58. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि पंचायतनामा में अपीलार्थी/अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं है तथा न ही हथियार का उल्लेख किया गया है। हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर भी अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त को नामित किया गया है और घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संख्या 2 ईलू तथा साक्षी संख्या 3 रामश्री द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के हाथ में हंसिया होने का उल्लेख किया गया है और हंसिया लेकर मृतका के शव के पास से भागते हुए देखने का उल्लेख किया गया है । पंचायतनामा में इस मामले के अपराध संख्या व धारा का उल्लेख है । ऐसी दशा में यदि पंचायतनामा में अपीलार्थी/अभियुक्त के नाम व हथियार का उल्लेख नहीं किया गया है तो

मात्र उक्त आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

59. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल का जो नक्शा नजरी तैयार किया है वह विश्वसनीय नहीं है । नक्शा नजरी में विवेचनाधिकारी ने अपीलार्थी/अभियुक्त को सी. स्थान पर बैठने का उल्लेख किया है और बी. स्थान पर मृतका की गठरी पड़ी होना दिखाया है तथा इसी बी. स्थान से मृतका को अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा पकड़ कर गन्ने के खेत में ए. स्थान पर ले जाने का उल्लेख किया गया है लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को घटना के पहले सी. स्थान पर बैठा देखा गया हो या किसी व्यक्ति ने मृतका को पकड़ कर गेहूं व गन्ने के बीच की मेड़ से खींचते हुए गन्ने के खेत में ले जाते हुए देखा हो । ऐसी दशा में घटनास्थल का जो नक्शा बनाया गया है वह विश्वसनीय नहीं है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में संदेह का कोई आधार नहीं पाया जाता है । कथित घटनास्थल वाला खेत राम गुलाम का है जो अपीलार्थी/अभियुक्त का पिता है और इसी खेत के पास से चकरोड निकलता है तथा इसी चकरोड से मृतका अपने घर जा रही थी व इसी खेत में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका को खींचकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया है और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है । साक्षियों द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखा गया है । ऐसी दशा में मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

60. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल से सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी की फर्द दिनांक 31.1.2007 को तैयार की है जिससे यह प्रकट होता है कि दिनांक 31.1.2007 तक मृतका का शव मौके पर पड़ा रहा है । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि साक्ष्य में यह आया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना प्रारम्भ कर दी गई थी और अभियोजन साक्षी संख्या 7 मोहम्मद याकूब खां द्वारा मृतका के शव का पंचायतनामा उसी दिन दिनांक 30.1.2007 को तैयार किया गया था । ऐसी दशा में यदि घटनास्थल से सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी कब्जा में लेने की कार्यवाही या फर्द दिनांक 31.1.2007 को तैयार

की गई है तो उक्त आधार पर न तो विवेचना दोषपूर्ण हो जाती है और न ही घटनास्थल के संबंध में संदेह का कोई आधार पाया जाता है । घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी को पुलिस कब्जा में लिया गया है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से **कैलाश गौर** बनाम **राज्य असम** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था प्रस्तुत की गई है उसका कोई लाभ अपीलार्थी/अभियुक्त को प्राप्त नहीं होता है ।

61. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे झूठा रंजिशन फंसाया गया है उसने कोई घटना नहीं की है । अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी सफाई में बचाव साक्षी संख्या 1 राम गुलाम तथा बचाव साक्षी संख्या 2 रामेश्वर दयाल को परीक्षित कराया गया है । बचाव साक्षी संख्या 1 राम गुलाम अपीलार्थी/अभियुक्त का पिता है ।

62. बचाव साक्षी संख्या 1 राम गुलाम ने अपने बयान में यह कथन किया है कि मुलजिम गुड्डू गंगवार उसका लड़का है । शादी-शुदा है उसके एक लड़का है । उसके गांव में कृष्ण कान्त रहते हैं । वह धान मील पर नौकरी करते हैं । सन् 2007 को शाम 6.00 बजे गांव में सूचना आई कि उसके खेत के बाहर लड़की की लाश मिली है । वह भी देखने पहुंचा, काफी भीड़ थी । उस समय कृष्ण कान्त गांव में मौजूद नहीं थे, वे धान मील पर थे उन्हें वहां से बुलवाया गया । वे करीब 6.30 बजे वहां आए । उस समय तक कोई चर्चा नहीं थी कि लड़की को कौन मार गया । यह लड़की पप्पू **उर्फ** कृष्ण कान्त की थी । कृष्ण कान्त के आने के बाद अपने बहनोई संजू को बरेली से बुलाया वह बरेली कचहरी में मुंशीगीरी का काम करते हैं । वह लगभग रात 7.30 बजे आए । पुलिस वाले घटनास्थल पर 6.00 बजे मौजूद नहीं थे बल्कि 6.00 बजे के आधे घंटे बाद आए थे । पुलिस वालों ने आने के बाद लाश सील कर दी । मुलजिम के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई । फिर रात के 2.00 बजे उसके लड़के गुड्डू गंगवार को उसके घर से पुलिस वाले पकड़ कर ले गए । पुलिस वाले साथ में उसे भी ले गए । उनसे पूछा तुम्हारे खेत के बाहर लाश मिली है बताओ किसने मारा है । मुझे पता ही नहीं था तो हम कैसे बताते । पुलिस वालों ने उसके लड़के को मारा-पीटा उसे झूठा बंद कर दिया । गजनेरा बड़ा गांव है 2300 वोट हैं गांव के कोई व्यक्ति को गवाह नहीं रखा, घर के लोग गवाह हैं उसके लड़के के खिलाफ झूठा मुकदमा बना दिया ।

63. बचाव साक्षी संख्या 2 रामेश्वर दयाल ने अपने बयान में यह

कथन किया है कि उसके गांव में कृष्ण कान्त **उर्फ** पप्पू रहते हैं 30 जनवरी, 2007 को शाम 6.00 बजे गांव में खबर फैली कि राम गुलाम के खेत के पास पप्पू की लड़की की लाश पड़ी है । पूरा गांव इकट्ठा हो गया । पप्पू राइस मील पर काम करता था वहां खबर करके बुलवाया गया । पुलिस आ गई उस समय यह जानकारी नहीं हुई कि घटना किसने की है । पुलिस वाले लाश को सील करके ले गए । पप्पू ने अपने बहनोई संजू को बरेली से बुलवाया । संजू कचहरी पर मुंशीगरी करता है । 6.00 बजे के डेढ़ घंटे के बाद संजू भटनागर गांव में आए । उस समय तक यह जानकारी नहीं हुई थी कि कौन मार गया । पुलिस वालों ने उस समय गुड्डू गंगवार को नहीं पकड़ा था । बाद में जानकारी हुई कि गुड्डू गंगवार के खिलाफ पुलिस ने वादी के साथ मिलकर झूठा मुकदमा बना दिया । उपरोक्त बचाव साक्षियों की सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उपरोक्त दोनों साक्षियों के साक्ष्य से घटना के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है तथा इस प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । प्रथम यह कि बचाव साक्षी संख्या 1 राम गुलाम स्वयं अभियुक्त का पिता है । यदि इस साक्षी को व उसके लड़के (गुड्डू **उर्फ** जितेन्द्र) को पुलिस वाले पकड़ कर थाने ले गए थे और उसके उक्त लड़के का चालान इस मुकदमे में कर दिया था तो यह साक्षी छूटने के बाद भी इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा सकता था लेकिन इस साक्षी ने इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि वह थाने से छूटने के बाद अपने लड़के गुड्डू को पकड़ने के बारे में किसी उच्चाधिकारी को सूचना नहीं दी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी स्वीकार किया है कि उसके तीन बेटे हैं उसके दो अन्य बेटों के नाम हरीश कुमार व सुरेन्द्र कुमार हैं । हमारे विचार से यदि इस घटना में अपीलार्थी/अभियुक्त की भूमिका न होती तो पुलिस इस साक्षी के उक्त पुत्रों से भी पूछताछ कर सकती थी और उन्हें भी थाने ले जा सकती थी लेकिन पुलिस द्वारा इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई ऐसी दशा में इस साक्षी का कथन स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है ।

64. बचाव साक्षी संख्या 2 रामेश्वर दयाल ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह

स्वीकार किया है कि जितेन्द्र **उर्फ** गुड्डू उसके ताऊ के लड़के का लड़का है । उसका और जितेन्द्र **उर्फ** गुड्डू का घर पास-पास में है । चूंकि यह साक्षी भी अपीलार्थी/अभियुक्त के खानदान व परिवार का व्यक्ति है । इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि घटना के संबंध में कोई संदेह व्यक्त किया जा सके । उपरोक्त दोनों बचाव साक्षियों की सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त हम इसी मत के हैं कि उनकी साक्ष्य से इस मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया जाना साबित नहीं होता है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 कृष्ण कान्त **उर्फ** पप्पू के साक्ष्य में यह आया है कि मौके पर संजू भटनागर 5.45 बजे शाम को पहुंच गए थे । संजू भटनागर का घर घटनास्थल से लगभग 22 किमी. दूर बताया गया है और उसे मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचना बताया गया है । हमारे विचार से घटनास्थल पर संजू भटनागर का 5.45 बजे पहुंचना स्वाभाविक है । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट शाम 6.10 बजे थाने पर दर्ज हो चुकी थी । ऐसी दशा में उपरोक्त दोनों बचाव साक्षियों का यह कहना कि वादी के बहनोई संजू भटनागर मौके पर रात्रि के 7.30 बजे पहुंचे इसमें कोई सत्यता नहीं रह जाती है । साक्ष्य में यह आया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए देखा गया था और अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू **उर्फ** जितेन्द्र को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद भी किया गया है । ऐसी दशा में उपरोक्त दोनों बचाव साक्षियों का यह कहना कि पुलिस द्वारा मृतका के शव को सील करने तक घटना कारित करने वाले व्यक्ति की जानकारी नहीं थी इसमें कोई वास्तविकता नहीं रह जाती है । अभियोजन साक्षियों के बयान में इस तरह की कोई बात नहीं आई है जिससे अपीलार्थी/अभियुक्त से वादी या उसके परिवार की कोई रंजिश होने की बात स्वीकार की जा सके बल्कि पत्रावली पर जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उससे एक मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि यह घटना अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा ही कारित की गई थी । ऐसी दशा में प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है ।

65. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि मृतका के सलवार पर मल पाए जाने का उल्लेख है । ऐसी

दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका की सलवार उतारना या उस पर शुक्राणु छोड़ना विश्वसनीय नहीं रह जाता है । हमारे विचार से उपरोक्त तर्क में भी कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मृतका की सलवार पंचायतनामे के समय उसके शव पर पड़ी पाई गई है । मृतका की योनि और हाईमन दोनों फटे हुए पाए गए हैं । इससे भी यही साबित है कि मृतका के साथ बलात्कार किया गया और मृतका की सलवार पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में शुक्राणु भी पाए गए हैं । ऐसी दशा में यदि मृतका की सलवार में मल भी पाया गया है तो मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

66. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित विधि संबंधी पांच स्वर्णिम सिद्धान्त (पंचशील) की शरद बिरदीचन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य¹ के प्रस्तर 152 में उचित रूप से निम्नरूपेण व्याखित किया गया है :-

* 152. The following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established :

(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. It may be noted here that this Court indicated that the circumstances. There is concerned 'must or should' and not 'may be' established. 'not proved' and 'must be or should be proved' as was held by this court in Shivaji Sahebrao Bobade Vs. State Maharashtra,

¹ [1985] 1 उम. नि. प. 995 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

* हिन्दी में यह इस प्रकार है :-

152. वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिए ।

(1) यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां 'सिद्ध करनी होंगी' या 'की जानी चाहिए' न की जा सकती है' । 'साबित की जा सकती हैं' और 'साबित करनी होंगी या की जानी चाहिए' में केवल व्याकरणिक अंतर ही नहीं है, बल्कि विधि अंतर है, जैसाकि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र

(1973) 2 SCC 793 : (AIR 1973 SC 2622) where the following observations were made :

“Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the mental distance between ‘may be’ and ‘must be’ is long and divides vague conjectures from sure conclusions.”

(2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency,

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

राज्य {[1973] 3 उम. नि. प. 1011 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793 = ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2622} में अभिनिर्धारित किया था । उसमें न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :

“निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी ‘होना चाहिए’ न कि केवल ‘दोषी हो सकता है’ और ‘हो सकता है’ तथा ‘होना चाहिए’ के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है, अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है ।”

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिए अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिए ;

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए ;

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए ; और

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

67. उल्लेखनीय है कि पस्तुत मामले में कथित घटना के दिन दिनांक 30.1.2007 को मृतका कुमारी सोनी अपनी दादी रामश्री (अभियोजन साक्षी संख्या 3) तथा बहन ईलू (अभियोजन साक्षी संख्या 2) व कंचन तथा भाई नितिन के साथ दिन में 2.00 बजे अपने खेत पर पुआल लेने गई थी । मृतका की दादी रामश्री ने सबसे पहले मृतका कुमारी सोनी को पुआल का गट्टर बांधकर देकर घर भेज दिया था । थोड़ी देर बाद मृतका की दादी रामश्री तथा बहन ईलू कंचन व भाई नितिन पताई लेकर घर वापस लौट रहे थे तथा जैसे ही वे राम गुलाम के खेत के पास पहुंचे तो उन्हें मृतका कुमारी सोनी की चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी जिस तरफ से चीखने-चिल्लाने की आवाज आ रही थी उस तरफ गन्ने के खेत में उन्होंने जाकर देखा तो अपीलार्थी/अभियुक्त मृतका के शव के पास से खून से सना हंसिया लेकर भाग रहा था । गवाहान ने मृतका सोनी के पास जाकर देखा तो वह खून से लथपथ मरी पड़ी थी । अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू के साक्ष्य में आया है कि मृतका की आंते बाहर निकली हुई थीं । इस घटना की सूचना वादी के बच्चों द्वारा घर पर आकर अपनी मां को दी गई जिस पर वादी की पत्नी ने नितिन को भेजकर इस घटना की सूचना वादी अभियोजन साक्षी संख्या 1 कृष्ण कान्त उर्फ पप्पू को दी जिस पर वादी घर आया तथा फिर मौके पर पहुंचा और उसने इस घटना की तहरीर अपने बहनोई संजू भटनागर से लिखवाकर थाने पर दाखिल की जिसके आधार पर थाने पर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया । यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को मृतका के शव के पास से हंसिया लेकर भागते हुए अभियोजन साक्षी संख्या 2 ईलू व अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री द्वारा देखा गया है । अभियोजन

(5) साक्ष्य की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि सम्पूर्ण मानवीय संभावना में वह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा ।

साक्षी संख्या 2 ईलू ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हम लोग राम गुलाम के गन्ने के खेत के पास आए तो गन्ने के खेत में से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और चकरोड पर ईख के खेत के कोने पर पुआल का गट्ठा पड़ा था इस पर वह व उसकी दादी, भाई, बहन भागकर गन्ने के खेत में जिधर से आवाज आ रही थी गए तो वहां देखा कि अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र हाथ में खून से सना हंसिया लेकर लाश के पास से भाग रहा था और सोनी खून से लथपथ वहां मरी हुई पड़ी थी । उसकी आंते बाहर निकली हुई थीं और सलवार अलग निकली हुई थी ।

68. अभियोजन साक्षी संख्या 3 रामश्री ने अपने बयान में अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार को मृतका के लाश के पास से हाथ में हंसिया लेकर खेत से निकलकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया है तथा यह भी बताया है कि जब अंदर जाकर गन्ने के खेत में देखा तो सोनी खून से लथपथ खेत में पड़ी थी और गला कटा हुआ था । यह घटना दिन में 3.30 बजे करीब की है । इस तरह गवाहान द्वारा मृतका के चीखने-चिल्लाने पर गन्ने के खेत में जाने का उल्लेख किया गया है और वहां पर मृतका के शव के पास से अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र को हंसिया लेकर भागते हुए देखने का उल्लेख किया गया है । उन्होंने मृतका कुमारी सोनी को खून से लथपथ पाया है और उसकी मृत्यु हो गई थी । इससे यही स्पष्ट है कि साक्षियों द्वारा मृतका की चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी गई और जब वह चीखने-चिल्लाने की आवाज पर मृतका के पास गए तो उन्होंने मृतका के शव के पास से अपीलार्थी/अभियुक्त को हंसिया लेकर भागते हुए देखा है तथा मृतका की हत्या में प्रयुक्त हंसिया अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.1.2007 को शाम 5.00 बजे बरामद कराया गया है । उक्त हंसिया को विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया था । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उक्त हंसिया पर मानव रक्त पाया गया है । उक्त हंसिया पर मानव रक्त कहां से आया । इसका कोई स्पष्टीकरण अभियुक्त की ओर से नहीं दिया गया । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृतका की सलवार अलग उतरी पड़ी थी तथा पोस्टमार्टम के समय मृतका की योनि और हाईमन फटे पाए गए हैं तथा मृतका की सलवार पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार शुक्राणु पाए गए हैं । मृतका के शरीर पर पोस्टमार्टम के समय

आठ कटे हुए घाव पाए गए हैं जिन्हें डाक्टर ने धारदार हथियार मसलन हंसिया से आना सम्भव कहा है तथा मृतका की मृत्यु घटना के समय यानि दिनांक 30.1.2007 को समय 3.30 बजे सायं होना सम्भव कहा है ।

69. उपरोक्त समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों से एक मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि यह घटना अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा ही कारित की गई थी और उसने ही कथित घटना के समय कुमारी सोनी को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा बलात्कार करने के पश्चात् उसकी हत्या कर दी । इस तरह पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से श्रृंखलाबद्ध तरीके से यह भली-भांति सिद्ध है कि कथित घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार ने मृतका के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के पश्चात् उसकी हत्या कर दी । तदनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 376 व 302 भा. द. स. संदेह से परे सिद्ध हैं । ऐसी स्थिति में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा जो अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 376 व 302 भा. द. स. के अन्तर्गत दोषी पाया गया है उसमें हम कोई विधिक त्रुटि व अनियमितता नहीं पाते हैं । तदनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त की धारा 376 व 302 भा. द. स. के अन्तर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है ।

70. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा विकल्प में यह भी तर्क रखा गया कि यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है । यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है यदि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित की गई है तो वह वासना को नियंत्रित न कर पाने के कारण हुई । ऐसी दशा में यह प्रकरण मृत्यु दण्ड से दण्डित किए जाने योग्य नहीं है ।

71. इसके विपरीत विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने कथित घटना के समय अपनी वासना की पूर्ति हेतु एक नाबालिग लड़की को पकड़ कर गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा बलात्कार करने के बाद हंसिया से घातक चोटें पहुंचाकर उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी है । ऐसी दशा में यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में आता है । अतएव विद्वान्

अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा पारित दण्डादेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । विद्वान् शासकीय अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में **अमित** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**¹, **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **संजय कुमार**², **रमेश भाई चन्दू भाई राथौड़** बनाम **गुजरात राज्य**³ तथा **राजेन्द्र प्रहालत्रों वाशनिक** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**⁴ उद्धृत किया है ।

72. **अमित** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**¹ के मामले में एक तीन साल की बच्ची का अपहरण तथा उसके साथ बलात्कार, अप्राकृतिक संभोग तथा उसकी हत्या कर साक्ष्य को छिपाने के आशय से उसके शव को एक गेंहू के खेत में फेंक देने का प्रकरण था तथा अभियुक्त के कथन के आधार पर मृतका का शव गवाहान के समक्ष एक प्लास्टिक के बैग में रखा हुआ बरामद हुआ था । उक्त प्रकरण में अभियुक्त को अन्य धाराओं में कारावास के साथ-साथ धारा 302 भा. द. स. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय ने भी अभियुक्त की दोषसिद्धि तथा उसके विरुद्ध पारित दण्डादेश की पुष्टि कर दी थी । उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्त के मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करते हुए उसे सम्पूर्ण जीवन तक के लिए जेल में रखने का आदेश पारित किया ।

73. **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **संजय कुमार**² के मामले में एक 18 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने व उसकी हत्या के प्रकरण में अभियुक्त को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है अतः अभियुक्त के मृत्यु दण्ड को उसके शेष बचे हुए जीवन तक कारावास में परिवर्तित कर दिया । उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील योजित की गई जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया ।

74. **रमेश भाई चन्दू भाई राथौड़** बनाम **गुजरात राज्य**³ के मामले में

¹ 2012 (77) ए. सी. सी. 201.

² (2012) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 970.

³ (2011) 2 एस. सी. सी. 764.

⁴ (2012) 4 एस. सी. सी. 37.

एक 27 वर्षीय युवक जो वाचमैन था को एक बच्ची के अपहरण व बलात्कार कर हत्या करने के प्रकरण में मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया था । उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त के मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करते हुए उसे सम्पूर्ण जीवन तक जेल में रखने का आदेश पारित किया है ।

75. **राजेन्द्र प्रहालत्रों वाशनिक** बनाम **महाराष्ट्र राज्य¹** के मामले में एक 31 वर्षीय शादी-शुदा अभियुक्त एक तीन वर्ष की बच्ची को उसके मां के पास से बिस्कूट दिलवाने के बहाने लिवा ले गया था बाद में बच्ची का शव नग्न अवस्था में पाया गया । उसके शरीर पर चोटें भी थीं । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 376(2)(एफ) एवं 377 भा. द. स. के अन्तर्गत दण्डादेश के साथ-साथ धारा 302 भा. द. स. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया । जिसके विरुद्ध अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में अपील योजित की गई जो उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई तत्पश्चात् अभियुक्त द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील योजित की गई जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निरस्त कर दिया गया ।

76. **अमृत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य²** के मामले में अभियुक्त ने एक 7-8 साल की बच्ची को ले जाकर उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी । मृतका का शव अभियुक्त के खेत में पाया गया था । इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 376 व 302 भा. द. स. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया था जिसकी पुष्टि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी । इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्ड को कठोर आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया ।

77. **अमित उर्फ अम्मू** बनाम **महाराष्ट्र राज्य³** के मामले में अभियुक्त जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी ने एक 11-12 वर्ष की लड़की जोकि कक्षा छः की छात्रा थी को बुलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी । उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा

¹ (2012) 4 एस. सी. सी. 37.

² ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 132.

³ (2003) 8 एस. सी. सी. 93.

अभियुक्त को धारा 376 भा. द. स. के अन्तर्गत दस वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 302 भा. द. स. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया था । जिसकी पुष्टि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय द्वारा कर दी गई थी । उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्त के मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया ।

78. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतका सोनी की आयु लगभग 14 वर्ष बताई गई है । वह कथित घटना के दिन अपनी दादी रामश्री, बहन ईलू, कंचन तथा भाई नितिन के साथ खेत पर पुआल व पताई लेने गई थी । मृतका की दादी रामश्री ने मृतका सोनी को सबसे पहले पुआल का गट्टर बांधकर घर भेज दिया था और मृतका पुआल का गट्टर लेकर अकेले घर वापस आ रही थी तो कथित घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतका कुमारी सोनी को अकेला पाकर अपने गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा बलात्कार के पश्चात् उसकी हत्या कर दी । अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने बयान के अन्तर्गत धारा 313 द. प्र. स. में अपनी आयु 25 वर्ष बताई है तथा उसका उक्त बयान दिनांक 16.7.2010 को अंकित किया गया था । इससे यही जाहिर होता है कि कथित घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त की आयु लगभग साढ़े 21 वर्ष थी चूंकि घटना के समय कुमारी सोनी की आयु लगभग 14 वर्ष थी तथा अपीलार्थी/अभियुक्त की आयु लगभग साढ़े 21 वर्ष थी । अपीलार्थी/अभियुक्त ने मृतका कुमारी सोनी को अकेला पाकर वासना के वशीभूत होकर मृतका कुमारी सोनी को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी । ऐसी दशा में प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है ।

79. यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है । अपीलार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है तथा इस तरह की भी परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं जिससे कि भविष्य में अपीलार्थी/अभियुक्त के जीवन में कोई सुधार न हो सके । अतएव प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त को मृत्यु दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा ।

80. तदनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पारित मृत्यु दण्ड के

आदेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डू उर्फ जितेन्द्र कुमार गंगवार को धारा 302 भा. द. स. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास एवं 20,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अपीलार्थी/अभियुक्त को तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

81. अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा. द. स. के अन्तर्गत पारित दण्डादेश की पुष्टि की जाती है। तदनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील आंशिक रूप से मृत्यु दण्ड के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है।

82. संदर्भ संख्या 12 वर्ष 2010 निरस्त किया जाता है।

83. निर्णय की प्रति एवं परीक्षण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाए।

दिनांक : 13.8.2013

अ.

आर्य

(2014) 1 दा. नि. प. 647

इलाहाबाद

हबीब

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

तारीख 26 सितंबर, 2013

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 256(2), 258 और 302 – परिवादी की मृत्यु – मात्र परिवादी की मृत्यु पर परिवादी द्वारा फाइल की गई आपराधिक कार्यवाहियां स्वतः समाप्त नहीं हो जातीं बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति या अभियोजन अभिकरण द्वारा कार्यवाही संचालित करने की अनुज्ञा देने की शक्ति प्राप्त है।

मामले का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक हबीब के विरुद्ध श्रीमती इमराना जो उसकी पत्नी थी, द्वारा एक परिवाद फाइल किया गया और उनके बीच भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 के अधीन इस परिवाद के फाइल करने के 6 वर्ष पूर्व विवाह संपन्न हुआ था। परिवादी श्रीमती इमराना और उसके साक्षियों के कथन विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और 202 के अधीन अभिलिखित किए गए जिसने उक्त साक्ष्य के आधार पर आवेदक और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन विचारण का सामना करने के लिए समन किया। परिवादी श्रीमती इमराना का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के अधीन अभिलिखित करने के लिए मामले की तिथि नियत की गई। श्रीमती इमराना, आवेदक की पत्नी की मृत्यु विचारण के दौरान तारीख 24 जुलाई, 2011 को हो गई। उसके पश्चात् विपक्षी पक्षकार संख्या 2 जो श्रीमती इमराना का सगा भाई है ने 12 सितंबर, 2011 को परिवादी श्रीमती इमराना जो उसकी बहन थी के स्थान पर उसे प्रतिस्थापित कर आवेदक के विरुद्ध विचारण जारी रखने के लिए उसे मंजूरी प्रदान करने के लिए न्यायालय से अनुज्ञा के लिए भी 2008 के परिवाद मामला संख्या 9508 में बुलंदशहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल किया। विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ज़हीर अहमद के उक्त आवेदन को विद्वान् मजिस्ट्रेट के द्वारा साक्ष्य के लिए मामला 12 सितंबर, 2011 नियत करते हुए मंजूर किया। जब आवेदक को परिवादी श्रीमती इमराना के भाई ज़हीर अहमद के तारीख 12 सितंबर, 2011 के उक्त आवेदन और विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 12 सितंबर, 2011 के उक्त आदेश की जानकारी मिली तो वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हुआ और अपनी उपस्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए छूट आवेदन फाइल किया और अंततः 2 सितंबर, 2011 के आदेश से व्यथित होकर परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन विलंब माफी के आवेदन के साथ बुलंदशहर के सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया। निचले पुनरीक्षण न्यायालय ने आवेदक और विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को सुनने के पश्चात् उसमें कथित सीमा के आधार पर आवेदक द्वारा फाइल आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया कि आवेदक को विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पारित तारीख 12 सितंबर, 2011 के आदेश के बारे में जानकारी तारीख 6 फरवरी, 2011 को अध्यक्ष संख्या 79 द्वारा 12 सितंबर, 2011 की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन फाइल की थी, जबकि आवेदक ने, निचले पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष यह कहा

है कि उसे तारीख 12 सितंबर, 2011 के आदेश के बारे में जानकारी अपने अधिवक्ता के माध्यम से 19 अगस्त, 2012 को हुई जिसका विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा विरोध किया गया था। निचले पुनरीक्षण न्यायालय के आगे यह मत व्यक्त किया गया कि आवेदक द्वारा उक्त पुनरीक्षण फाइल करने में 9 मास का विलंब किया गया जिसका उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और आज भी पुनरीक्षण फाइल करने में उक्त विलंब के लिए आवेदक द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। आवेदक का परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन खारिज कर दिया गया क्योंकि उक्त पुनरीक्षण फाइल करने के लिए विलंब के लिए आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण समाधानप्रद नहीं था। अतः आवेदक के उक्त आवेदन पत्र संख्या 5-बी को तारीख 17 जनवरी, 2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। बुलंदशहर जिले के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 16 द्वारा पारित तारीख 17 जनवरी, 2013 के आदेश से व्यथित होकर बुलंदशहर जिला के कोतवाली शहर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन 2008 के परिवाद मामला संख्या 9508 में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश तारीख 12 सितंबर, 2011 और 2012 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 105 में आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह आवेदन फाइल किया। उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट है कि परिवादी श्रीमती इमराना जो आवेदक की पत्नी है, की स्वीकार्यतः मृत्यु 24.7.2011 को हुई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के अधीन उसका साक्ष्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाना था। विचारण के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई अतः इसे अभिलिखित नहीं किया जा सका। विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ज़हीर अहमद जो परिवादी श्रीमती इमराना का सगा भाई है आवेदक को नियोजित करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन विचारण चालू रखने की अनुज्ञा चाहते हुए संबद्ध विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जिसे विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 12 सितंबर, 2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा मंजूर किया गया। आवेदकों को अभियोजित करने की अनुज्ञा चाहते हुए विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा फाइल उक्त आवेदक के परिशीलन से आगे यह प्रकट होता है कि श्रीमती इमराना के असामयिक मृत्यु के पश्चात् उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था अतः विपक्षी पक्षकार संख्या 2 जो परिवादी इमराना का भाई है, ने आवेदन को जारी रखने की अनुज्ञा मांगी। दंड

प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त या अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने की दशा में उपलब्ध है किंतु उक्त संहिता में परिवादी की मृत्यु के लिए अभिव्यक्ततः यह उपबंध नहीं करता। संहिता जांच या विचारण का उपशमन का उपबंध नहीं करता यद्यपि यह पुरानी संहिता की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 411अ(2) और 417 के अधीन अपील में अभियुक्त की मृत्यु पर अपीलों के उपशमन का उपबंध करती है और दण्डादेश या जुर्माने से अपील के सिवाय सभी अपील को अपीलार्थी की मृत्यु पर उपशमन का उपबंध करता है। अतः परिवादी पर आरंभ हुए मामले में परिवादी की मृत्यु पर क्या होता है, साधारणतया संहिता के उपबंधों से अनुमान निकाला जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के परिशीलन से यह सुस्थिर है कि परिवादी की मृत्यु पर धारा 256(2) परिवादी की मृत्यु पर दंड प्रक्रिया संहिता स्वयमेव आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त नहीं कर सकती और उस दशा में आपराधिक मामलों के संचालन के लिए किसी व्यक्ति या अभियोजन अभिकरण को मंजूर कर विद्वान् मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है। उसके द्वारा फाइल किए गए परिवाद को खारिज नहीं किया जा सकता है न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 और 258 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित किया जा सकता है। (पैरा 16, 19 और 23)

अवलंबित निर्णय

पैरा

- [1967] ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 983 :
आश्विन नानू भाई व्यास बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य । 11,20,21

निर्दिष्ट निर्णय

- [2006] 2006 (55) ए. सी. सी. 1016 (एस. सी.) :
बाला साहब के ठाकरे और एक अन्य बनाम वेंकट उर्फ बाबरू और एक अन्य ; 12,22
- [2005] ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 48 :
जिम्मी जहांगीर मदान बनाम बॉली कैरीयप्पा हिंडनले (मृतक) विधिक प्रतिनिधि द्वारा ; 13,21
- [1980] 1980 ला सूट (कर्ना.) 28 :
सुबाना हेगड़े बनाम दया वप्पा गोड़ा ; 8

[1919] ए. आई. आर. 1919 लाहौर 409 :
लाभू और अन्य बनाम सम्राट ।

7

**आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2013 का आवेदन संख्या
17280.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से

श्री शिशिर कुमार तिवारी

प्रत्यर्था की ओर से

सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा – मामले का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक हबीब के विरुद्ध श्रीमती इमराना जो उसकी पत्नी थी, द्वारा एक परिवाद फाइल किया गया और उनके बीच भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 के अधीन इस परिवाद के फाइल करने के 6 वर्ष पूर्व विवाह संपन्न हुआ था । परिवादी श्रीमती इमराना और उसके साक्षियों के कथन विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और 202 के अधीन अभिलिखित किए गए जिसने उक्त साक्ष्य के आधार पर आवेदक और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन विचारण का सामना करने के लिए समन किया । परिवादी श्रीमती इमराना का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के अधीन अभिलिखित करने के लिए मामले की तिथि नियत की गई । श्रीमती इमराना, आवेदक की पत्नी की मृत्यु विचारण के दौरान तारीख 24 जुलाई, 2011 को हो गई । उसके पश्चात् विपक्षी पक्षकार संख्या 2 जो श्रीमती इमराना का सगा भाई है ने 12 सितंबर, 2011 को परिवादी श्रीमती इमराना जो उसकी बहन थी के स्थान पर उसे प्रतिस्थापित कर आवेदक के विरुद्ध विचारण जारी रखने के लिए उसे मंजूरी प्रदान करने के लिए न्यायालय से अनुज्ञा के लिए भी 2008 के परिवाद मामला संख्या 9508 में बुलंदशहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल किया । विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ज़हीर अहमद के उक्त आवेदन को विद्वान् मजिस्ट्रेट के द्वारा साक्ष्य के लिए मामला 12 सितंबर, 2011 नियत करते हुए मंजूर किया ।

2. जब आवेदक को परिवादी श्रीमती इमराना के भाई ज़हीर अहमद के तारीख 12 सितंबर, 2011 के उक्त आवेदन और विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 12 सितंबर, 2011 के उक्त आदेश की जानकारी मिली तो वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हुआ और अपनी उपस्थिति से मुक्ति

दिलाने के लिए छूट आवेदन फाइल किया और अंततः 2 सितंबर, 2011 के आदेश से व्यथित होकर परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन विलंब माफी के आवेदन के साथ बुलंदशहर के सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया। निचले पुनरीक्षण न्यायालय ने आवेदक और विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को सुनने के पश्चात् उसमें कथित सीमा के आधार पर आवेदक द्वारा फाइल आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया कि आवेदक को विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पारित तारीख 12 सितंबर, 2011 के आदेश के बारे में जानकारी तारीख 6 फरवरी, 2011 को अध्यक्ष संख्या 79 द्वारा 12 सितंबर, 2011 की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन फाइल की थी, जबकि आवेदक ने, निचले पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष यह कहा है कि उसे तारीख 12 सितंबर, 2011 के आदेश के बारे में जानकारी अपने अधिवक्ता के माध्यम से 19 अगस्त, 2012 को हुई जिसका विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा विरोध किया गया था। निचले पुनरीक्षण न्यायालय के आगे यह मत व्यक्त किया गया कि आवेदक द्वारा उक्त पुनरीक्षण फाइल करने में 9 मास का विलंब किया गया जिसका उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और आज भी पुनरीक्षण फाइल करने में उक्त विलंब के लिए आवेदक द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। आवेदक का परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन खारिज कर दिया गया क्योंकि उक्त पुनरीक्षण फाइल करने के लिए विलंब के लिए आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण समाधानप्रद नहीं था। अतः आवेदक के उक्त आवेदन पत्र संख्या 5-बी को तारीख 17 जनवरी, 2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. बुलंदशहर जिले के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 16 द्वारा पारित तारीख 17 जनवरी, 2013 के आदेश से व्यथित होकर बुलंदशहर जिला के कोतवाली शहर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन 2008 के परिवाद मामला संख्या 9508 में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश तारीख 12 सितंबर, 2011 और 2012 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 105 में आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह आवेदन फाइल किया।

4. विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को कोई नोटिस जारी करने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि इस आवेदन में अन्तर्वलित प्रश्न विधिक प्रकृति का है। अतः इस न्यायालय ने विद्वान् सहायक सरकारी अधिवक्ता की सहायता से मामले की सुनवाई आरंभ होती है।

5. आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री अपूर्व हजेला और राज्य की ओर से विद्वान् सहायक सरकारी अधिवक्ता श्री निखिल चतुर्वेदी को सुना ।

6. आवेदक के काउंसेल विद्वान् द्वारा यह दलील दी गई कि आवेदक और श्रीमती इमराना के बीच विवाह परिवाद फाइल करने के 6 वर्ष पूर्व हुआ था और श्रीमती इमराना की मृत्यु विचारण के दौरान हुई इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के अधीन परिवादी की मृत्यु के कारण विचारण न्यायालय द्वारा उसका साक्ष्य अभिलिखित नहीं किया जा सका अतः उसके द्वारा फाइल यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है और आवेदक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अधीन उपबंधों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जाना चाहिए । उन्होंने आगे यह तर्क किया कि परिवादी श्रीमती इमराना की मृत्यु के पश्चात् उसके भाई ज़हीर अहमद को आवेदक के विरुद्ध विचारण जारी रखने की अनुज्ञा की ईप्सा कर आवेदन फाइल करने का कोई अधिकार नहीं था और परिवादी श्रीमती इमराना के स्थान पर आवेदक के विरुद्ध विचारण जारी रखने की उसे अनुज्ञा देते हुए विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ज़हीर अहमद के उक्त आवेदन को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा मंजूर किया जाना विधि की स्थापित प्रतिपादना के विरुद्ध है । अतः, तारीख 12 सितंबर, 2011 को विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाना चाहिए । उन्होंने आगे इंगित किया कि तारीख 12 सितंबर, 2011 के आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने निचले पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण फाइल किया जो इस आधार पर अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया कि उक्त पुनरीक्षणकाल बाधित है और उक्त पुनरीक्षण फाइल करने के विलंब को आवेदक द्वारा समाधानप्रद रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है । उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि दांडिक पुनरीक्षण के समर्थन में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन खारिज करते हुए निचले पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को न्यायालय द्वारा अवैध रूप से खारिज किया गया था अतः, इसे भी अपास्त किया जाना चाहिए ।

7. उन्होंने आगे यह आग्रह किया कि परिवादी श्रीमती इमराना के भाई ज़हीर अहमद को परिवादी के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि परिवाद परिवादी का व्यक्तिगत था जो न्यायालय की अनुशास्ति के बिना समन नहीं किया जा सकता । उन्होंने

लाभू और अन्य बनाम सम्राट¹ वाले मामले के निर्णय का अवलंब लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी विचारण के लंबन के दौरान परिवादी की मृत्यु पर कार्यवाही तब उपशमित हो जाएगी यदि शिकायत किया गया अपराध परिवादी का व्यक्तिगत हो अर्थात् यदि यह ऐसा मामला हो जिसे न्यायालय की अनुशास्ति के बिना उपशमित किया जा सकता हो। दूसरे मामलों में कार्यवाही उपशमित नहीं होती।

8. उन्होंने आगे **सुबाना हेगड़े बनाम दया वप्पा गोड़ा²** वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के उपबंध को ध्यान में रखते हुए परिवादी की मृत्यु पर अभियुक्त की मृत्यु को दोषमुक्त कर दिया था।

9. उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह अनुरोध किया कि विद्वान् मजिस्ट्रेट और निचले पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को इस न्यायालय द्वारा अपास्त किया जाए।

10. समानांतर स्तंभ में, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री निखिल चतुर्वेदी का यह निवेदन है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 12 सितंबर, 2011 का आक्षेपित आदेश और निचले पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि से संगत है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं। उन्होंने यह निवेदन किया कि श्रीमती इमराना जो आवेदक की पत्नी थी, उससे स्त्री धन वापस मांग करते हुए आवेदक के विरुद्ध शिकायत की थी, विचारण के लंबित रहने के दौरान उस समय मृत्यु हो गई जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया जाने वाला था और विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ज़हीर अहमद जो परिवादी का भाई था, को अपनी बहन श्रीमती इमराना जिसकी मृत्यु 24 अगस्त, 2011 को हुई थी, के स्थान पर आवेदक का अभियोजन जारी रखने की अनुज्ञा चाहते हुए निचले न्यायालय के समक्ष आवेदन करने का अधिकार था और विद्वान् मजिस्ट्रेट ने उचित ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 को ध्यान में रखते हुए आवेदक के अभियोजन के लिए उसकी अनुज्ञा मंजूर की थी।

11. अपनी दलील के समर्थन में विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता

¹ ए. आई. आर. 1919 लाहौर 409.

² 1980 ला सूट (कर्ना.) 28.

आश्विन नानू भाई व्यास बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य¹ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय का अवलंब लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि न्यायालय नया परिवादी प्रतिस्थापित नहीं कर सकती फिर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 495 (नई संहिता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अभियोजन संचालित करने को प्राधिकृत करने की शक्ति है ।

12. उन्होंने आगे **बाला साहब के ठाकरे और एक अन्य बनाम वेंकट उर्फ बाबरू और एक अन्य²** वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता की धारा 302 के अधीन आवेदन करने के लिए अभियोजन संचालित करने की अनुज्ञा मामले की जांच कर रहे या विचारण कर रहे मजिस्ट्रेट से अभिप्राप्त किया जाना चाहिए । मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से किसी पुलिस अधिकारी के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा अभियोजन संचालित करने की अनुज्ञा देने के लिए सशक्त है किंतु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा ।

13. उन्होंने **जिम्मी जहांगीर मदान बनाम बॉली कैरीयप्पा हिंडनले (मृतक) विधिक प्रतिनिधि द्वारा³** वाले मामले में उच्चतम न्यायालय का भी अवलंब लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन कोई पक्षकार स्वयं अभियोजन जारी रखने का आवेदन कर सकता है ऐसा आवेदन अधिवक्ता द्वारा भी किया जा सकता है ।

14. उक्त निर्णय को ध्यान देते हुए, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक के अभियोजन को जारी रखने की विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को अनुज्ञा देते हुए विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि के अनुकूल है जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह अनुरोध किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस आवेदन को खारिज किया जाए ।

¹ ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 983.

² 2006 (55) ए. सी. सी. 1016 (एस. सी.).

³ ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 48.

15. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए निवेदनों पर विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया ।

16. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट है कि परिवादी श्रीमती इमराना जो आवेदक की पत्नी है, की स्वीकार्यतः मृत्यु तारीख 24 जुलाई, 2011 को हुई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के अधीन उसका साक्ष्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाना था । विचारण के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई अतः इसे अभिलिखित नहीं किया जा सका । विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ज़हीर अहमद जो परिवादी श्रीमती इमराना का सगा भाई है आवेदक को नियोजित करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन विचारण चालू रखने की अनुज्ञा चाहते हुए संबद्ध विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जिसे विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 12 सितंबर, 2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा मंजूर किया गया । आवेदकों को अभियोजित करने की अनुज्ञा चाहते हुए विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा फाइल उक्त आवेदक के परिशीलन से आगे यह प्रकट होता है कि श्रीमती इमराना के असामयिक मृत्यु के पश्चात् उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था अतः विपक्षी पक्षकार संख्या 2 जो परिवादी इमराना का भाई है, ने आवेदन को जारी रखने की अनुज्ञा मांगी ।

17. विद्वान् विधिक विवाद्यक जो आवेदक द्वारा फाइल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन से न्यायनिर्णयन के लिए इस न्यायालय के समक्ष उद्भूत हुए, इस प्रकार है :-

“(i) क्या परिवादी की मृत्यु पर परिवादी द्वारा फाइल शिकायत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज किए जाने योग्य है और अभियुक्त आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है ?

(ii) क्या संबद्ध मजिस्ट्रेट के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए आदेश पारित करना आज्ञापक है ?”

18. इस बाबत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के उपबंध का परिशीलन आवश्यक है जिसे यहां उद्धृत किया जा रहा है :-

“256. परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु – (1) यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात्तर्वती किसी दिन,

जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं होता है तो, मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे :

परन्तु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवादी की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं है वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में कार्यवाही कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, उन मामलों को भी लागू होंगे, जहां परिवादी के हाजिर न होने का कारण उसकी मृत्यु है ।”

19. दंड प्रक्रिया संहिता अभियुक्त या अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने की दशा में ही किंतु परिवादी की मृत्यु के लिए अभिव्यक्ततः यह उपबंध नहीं करता । संहिता जांच या विचारण का उपशमन का उपबंध नहीं करता यद्यपि यह पुरानी संहिता की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 411अ(2) और 417 के अधीन अपील में अभियुक्त की मृत्यु पर अपीलों के उपशमन का उपबंध करती है और दण्डादेश या जुर्माने से अपील के सिवाय सभी अपील को अपीलार्थी की मृत्यु पर उपशमन का उपबंध करता है । अतः परिवादी पर आरंभ हुए मामले में परिवादी की मृत्यु पर क्या होता है, साधारणतया संहिता के उपबंधों से अनुमान निकाला जा सकता है ।

20. इस बाबत **आश्विन नानूभाई व्यास बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य¹** वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 3 और 4 पर ध्यान देना आवश्यक है जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

“3. कुसुम का परिवाद इस आधार पर अन्तर्विष्ट वर्जन को हटाने के लिए फाइल किया गया था यद्यपि धारा 417 के अधीन अपराध के लिए ऐसा कोई वर्जन विद्यमान नहीं है । धारा 493 के अधीन अपराध (ऐसा पुरुष जो किसी स्त्री को, जो विधि पूर्वक उससे विवाहित न हो प्रवंचना से यह विश्वास कारित करता है कि, वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास के साथ उसके साथ

¹ ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 983.

सहवास करता है और धारा 496 के अधीन कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने के कर्म जानते हुए पूरा करता है कि वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है) असंज्ञेय अशमनीय और अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ये ऐसे गंभीर अपराध हैं जो क्रमशः 10 वर्ष और 7 वर्ष तक के कारावासित से दंडनीय हैं। प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट मामले का विचारण नहीं कर रहा था बल्कि केवल सेशन न्यायालय को इसे सुपुर्द करने के लिए इसकी जांच कर रहा था यदि तथ्य सुपुर्दगी के योग्य पाया जाए। इस बात के दौरान कुसुम की मृत्यु हो गई। हमें यह उपधारित करना था कि परिवाद फाइल किए जाने के पश्चात् व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवाद की अपेक्षा अपराधों की बाबत अध्याय 18 के अधीन जांच होते समय परिवादी की मृत्यु का क्या प्रभाव है।

4. मामले के उपशमन का समर्थन करते हुए व्यास की ओर से श्री केसवानी ने धारा 431 के अधीन सादृश्यता का अवलंब लिया जिसके अधीन अपील धारा 247 और 259 के अधीन उपशमित होती है। जब परिवादी अनुपस्थित रहता है तो न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है। इस सादृश्यता का लाभ उसे नहीं मिलता क्योंकि वे विशेष स्थितियों का उपबंध करते हैं। न्यायालय के समक्ष जांच और विचारण की कई प्रक्रिया हैं। धारा 247 अध्याय 20 के अधीन आती है जो मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण के बारे में है और धारा 259 अध्याय 21 के अधीन आती है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के बारे में है। पूर्व वाले मामले के अधीन, यदि परिवाद और समन जारी किया जाता है तो किसी दिन परिवादी न्यायालय से अनुपस्थित रहता है तो जब तक वह विचारण में आगे कार्यवाही करने का विनिश्चय नहीं करता अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है। यह ऐसे मामले के विचारण में ही हो सकते हैं जो एक वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हैं। यह मामला मामले का समय से विचारण न होते हुए सुपुर्दगी जांच का मामला है। अतः धारा 247 न तो लागू होती है न ही कोई विधिमान्य सादृश्यता प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार धारा 259 जो वारंट मामलों के विचारण के लिए अध्याय में है अर्थात् मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामला और एक वर्ष से अधिक कारावासित दंडनीय है, कोई सादृश्यता प्रस्तुत नहीं कर सकती है। धारा 259 के अधीन अपराध का विचारण वारंट मामले के रूप में किया जा रहा है जो

शमनीय है और संज्ञेय नहीं है अतः मजिस्ट्रेट आरोप विरचित करने से पूर्व अभियुक्त को उन्मोचित भी कर सकता है यदि परिवादी अनुपस्थित रहता है। एक बार पुनः यह धारा लागू नहीं हो सकती क्योंकि प्रेंजिडेंसी मजिस्ट्रेट अध्याय-21 के अधीन मामले का विचारण नहीं कर रहा था।”

21. इसी प्रकार, जिम्मी जहांगीर मदान बनाम बॉली कैरीयप्पा हिंडनले (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा¹ वाले मामले में नाम आश्विन नानू भाई व्यास बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य² वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में यह अनुज्ञा दी थी कि विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल कर कोई व्यक्ति अभियोजन जारी रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन अनुज्ञा मामले का हकदार है। इस बाबत उक्त निर्णय के पैराग्राफ को नीचे उद्धृत किया रहा है :-

“10. इस मामले में, न तो परिवादी के वारिसों द्वारा अभियोजन चलाने के लिए संहिता की धारा 302 के अधीन याचिका फाइल की गई न ही सक्षम न्यायालय से उनके द्वारा कोई अनुज्ञा मांगी गई कि उन्हें मुख्तारनामा धारकों के माध्यम से अभियोजन चलाए जाने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए बल्कि मुख्तारनामा धारकों द्वारा अनुरोध किया गया था जो विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा यह मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 302 के अधीन याचिका का मंजूर किया जाना उचित नहीं था और उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश का जो अपास्त किए जाने योग्य है की पुष्टि गलत की है और संहिता की धारा 302 के अधीन वारिसों को संबद्ध न्यायालयों के समक्ष अभियोजन चलाए रखने या न्यायालय के समक्ष मुख्तारनामा धारकों के इस बाबत अभियोजन चलाए रखने के लिए प्राधिकृत के आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए फाइल की गई याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।”

22. बाला साहब के ठाकरे और एक अन्य बनाम वेंकट उर्फ बाबरू और एक अन्य³ वाले मामले के उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णय के पैराग्राफ संख्या 5, 6, 7 और 8 पर विचार करना इस विवाद्यक के लिए

¹ ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 48.

² ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 983.

³ 2006 (55) ए. सी. सी. 1016 (एस. सी.).

आवश्यक है जिसे यहां नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

“5. इस मोड़ पर, इस बात पर ध्यान देना सुसंगत है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में लागू सिद्धांतों के बारे में क्या कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘पुरानी संहिता’ कहा गया है) की धारा 495 के प्रतिनिर्देश से आश्विन नानू भाई व्यास **बनाम** महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य (ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 983) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मजिस्ट्रेट को किसी रिश्तेदार को अभियोजन जारी रखने के लिए परिवादी के रूप में कार्य करने की अनुज्ञा देने की शक्ति है। आश्विन नानू भाई व्यास **बनाम** महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य (पूर्वोक्त) को निर्दिष्ट करने के पश्चात् जिम्मी जहांगीर मदान **बनाम** बॉली कैरीयप्पा हिंडनले (मृतक) विधिक प्रतिनिधि द्वारा (ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 48) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवादी के वारिस को अभियोजन जारी रखने के लिए संहिता की धारा 302 के अधीन याचिका फाइल करने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

6. संहिता की धारा 302 इस प्रकार है –

‘302. अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा – (1) किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन के संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है, किन्तु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार न होगा :

परन्तु यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अपराध के अन्वेषण में, जिसके बारे में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, भाग लिया है तो अभियोजन का संचालन करने की उसे अनुज्ञा दी जाएगी।

(2) अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या प्लीडर द्वारा ऐसा कर सकता है।’

7. संहिता की धारा 302 को लागू करने के लिए मामले की जांच कर रहे या विचारण कर रहे मजिस्ट्रेट से अभियोजन चलाने की

अनुज्ञा अभिप्राप्त की जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट को निरीक्षक की पंक्ति से नीचे किसी पुलिस अधिकारी के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा अभियोजन चलाए जाने की अनुज्ञा देने की शक्ति है। किंतु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार होगा।

8. उपरोक्त ऐसी स्थिति में यदि कोई अनुज्ञा मृतक परिवादी के विधिक वारिसों द्वारा अभियोजन चलाए जाने के लिए मांगी जाती है तो इस पर न्यायालय द्वारा मामले पर विचार करते हुए इस परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा। ध्यान में यह बात लाई गई है कि तारीख 13 अक्टूबर, 2003 के आदेश द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई हैं। उस पृष्ठभूमि में मिस्टर एडूसर ने यह निवेदन किया है कि आवेदन इस न्यायालय के समक्ष फाइल किया जाएगा। जैसे ही कोई आवेदन फाइल किया जाएगा समुचित रूप से विचार किया जाएगा।”

23. उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के परिशीलन से यह सुस्थिर है कि परिवादी की मृत्यु पर धारा 256(2) परिवादी की मृत्यु पर दंड प्रक्रिया संहिता स्वयमेव आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त नहीं कर सकती और उस दशा में आपराधिक मामलों के संचालन के लिए किसी व्यक्ति या अभियोजन अभिकरण को मंजूर कर विद्वान् मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है। उसके द्वारा फाइल किए गए परिवाद को खारिज नहीं किया जा सकता है न ही दंड प्रक्रिया संहिता 256 और 258 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित किया जा सकता है।

24. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए आवेदक के विद्वान् काउंसिल के निवेदनों में कोई सार नहीं है अतः निचले न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों पर इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह आवेदन सारहीन है और तदनुसार खारिज किया जाता है।

आवेदन खारिज किया गया।

पां.

परवेज

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 17 जनवरी, 2014

न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति (सुश्री) सुनीता अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 307 – हत्या और हत्या का प्रयास – क्षतिग्रस्त साक्षियों और मृतक के शरीर पर पहुंची क्षतियों की प्रकृति हेतु अभियुक्त की गिरफ्तारी, हथियार की बरामदगी और अभियुक्त के प्रकटन कथन से युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन कथन साबित होने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने किसी भी कीमत पर आक्रामक प्रक्रम पर हत्या कारित की, अतः अभियुक्त हत्या और हत्या के प्रयास के अपराध का दायी है ।

अभियोजन का यह पक्षकथन है कि जनकपुरी थाना के पीरबजेशाह वाली गली संख्या 3 के निवासी अब्दुल हामिद की पत्नी इत्तिलाकर्ता असगरी ने जनकपुरी थाने में तारीख 2 सितंबर, 1997 को आवेदन किया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कहा गया है कि परवेज़ अपीलार्थी उसकी पुत्री शन्नो का पति था । तथापि, घटना पूर्व वे पृथक् हो गए थे और विवाह-विच्छेद कर लिया था । विवाह से उत्पन्न 3 बच्चे परवेज़ के साथ रह रहे थे । केवल एक पुत्री रूबी शन्नो के साथ उसके मायके में रह रही थी । न्यायालय में पक्षकारों के बीच विवाद चलने की कुछ फुसफुसाहट है क्योंकि परवेज़ घटना के 6 वर्ष पूर्व शन्नो को भगा ले गया था और उसके साथ विवाह कर लिया था । परवेज़ काफ़ी समय से शन्नो पर अपनी पुत्री रूबी को सौंपने का दबाव डाल रहा था और नाराज़ था क्योंकि उसने अपने साथ रह रही एक मात्र पुत्री को देने से इनकार कर दिया था । इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्थात् 2 सितंबर, 1997 को प्रातः लगभग 8 बजे परवेज़ अपने भाई रियासत के साथ असगरी के मकान पर आया और उसके और शन्नो के बीच रूबी (उसकी पुत्री) की अभिरक्षा के बारे में कुछ कहा-सुनी हुई । इसके पश्चात् उसने अपने भाई रियासत के साथ शन्नो को उस्तरा (चाकू) से मारना आरंभ कर दिया । इत्तिलाकर्ता असगरी और उसकी छोटी पुत्री शब्बो, उम्र लगभग 14 वर्ष ने शन्नो को बचाने का प्रयास किया गया

था और उन पर भी अपीलार्थी और भाई द्वारा आक्रमण किया गया । इत्तिलाकर्ता असगरी की छोटी पुत्री शब्बो को उसके शरीर पर घातक क्षतियां पहुंचीं । वह क्षतिग्रस्त स्थिति में चिल्लाते हुए अपने मकान से बाहर आई और मकान के बाहर खड़ंजे पर गिर गई । वह अपनी गर्दन पर पहुंची घातक क्षति के कारण घटनास्थल पर मर गई । घटना के दौरान पड़ोसी मृतक और क्षतिग्रस्त की चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर आए । अन्य पड़ोसियों के साथ जमालुदीन की पत्नी रशीदा ने भी घटना को देखा । उक्त सूचना पर अपीलार्थी और उसके भाई रियासत के विरुद्ध तारीख 2 सितंबर, 1997 प्रातः 9.05 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अधीन मामला दर्ज किया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् असगरी और शन्नो को पुलिस द्वारा उनके चिकित्सीय परीक्षा के लिए जिला अस्पताल भेजा गया । डा. टी. आर. शर्मा जो गवाह कक्ष में उपस्थित हुए, ने दोनों क्षतिग्रस्त अर्थात् असगरी और शन्नो की और मृतक शब्बो की भी मरणोत्तर परीक्षा की । विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपराध करने का हेतु था । यह अविवादित तथ्य है कि अपीलार्थी और शन्नो अभि. सा. 6 क्षतिग्रस्त साक्षी पति और पत्नी थे और उनके तनावग्रस्त संबंधों के कारण घटना के 2 वर्ष पूर्व उनका विवाह-विच्छेद हो गया था । तथापि, शन्नो के माता-पिता के मकान की विवाह-विच्छेद के पश्चात् उनके विवाह बंधन से उत्पन्न एक पुत्री के कारण विवाद बना रहा । अपीलार्थी अपनी पुत्री को अपनी अभिरक्षा में लेना चाहता था और पहले भी बच्चे की अभिरक्षा पर कहा-सुनी हुई थी । घटना की तारीख को अपीलार्थी इत्तिलाकर्ता के घर पर आया और अपनी पुत्री रूबी की अभिरक्षा के बारे में अपीलार्थी और शन्नो के बीच फिर से कहा-सुनी हुई । कुछ कहा-सुनी होने के पश्चात् अपीलार्थी ने अपनी पूर्व पत्नी शन्नो और इत्तिलाकर्ता असगरी के गर्दन में क्षतियां पहुंचाईं । जब वह उस्तरे से उन पर हमला कर रहा था तब असगरी की छोटी पुत्री उन्हें बचाने के लिए आई और अपीलार्थी ने उसकी गर्दन पर भी घातक क्षतियां पहुंचाईं । इससे मध्य से उसके गर्दन की श्वास नली और धमनी कट गई । मृतका शब्बो अपनी गर्दन पर पहुंची क्षतियों के कारण भागती हुई बाहर आई और मकान के सामने सड़क पर क्षतियों के कारण स्वर्ग सिधार गई । एक पड़ोसी अभि. सा. 1 जिसे घटना का साक्षी होना बताया गया है यद्यपि

उसने घटनास्थल पर अभियुक्त अपीलार्थी की उपस्थिति से इनकार किया और घटना लगभग प्रातः 8.00 बजे के आस-पास होने के बारे में भी इनकार किया, फिर भी अपनी मुख्य परीक्षा में उसने स्वीकार किया कि उसने दो क्षतिग्रस्त व्यक्ति अर्थात् असगरी और शन्नो को उनके घावों से रक्त निकलते हुए देखा और मृतका शब्बो को भी घर के बाहर सड़क पर पड़ा देखा। जहां तक घटनास्थल के बारे में विसंगतियों से संबंधित अपीलार्थी के विद्वान् काउंसिल के आवेदन का संबंध है यह देखने में आता है कि इसमें कोई असंगतता नहीं है। वस्तुतः अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार और उसके द्वारा हस्ताक्षरित योजना से यह दर्शित होता है कि मृतका “s” जहां मृतका का शरीर के चिह्नानित स्थान पर “s” और “x” की दूरी 24 कदम बताई गई थी। आगे इत्तिलाकर्ता ने शपथ पर यह भी कहा कि मृतका मकान में पहुंची क्षति के पश्चात् भागी और सड़क पर मकान के बाहर स्वर्ग सिधार गई। मात्र अभि. सा. 6 के कथन की एक पंक्ति कि पूरी घटना सहन में हुई जबकि उसने भी यह कहा कि अपीलार्थी द्वारा एक बार हमला किए जाने के पश्चात् और रक्त कमरे में जमीन पर गिरा, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसिल की दलील को स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है। अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी और साफ मिट्टी के नमूने लिए। सीरमविज्ञानी रिपोर्ट में रासायनिक परीक्षा के लिए भेजी गई रक्त रंजित मिट्टी में मानव रक्त पाए गए। अपीलार्थी के विद्वान् काउंसिल ने यह दलील दी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व लिखाई गई, को इस कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित घटना का समय प्रातः लगभग 8.00 बजे है। चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रातः 9.05 बजे तैयार की गई। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् क्षतिग्रस्त साक्षियों को जिला अस्पताल भेजा गया और उनकी परीक्षा प्रातः 9.30 बजे और 9.45 बजे की गई। क्षतिग्रस्त साक्षियों का यह कथन है कि वह पहले पुलिस थाने गए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और तब चिकित्सीय परीक्षा के लिए पत्र के साथ पुलिस द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया। मृत्यु समीक्षा में वर्णित चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का समय प्रातः 9.05 बजे है। मृत्यु समीक्षा के आरंभ का समय प्रातः 10.15 बजे और पूरा होने का समय 11.15 बजे उल्लिखित है। इस प्रकार घटनाओं के क्रम में कोई गायब कड़ी नहीं है तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित समय यह इंगित नहीं करता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व की है। इत्तिलाकर्ता और अन्य क्षतिग्रस्त साक्षियों पर अन्वेषक अधिकारी के कथनों में संगति है कि

क्षतिग्रस्त साक्षी पहले पुलिस थाने गए और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और तब चिकित्सा परीक्षा के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के लिए क्षतिग्रस्त साक्षियों के साथ चिकित्सालय को भेजे गए पत्र में मात्र इस कारण कि इसमें अपराध संख्या का उल्लेख नहीं था, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व है। हत्या हथियार “उस्तरा” की बरामदगी अपीलार्थी के इशारे पर हुई थी। बरामदगी को खुले स्थान से किया गया नहीं कहा जा सकता क्योंकि “उस्तरा” के खुले स्थान पर घास और कूड़े के नीचे छिपाया पाया गया था जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रकट किया गया यद्यपि इसे 4 बिजली के खंभों के बीच पारपुल के नीचे खुला स्थान बताया गया। क्योंकि अपीलार्थी अपने प्रकटन कथन में वर्णित निर्दिष्ट स्थान का अन्वेषक अधिकारी को ले गया तथा रक्त रंजित “उस्तरा” बरामद किया गया जो नीचे छिपाया गया था इसलिए इसे खुले स्थान से की गई बरामदगी नहीं कही जा सकती। अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श क-5 के रूप में तैयार और चिह्नित किया गया था। इसके परिशीलन से अभियुक्त अपीलार्थी के कथन से उस्तरा हथियार की बरामदगी को उसके द्वारा छिपाए जाने और पता चलने का तथ्य उपदर्शित होता है। अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर बरामदगी पर विचार करते हुए तेजाराम वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी की सहायता से कूड़े के नीचे से कुल्हाड़ी बरामद की गई थी वहां सामान्यतः उपरोक्त परिस्थितियों पर पारिस्थितिक साक्ष्य के मूल्यांकन के समय अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस मामले में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपराध कारित करने का ठोस हेतु था। यद्यपि अपीलार्थी ने घटना के लगभग 2 वर्ष पूर्व अपनी पूर्व पत्नी शन्नो का विवाह-विच्छेद कर दिया था और अलग-अलग रह रहा था फिर भी वह इत्तिलाकर्ता के मकान पर विवाह-विच्छेद के पश्चात् उत्पन्न अपनी पुत्री की अभिरक्षा पर जोर दे रहा था। स्वीकार्यतः उनके विवाह-बंधन से उत्पन्न 3 बच्चे अपीलार्थी के साथ रह रहे थे। इस प्रकार हेतु के अस्तित्व की बाबत संदेह की थोड़ी संभावना है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुतः अपीलार्थी किसी भी हालात में अपनी पुत्री को वापस लेना चाहता था। फिर भी यह स्थिर विधिक प्रतिपादन है कि प्रत्येक साक्ष्य को तब तक प्राथमिकता दी जाएगी जब तक उपलब्ध मौखिक साक्ष्य बिल्कुल चिकित्सा साक्ष्य से असुधार्य न हो।

किसी साक्षी के प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य की तुलना में अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य होगा और जब चिकित्सा साक्ष्य मौखिक परिसाक्ष्य को असंभाव्य ठहराता हो तो यह ऐसे साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुसंगत कारक होता है। जब दोनों के बीच विरोध इतना अधिक हो कि चिकित्सा साक्ष्य पूर्णतया प्रत्यक्ष साक्ष्य को कतई सत्य होने की पूरी संभावना से इनकार करता हो तो प्रत्यक्ष साक्ष्य अविश्वास किए जाने योग्य है। जहां तक चिकित्सक की राय का संबंध है कि घटना प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के वर्णित समय अर्थात् प्रातः 8.00 बजे पूर्व 6 घंटे पहले हुई होगी और अपीलार्थी का यह सुझाव है कि यह रात में हुई का यह अर्थ नहीं है कि डा. टी. आर. शर्मा अभि. सा. 3 मृत्यु का सही समय नियत करने में समर्थ था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, घटना लगभग प्रातः 8.00 बजे के आस-पास हुई। क्षतिग्रस्त असगरी और शन्नो पुलिस थाने गए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक द्वारा उनकी परीक्षा की गई। स्वयं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हेतु को भी प्रकट किया गया था। अतः यह असंभाव्य है कि अपीलार्थी को निश्चित रूप से फंसाया गया है क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने की तत्परता से यह दर्शित होता है कि छल साधन का कोई समय नहीं था। इसके अतिरिक्त यह समझ में आता है कि क्षतिग्रस्त साक्षी अपीलार्थी को मिथ्या रूप से क्यों फंसाएंगे जब उसने पहले ही शन्नो को तलाक दे दिया था और वह घटना होने से लगभग 2 वर्ष पहले से अलग रह रहा था और वास्तविक दोषी को मुक्त हो जाने देंगे। दोनों क्षतिग्रस्त साक्षियों के कथन में कोई विसंगति नहीं है और साक्षियों के बयानों में जब उन्होंने विस्तार से बताया कुछ छुटपुट विसंगतियां हैं तो जब तक विरोध तात्विक विषयों पर न हो तब तक समग्रता साक्षियों को अस्वीकार करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अन्य परिस्थितियों विशेषकर मृतका के शरीर पर पहुंचाई गई क्षतियों की प्रकृति, अभियुक्त की गिरफ्तारी, हथियार की बरामदगी, उसके प्रकटन कथन, अभियोजन पक्षकथन को साबित करती हैं। क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों पर विश्वास न होने का कोई कारण नहीं है। उक्त संस्वीकृति का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी अपने साथ उस्तरा लिए हुए था जब वह शन्नो से मिलने गया और फिर भी उसने शन्नो पर ही हमला नहीं किया किंतु दो अन्य व्यक्तियों पर भी हमला किया जो उसे बचाने के लिए आए। वह शब्दों जो घटनास्थल पर ही मर गई पर गंभीर क्षतियां कारित करने के पश्चात् भाग

गया । अपने साथ हथियार लिए रहने के तथ्य से स्पष्टतया यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी किसी भी कीमत पर हमेशा के लिए विवाद को सुलझाने का आशय रखता था । (पैरा 26, 28, 29, 32, 36, 41, 47, 48, 51, 52, 53, 54 और 56)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 4 एस. सी. सी. 360 : उमेश सिंह बनाम बिहार राज्य ;	49
[2012]	(2012) 10 एस. सी. सी. 476 : दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य ;	49
[2012]	(2012) 11 एस. सी. सी. 205 : सुनील क्लिफोर्ड डैनियल बनाम पंजाब राज्य ;	38,43
[2011]	(2011) 9 एस. सी. सी. 698 : राकेश और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य ;	49
[2011]	(2011) 6 एस. सी. सी. 288 : ब्रह्म स्वरूप और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ;	33
[2006]	(2006) 2 एस. सी. सी. 450 : राधा मोहन सिंह उर्फ लाल साहेब और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ;	33
[2006]	(2006) 13 एस. सी. सी. 65 : बासो प्रसाद बनाम बिहार राज्य ;	49
[2005]	(2005) 9 एस. सी. सी. 788 : जयश्री यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ;	34
[2005]	(2005) 10 एस. सी. सी. 374 : मांगू खान बनाम राजस्थान राज्य ;	46
[2002]	(2002) 4 एस. सी. सी. 426 : राजेश उर्फ राजू चन्दू लाल गांधी और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य ;	33
[1999]	(1999) 3 एस. सी. सी. 507 : राजस्थान राज्य बनाम तेजाराम और अन्य ;	30,39

- [1995] (1995) 1 एस. सी. सी. 80 :
सुरेश चन्द्र बाहरी बनाम बिहार राज्य ; 43
- [1988] (1988) सप्ली. एस. सी. सी. 241 :
अप्पाभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य
और अन्य । 31,44

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील संख्या
1728.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से

सर्वश्री सुधांशु श्रीवास्तव, राजुल
भार्गव, शरफुद्दीन अहमद, श्रीमती
नयनश्री, एस. एम. एन. अब्बास
अब्बादी, शकील अहमद और सुमित
गोयल

राज्य की ओर से

अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (सुश्री) सुनीता अग्रवाल ने दिया ।

न्या. अग्रवाल – अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री एस. एम. एन.
अब्बास अब्बादी और विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना ।

2. दो व्यक्ति अर्थात् परवेज़ और उसके भाई रियासत को भारतीय
दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सहारनपुर अपर जिला और सेशन
न्यायाधीश (एफ. टी. सी.) न्यायालय संख्या 1 के न्यायालय में विचारण के
लिए सुपुर्द किया गया । रियासत को भारतीय दंड संहिता की धारा 302
और 307 के अधीन अपराधों के किए जाने में संदेह का फायदा देते हुए
दोषमुक्त किया गया ।

3. अपीलार्थी परवेज़ को दोषी पाया गया और भारतीय दंड संहिता की
धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और 3,000/- रुपए के जुर्माने के
साथ आजीवन कारावास से दंडित किया गया । भारतीय दंड संहिता की
धारा 307 के अधीन उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/- रुपए
के जुर्माने से दंडित किया गया । व्यतिक्रम की दशा में अपीलार्थी को 6
मास अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । सभी दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

4. अभियोजन का यह पक्षकथन है कि जनकपुरी थाना के पीरबजेशाह वाली गली संख्या 3 के निवासी अब्दुल हामिद की पत्नी इत्तिलाकर्ता असगरी ने जनकपुरी थाने में तारीख 2 सितंबर, 1997 को आवेदन किया। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कहा गया है कि परवेज़ अपीलार्थी उसकी पुत्री शन्नो का पति था। तथापि, घटना पूर्व वे पृथक् हो गए थे और विवाह-विच्छेद कर लिया था। विवाह से उत्पन्न 3 बच्चे परवेज़ के साथ रह रहे थे। केवल एक पुत्री रूबी शन्नो के साथ उसके मायके में रह रही थी। न्यायालय में पक्षकारों के बीच विवाद चलने की कुछ फुसफुसाहट है क्योंकि परवेज़ घटना के 6 वर्ष पूर्व शन्नो को भगा ले गया था और उसके साथ विवाह कर लिया था।

5. परवेज़ काफ़ी समय से शन्नो पर अपनी पुत्री रूबी को सौंपने का दबाव डाल रहा था और नाराज़ था क्योंकि उसने अपने साथ रह रही एक मात्र पुत्री को देने से इनकार कर दिया था।

6. इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्थात् 2 सितंबर, 1997 को प्रातः लगभग 8 बजे परवेज़ अपने भाई रियासत के साथ असगरी के मकान पर आया और उसके और शन्नो के बीच रूबी (उसकी पुत्री) की अभिरक्षा के बारे में कुछ कहा-सुनी हुई। इसके पश्चात् उसने अपने भाई रियासत के साथ शन्नो को उस्तरा (चाकू) से मारना आरंभ कर दिया। इत्तिलाकर्ता असगरी और उसकी छोटी पुत्री शब्बो, उम्र लगभग 14 वर्ष ने शन्नो को बचाने का प्रयास किया गया था और उन पर भी अपीलार्थी और भाई द्वारा आक्रमण किया गया। इत्तिलाकर्ता असगरी की छोटी पुत्री शब्बो को उसके शरीर पर घातक क्षतियां पहुंचीं। वह क्षतिग्रस्त स्थिति में चिल्लाते हुए अपने मकान से बाहर आई और मकान के बाहर खडंजे पर गिर गई। वह अपनी गर्दन पर पहुंची घातक क्षति के कारण घटनास्थल पर मर गई। घटना के दौरान पड़ोसी मृतक और क्षतिग्रस्त की चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर आए। अन्य पड़ोसियों के साथ जमालुदीन की पत्नी रशीदा ने भी घटना को देखा।

7. उक्त सूचना पर अपीलार्थी और उसके भाई रियासत के विरुद्ध तारीख 2 सितंबर, 1997 प्रातः 9.05 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अधीन मामला दर्ज किया गया। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् असगरी और शन्नो को पुलिस द्वारा उनके चिकित्सीय परीक्षा के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। डा. टी. आर. शर्मा जो गवाह

कक्ष में उपस्थित हुए, ने दोनों क्षतिग्रस्त अर्थात् असगरी और शन्नो और मृतक शब्बो की भी मरणोत्तर परीक्षा की ।

8. इत्तिलाकर्ता असगरी की चिकित्सा परीक्षा प्रातः 9.00 बजे हुई और क्षति रिपोर्ट के अनुसार उसकी गर्दन और मध्य ठुड्डी के बाईं निचले ओर छेदित घाव की 2 क्षतियां थीं । इन दो क्षतियों के अलावा उसके शरीर पर नील और खरोंच भी पाई गई । क्षतियों की प्रकृति को सामान्य और किसी धारदार वस्तु द्वारा पहुंचाए जाने के रूप में उल्लिखित किया गया । इसी प्रकार की क्षतियां शन्नो के शरीर पर भी पाई गई जिसकी परीक्षा 9.45 बजे की गई । गर्दन के पीछे और सामने की ओर बाईं भौंह के बाह्य किनारे पर 3 छेदित घाव पाए गए । यह टिप्पण की गई है कि क्षतियां किसी धारदार वस्तु से कारित की गई थीं । दोनों क्षति रिपोर्टें तारीख 2 नवंबर, 1997 की ही हैं ।

9. मृतक की क्षतियां गर्दन के दाहिने और सामने की ओर छेदित घाव है जो हड्डी तक गहरा था और जो गर्दन के दाहिने कान के आधे भाग से तिरछा गर्दन के दाहिनी ओर के मध्य भाग से श्वास नली और धमनी तक था । मृत्यु पूर्व क्षतियों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई ।

10. अपीलार्थी परवेज़ को 18 सितंबर, 1997 को गिरफ्तार किया गया तथा उसके द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर हत्या के हथियार, उस्तरा की बरामदगी, घास-फूस से ढके पारपुल के नज़दीक 4 बिजली के खंभों के नीचे से हुए । 8 सितंबर, 1997 के बरामदगी ज्ञापन के अनुसार उस्तरा के हथ्ये और धारदार के अगले भाग पर रक्त पाया गया । सीरमविज्ञानी रिपोर्ट के अनुसार हत्या हथियार के उस्तरे पर पाए गए रक्त विघटित थे ।

11. इत्तिलाकर्ता की पड़ोसी अभि. सा. 1, श्रीमती रशीदा को पक्षद्रोही घोषित किया गया । अभियोजन द्वारा इसकी प्रतिपरीक्षा की गई । श्रीमती रशीदा अभि. सा. 1 यद्यपि पक्षद्रोही हो गई फिर भी यह स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर पहुंची थीं और क्षतिग्रस्त असगरी तथा शन्नो को सड़क पर मृत पड़ा देखा किन्तु परवेज़ और रियासत की उपस्थिति से इनकार किया । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह संकेत देने का प्रयास किया कि मोहल्ला के निवासियों ने असगरी और शन्नो के विरुद्ध अभिकथित रूप से वेश्यावृत्ति चलाए जाने का अभिकथन करते हुए आवेदन दिया था ।

12. अभि. सा. 2 क्षतिग्रस्त साक्षी और इत्तिलाकर्ता श्रीमती असगरी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपने बयान को दोहराया था ।

13. क्षतिग्रस्त साक्षी शन्नो अभि. सा. 6 ने यह बताया कि पुलिस थाने में उसकी माता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई और इसके पश्चात् जिला अस्पताल में उनकी चिकित्सा परीक्षा की गई । उसे और उनकी माता को अस्पताल में भर्ती किया गया । घटना का उल्लेख करते हुए उसने कहा कि परवेज़ अपने भाई रियासत के उसके मकान पर आया और उसकी पुत्री रूबी को उसकी गोद से छीनकर उस्तरा से उस पर हमला किया । रूबी को कोई क्षति नहीं पहुंची । अपीलार्थी ने पहले उस पर और फिर उसकी माता असगरी पर हमला किया । इसी बीच उसकी छोटी बहन शब्बो उसे बचाने के लिए आई, उस पर भी हमला किया गया और उसे घातक क्षतियां पहुंचीं । घटना मकान के सहन में हुई । अपीलार्थी सह-अभियुक्त के साथ कमरे के दरवाज़े से भाग गए जो गली की तरफ खुलता है ।

14. अभि. सा. 3 डा. टी. आर. शर्मा, जिसने क्षतिग्रस्त असगरी और शन्नो की परीक्षा की और शब्बो की भी मरणोत्तर परीक्षा की और शपथ-पत्र पर यह कहा कि असगरी और शन्नो को पहुंची क्षतियां ताज़ी थीं और उन्होंने अपने द्वारा की गई मरणोत्तर परीक्षा और रिपोर्ट को साबित किया ।

15. अभि. सा. 4 कांस्टेबल विजेंद्र सिंह और अभि. सा. 7, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह मृत्यु समीक्षा के साक्षी थे ।

16. अभि. सा. 5 कांस्टेबल हरीन्द्र सिंह हत्या हथियार “उस्तरा” की बरामदगी का साक्षी था । उसने दृढ़तापूर्वक यह कहा कि हथियार अभियुक्त परवेज़ की गिरफ्तारी के पश्चात् उसके बताए जाने पर 8 सितंबर, 1997 को बरामद किया गया था ।

17. अभि. सा. 8 उप-निरीक्षक के. पी. सिंह अन्वेषक अधिकारी थे ।

18. अभि. सा. 8 उप-निरीक्षक के. पी. सिंह स्थल अन्वेषक अधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा कि उसके द्वारा अर्थात् योजना तैयार की गई और इत्तिलाकर्ता असगरी की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया । उन्होंने आगे यह बताया कि रक्त इत्तिलाकर्ता के मकान के उस स्थान पर जहां शब्बो का शव पड़ा था, बिखरा पाया गया था । उन्होंने घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी और साफ मिट्टी की बरामदगी की और अभियुक्त के इशारे पर पारपुल के समीप 4 बिजली के खंभों के नज़दीक घास और कूड़े

के नीचे छिपाए गए स्थान से उस्तरा की बरामदगी की । पंच साक्षियों तथा अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7 अर्थात् कांस्टेबल विजेंदर सिंह और राजेन्दर सिंह जिनके हस्ताक्षर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर भी प्राप्त किए गए की उपस्थिति में उसकी मृत्यु समीक्षा तैयार की गई । हत्या हथियार को रासायनिक परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । उन्होंने यह भी बताया कि हत्या हथियार की बरामदगी के समय उस पर रक्त पाए थे ।

19. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया है और सभी अभिशंसी परिस्थितियां उसके सामने रखी गईं, जिसका उसने इनकार किया ।

20. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि घटना-स्थल के बारे में क्षतिग्रस्त साक्षी इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 2 असगरी और अभि. सा. 6 शन्नो के कथन में विसंगति है । अभि. सा. 2 इत्तिलाकर्ता ने कहा कि अपीलार्थी द्वारा कमरे के अंदर शब्बो पर हमला किया गया जब वह उसे और शन्नो को बचाने के लिए बाहर आई । वह चिल्लाते हुए घर से बाहर आई और इत्तिलाकर्ता के मकान के बाहर सड़क पर उसकी मृत्यु हो गई जबकि अभि. सा. 6 ने अपने कथन में कहा कि संपूर्ण घटना कमरे से जुड़े सहन में हुई जो इत्तिलाकर्ता के मकान के बाहर गली में खुलता है । उसने आगे यह कहा कि अभि. सा. 2 के कथन को ध्यान में रखते हुए यथा उपवर्णित घटना का समय गलत है । यह कहा गया है कि घटना लगभग 8.00 बजे प्रातः के आस-पास हुई जबकि डा. टी. आर. शर्मा जिसने मरणोत्तर परीक्षा की ने कहा कि मृतक के हाथ के ऊपरी भाग पर शव काठिन्य था, अतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित समय के 6 घंटे पूर्व घटना होने की संभावना है इस प्रकार यह 3 से 4 बजे के बीच का समय निकलता है ।

21. अगला आवेदन यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय से पूर्व की गई है क्योंकि क्षतिग्रस्त असगरी और शब्बो की चिकित्सीय परीक्षा के लिए लिखे गए पत्र (चिट्ठी मजरूबी) में अपराध संख्या नहीं लिखा गया है । साक्षियों का यह कथन है कि क्षतिग्रस्त साक्षी पुलिस थाने गए और रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् उन्हें चिकित्सीय परीक्षा के लिए पत्र के साथ भेजा गया था । यह तथ्य कि चिकित्सा परीक्षा के लिए चिकित्सक को सम्बोधित पत्र में अपराध संख्या वर्णित नहीं है स्पष्टतया यह दर्शित करता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व लिखित की गई है और यह मृत्यु समीक्षा

तैयार किए जाने और मरणोत्तर परीक्षा तैयार किए जाने के पश्चात् दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि मृत्यु समीक्षा अन्वेषक अधिकारी उप-निरीक्षक के. पी. सिंह द्वारा तैयार किया गया अभिकथित था तथापि, उसने मृत्यु समीक्षा पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए और 2 अन्य कांस्टेबल विजेंदर सिंह और राजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर मृत्यु समीक्षा पर लिए गए थे।

22. फिर भी अन्वेषक अधिकारी के. पी. सिंह ने अपने कथन में कहा कि स्थल योजना इत्तिलाकर्ता श्रीमती असगरी की उपस्थिति में तैयार की गई थी जबकि असगरी ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् उसे चिकित्सीय परीक्षा के लिए शब्बो के साथ भेजा गया था वह अस्पताल में ही रही। मृतका की शव-परीक्षा उसकी उपस्थिति में तैयार की गई थी और स्थल योजना की तैयारी के समय न तो वह और न ही उसकी पुत्री क्षतिग्रस्त साक्षी घटनास्थल पर गए। स्थल योजना पड़ोसियों की उपस्थिति में तैयार की गई थी, उसने अपने मकान की चाबी दी।

23. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने इत्तिलाकर्ता असगरी और अन्वेषक अधिकारी के कथन में उक्त असंगतता पर अधिक बल दिया और उस आधार पर यह आवेदन किया गया कि स्थल योजना घटनास्थल पर तैयार की गई थी।

24. अंत में उनका यह निवेदन है कि अभिकथित हत्या हथियार “उस्तरा” खुले स्थान में पाया गया था और यह अपीलार्थी पर थोपा गया था। उक्त तथ्य की पुष्टि अभि. सा. 5 के कथन से होती है जो उस कपड़ा जिस पर अभिकथित हत्या हथियार रखा गया था और सीलबंद कर दिया गया था, सहारनपुर के लियाकत पुलिस थाना नाकौर का नाम था। यद्यपि इसमें न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की पर्ची थी जहां परीक्षा के लिए भेजी गई थी। अभिकथित हथियार को इस अपीलार्थी से नहीं जोड़ा जा सकता और यह कोई अन्य हथियार था जिसे रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था। इन विसंगतियों के कारण संपूर्ण अभियोजन कथन मिथ्या है क्योंकि पाई गई असंगतियां और विसंगतियां अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक हैं।

25. समानांतर स्तंभ में, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता का यह निवेदन है कि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा इंगित की गई

विसंगतियां नगण्य विसंगतियां हैं । यह पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है और विश्वसनीय और अकाट्य साक्ष्य द्वारा अभिशंसी पारिस्थितिक की प्रत्येक घटना के आधार पर अभियोजन द्वारा साबित किया गया है । घटनाओं की कड़ी पूरी है जिसके आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी ठहराने के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

26. अपराध करने का हेतु था । यह अविवादित तथ्य है कि अपीलार्थी और शन्नो अभि. सा. 6 क्षतिग्रस्त साक्षी पति और पत्नी थे और उनके तनाव ग्रस्त संबंधों के कारण घटना के 2 वर्ष पूर्व उनका विवाह-विच्छेद हो गया था । तथापि, शन्नो के माता-पिता के मकान की विवाह-विच्छेद के पश्चात् उनके विवाह बंधन से उत्पन्न एक पुत्री के कारण विवाद बना रहा । अपीलार्थी अपनी पुत्री को अपनी अभिरक्षा में लेना चाहता था और पहले भी बच्चे की अभिरक्षा पर कहा-सुनी हुई थी । घटना की तारीख को अपीलार्थी इत्तिलाकर्ता के घर पर आया और अपनी पुत्री रूबी की अभिरक्षा के बारे में अपीलार्थी और शन्नो के बीच फिर से कहा-सुनी हुई । कुछ कहा-सुनी होने के पश्चात् अपीलार्थी ने अपनी पूर्व पत्नी शन्नो और इत्तिलाकर्ता असगरी के गर्दन में क्षतियां पहुंचाईं । जब वह उस्तरे से उन पर हमला कर रहा था तब असगरी की छोटी पुत्री उन्हें बचाने के लिए आई और अपीलार्थी ने उसकी गर्दन पर भी घातक क्षतियां पहुंचाईं । इससे मध्य से उसके गर्दन की श्वास नली और धमनी कट गई । मृतका शब्बो अपनी गर्दन पर पहुंची क्षतियों के कारण भागती हुई बाहर आई और मकान के सामने सड़क पर क्षतियों के कारण स्वर्ग सिधार गई । एक पड़ोसी अभि. सा. 1 जिसे घटना का साक्षी होना बताया गया है यद्यपि उसने घटनास्थल पर अभियुक्त-अपीलार्थी की उपस्थिति से इनकार किया और घटना लगभग प्रातः 8.00 बजे के आस-पास होने के बारे में भी इनकार किया, फिर भी अपनी मुख्य परीक्षा में उसने स्वीकार किया कि उसने दो क्षतिग्रस्त व्यक्ति अर्थात् असगरी और शन्नो को उनके घावों से रक्त निकलते हुए देखा और मृतका शब्बो को भी घर के बाहर सड़क पर पड़ा देखा ।

27. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसलों के निवेदनों पर विचार किया और अभिलेख का परिशीलन किया ।

28. जहां तक घटनास्थल के बारे में विसंगतियों से संबंधित अपीलार्थी के विद्वान् काउंसल के आवेदन का संबंध है यह देखने में आता

है कि इसमें कोई असंगतता नहीं है। वस्तुतः अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार और उसके द्वारा हस्ताक्षरित योजना से यह दर्शित होता है कि मृतका “s” जहां मृतका का शरीर पड़ा हुआ था, उस स्थान पर “s” और “x” की दूरी 24 कदम बताई गई थी।

29. आगे इत्तिलाकर्ता ने शपथ पर यह भी कहा कि मृतका मकान में पहुंची क्षति के पश्चात् भागी और सड़क पर मकान के बाहर स्वर्ग सिंघार गई। मात्र अभि. सा. 6 के कथन की एक पंक्ति की पूरी घटना “सहन” में हुई जबकि उसने भी यह कहा कि अपीलार्थी द्वारा एक बार हमला किए जाने के पश्चात् और रक्त कमरे में जमीन पर गिरा, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसिल की दलील को स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है। अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी और साफ मिट्टी के नमूने लिए। सीरमविज्ञानी रिपोर्ट में रासायनिक परीक्षा के लिए भेजी गई रक्त रंजित मिट्टी में मानव रक्त पाए गए।

30. **राजस्थान राज्य बनाम तेजाराम और अन्य¹** वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का निर्देश किया जा सकता है जिसमें साक्षियों के दो वर्ग के बीच साक्ष्य की विसंगति पर विचार किया गया था। निर्णय के पैरा 18 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि छोटी से विसंगति को पर्वताकार बनाने और तत्पश्चात् संपूर्ण साक्ष्य का तात्त्विक विसंगति बताकर नामंजूर करने के पक्ष में उच्च न्यायालय के पास कोई औचित्य नहीं था। उक्त मामले में दो वर्ग के साक्ष्यों में यह विसंगति थी कि 2 साक्षियों ने कहा कि हमलावरों को मकान के पश्चिमी दरवाजे से जाते हुए देखा गया जबकि 2 अन्य साक्षियों ने कहा कि हमलावर पूर्वी दरवाजे से बाहर गए। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मामले की परिस्थितियों में ऐसे साक्षियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

31. **अप्पाभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य²** वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 13 और 14 में यह अभिनिर्धारित किया कि परिसाक्ष्य की छुटपुट विसंगतियों को असम्यक् महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त पीड़ित, हमलाग्रस्त पीड़ित को सर्वोत्तम प्रत्यक्षदर्शी साक्षी माना जाना चाहिए। निर्णय के पैराग्राफ 13 और

¹ (1993) 3 एस. सी. सी. 507.

² (1988) सप्ली. एस. सी. सी. 241.

14 को उद्धृत किया जा रहा है :-

“13. दूसरी दलील पर, विद्वान् काउंसिल ने अपने पूर्व कथन एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कथन प्रदर्श 66 और दूसरा अन्वेषण के दौरान के विपरीत देवजी (अभि. सा. 4) के साक्ष्य के कई विरोधों को उजागर किया। तथापि, हमने सुसंगत साक्ष्य की भी परीक्षा की। यह सही है कि देवजी के साक्ष्य में कई विरोध हैं। पुलिस के समक्ष अपने कथन में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रकट कार्य किया गया नहीं बताया है जबकि उसने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में ऐसा प्रकट कार्य उसके द्वारा किया गया बताया। किंतु उसके संपूर्ण परिसाक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि वह हमले का शिकार व्यक्ति था। भाग्यवश वह बच गया। अतः उसे सर्वोत्तम प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य माना जाना चाहिए। न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय छुटपुट विसंगतियों को सम्यक् महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसी विसंगतियों को अस्वीकार किया जा सकता है। जो अभिकथन कथन के आधारभूत बयान को अस्थिर नहीं करते। ऐसी विसंगतियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो अवधारणा या संप्रेक्षण की सामान्य त्रुटियों के कारण है। याददाश्त खो जाने की त्रुटियों को सम्यक् महत्व दिया जाना चाहिए। न्यायालयों को विभिन्न मामलों के व्यक्तियों और विषयों के व्यापक अनुभव की सहायता से किसी साक्ष्य द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए बयान को अपवर्जित कर अभिलेख की सम्पूर्ण सामग्री को मूल्यांकन करना चाहिए। जब ऐसे साक्षी द्वारा अभिकथित कतिपय तथ्यों की बाबत संदेह पैदा होता है तो जब तक वह मामले की जड़ तक नहीं जाया जाए जो संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन को नष्ट करता हो। आजकल साक्षी सम्भवतः अपने परिसाक्ष्य को न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने के भय से अपने बयान को अलंकृत कर बताते हैं। तथापि, न्यायालयों को कुल मिलाकर ऐसे साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास नहीं करना चाहिए यदि वह अन्यथा विश्वसनीय है। सोहराब और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (1972 क्रिमिनल ला जर्नल 1302) वाले मामले में न्यायालय की ओर से निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति जगमोहन रेड्डी ने इस प्रकार मत व्यक्त किया -

इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक बात में

मिथ्या तो सब में मिथ्या इसका इस कारण आधारीक नियम नहीं है कि मुश्किल से ऐसा कोई साक्षी है जिसके साक्ष्य में असत्यता या किसी हद तक अतिशयोक्ति, अलंकरण या सजावट का पुट न हो । अधिकांश मामलों में ऐसे साक्षियों से जब ब्यौरे बताने के लिए कहा जाता है तो कुछ ऐसा उत्तर देते हैं जो निश्चित ही आवश्यक सही या सुसंगत नहीं होता है । इस भय से कि उनका साक्ष्य मुख्य घटना की बाबत अस्वीकार न किया जाए जिसके बारे में उन्होंने साक्ष्य दिया है किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि सतर्कतापूर्ण समीक्षा के पश्चात् मामले के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में उनके साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

14. भारवदा भोगिनभाई हिरजीभाई **बनाम** गुजरात राज्य वाले मामले में न्यायमूर्ति एम. पी. ठक्कर ने यह मत व्यक्त किया –

ऐसा साक्षी जो पूर्णतया सच्चा है वह न्यायालय के वातावरण और काउंसेल द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा से आतंकित होने का दायी है घबराहट के कारण घटनाओं के क्रम के बारे में भ्रमित हो जाता है, तथ्यों को मिश्रित कर देता है और तत्काल कल्पना से ब्यौरे बताने लगता है । साक्षी को मूर्ख दिखने या विश्वास न किए जाने के भय के कारण साक्षी का अवचेतन मस्तिष्क कभी-कभी ऐसा क्रियात्मक होता है यद्यपि साक्षी अपने द्वारा देखी गई घटना का सही और ईमानदार लेखा प्रस्तुत कर रह है – संभवतः यह तत्काल मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र की रीति है ।

ऐसी विसंगति जो मामले की जड़ तक नहीं जाती और साक्षियों के आधारभूत बयान को अस्थिर करती है, को असम्यक् महत्व नहीं दिया जा सकता । इसके अतिरिक्त, जब सभी महत्वपूर्ण 'सम्भाव्य कारक' साक्षियों द्वारा वर्णित बयान के पक्ष में प्रतिध्वनित होते हैं ।”

32. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व लिखाई गई, को इस कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित घटना का समय प्रातः लगभग 8.00 बजे है । चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रातः 9.05 बजे तैयार की गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् क्षतिग्रस्त साक्षियों को जिला

अस्पताल भेजा गया और उनकी परीक्षा प्रातः 9.30 बजे और 9.45 बजे की गई। क्षतिग्रस्त साक्षियों का यह कथन है कि वह पहले पुलिस थाने गए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और तब चिकित्सीय परीक्षा के लिए पत्र के साथ पुलिस द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया। मृत्यु समीक्षा में वर्णित चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का समय प्रातः 9.05 बजे है। मृत्यु समीक्षा के आरंभ का समय प्रातः 10.15 बजे और पूरा होने का समय 11.15 बजे उल्लिखित है। इस प्रकार घटनाओं के क्रम में कोई गायब कड़ी नहीं है तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित समय यह इंगित नहीं करता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व की है। इत्तिलाकर्ता और अन्य क्षतिग्रस्त साक्षियों पर अन्वेषक अधिकारी के कथनों में संगति है कि क्षतिग्रस्त साक्षी पहले पुलिस थाने गए और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और तब चिकित्सा परीक्षा के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के लिए क्षतिग्रस्त साक्षियों के साथ चिकित्सालय को भेजे गए पत्र में मात्र इस कारण कि इसमें अपराध संख्या का उल्लेख नहीं था, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व है।

33. उच्चतम न्यायालय ने राजेश उर्फ राजू चन्दू लाल गांधी और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य¹, राधा मोहन सिंह उर्फ लाल साहेब और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य² और ब्रह्म स्वरूप और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य³ वाले मामलों में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की विसंगतियों और लोपों की चर्चा की और यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी विसंगतियां या लोप अभियोजन को न्यायालय से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और ऐसे लोप से निश्चय ही यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व है।

34. जयश्री यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य⁴ वाले मामले के पैराग्राफ 16 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां मरणोत्तर परीक्षा करने के लिए अन्वेषक अधिकारी द्वारा चिकित्सक को भेजी गई अध्यक्षता में सभी विशिष्टियां नहीं लगी हों वहां अभियुक्त के विद्वान् काउंसिल की यह दलील कि जब शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया तब अन्वेषक

¹ (2002) 4 एस. सी. सी. 426.

² (2006) 2 एस. सी. सी. 450.

³ (2011) 6 एस. सी. सी. 288.

⁴ (2005) 9 एस. सी. सी. 788.

अधिकरण को मामले की जानकारी नहीं थी । यह अभिनिर्धारित किया गया :-

“हम यह नहीं समझते कि यह लोप, यदि कोई है, से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय पूर्व है । विधि का यह स्थिर सिद्धांत है कि यद्यपि मृत्यु समीक्षा कार्यवाहियों के दौरान एकत्रित जानकारी का सार देना है और मरणोत्तर परीक्षा कर रहे चिकित्सक को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उपलब्ध सामग्री देना आवश्यक है फिर भी उपरोक्त उक्त दस्तावेजों में यथाअन्तर्विष्ट सभी विशिष्टियां देना आवश्यक नहीं हैं । यह महेन्द्र राय **बनाम** मिथिलेश राय और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है ।”

35. इसके अलावा यह तथ्य कि मृत्यु समीक्षा पर अन्वेषक अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है इस कारण अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है । मृत्यु समीक्षा के 2 अन्य साक्षी अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7 जिन्होंने शपथ पर यह कहा कि वे लोग उपस्थित थे और मृत्यु समीक्षा पर हस्ताक्षर किए जो अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार की गई थी । फिर भी मृत्यु समीक्षा का प्रयोजन निरीक्षण के समय मृतक के शव की दशा को सुनिश्चित करना है । पंच साक्षियों और 2 कांस्टेबल अर्थात् अभि. सा. 7 और अभि. सा. 4 के हस्ताक्षर मृत्यु समीक्षा पर हैं ।

36. हत्या हथियार “उस्तरा” की बरामदगी अपीलार्थी के इशारे पर हुई थी । बरामदगी को खुले स्थान से किया गया नहीं कहा जा सकता क्योंकि “उस्तरा” को खुले स्थान पर घास और कूड़े के नीचे छिपाया पाया गया था जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रकट किया गया यद्यपि इसे 4 बिजली के खंभों के बीच पारपुल के नीचे खुला स्थान बताया गया । क्योंकि अपीलार्थी अपने प्रकटन कथन में वर्णित निर्दिष्ट स्थान का अन्वेषक अधिकारी को ले गया तथा रक्त-रंजित “उस्तरा” बरामद किया गया जो नीचे छिपाया गया था इसलिए इसे खुले स्थान से की गई बरामदगी नहीं कही जा सकती । अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श क-5 के रूप में तैयार और चिह्नित किया गया था । इसके परिशीलन से अभियुक्त अपीलार्थी के कथन से उस्तरा हथियार की बरामदगी को उसके द्वारा छिपाए जाने और पता चलने का तथ्य उपदर्शित होता है । अभियुक्त द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर बरामदगी पर विचार करते हुए **तेजाराम** (पूर्वोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां अभियुक्त द्वारा दी गई

जानकारी की सहायता से कूड़े के नीचे से कुल्हाड़ी बरामद की गई थी वहां सामान्यतः उपरोक्त परिस्थितियों पर पारिस्थितिक साक्ष्य के मूल्यांकन के समय अधिक महत्व दिया जाना चाहिए ।

37. इसके आगे सीरम विज्ञानी रिपोर्ट में वियोजित रक्त पाए जाने का यह अर्थ नहीं है कि कुल्हाड़ी पर टिका रक्त कतई मानव रक्त नहीं हो सकता है ।

38. **सुनील क्लिफोर्ड डैनियल** बनाम **पंजाब राज्य**¹ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि बरामद वस्तु पर पाए गए रक्त वियोजित थे । विभिन्न न्यायालयों पर विचार करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 46 में यह मत व्यक्त किया जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

“उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा इस निवेदन को स्वीकार करना असंभव है कि रक्त के उद्भव से संबंधित रिपोर्ट के अभाव में अभियुक्त को इस मताभिव्यक्ति पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता कि समय के मात्र व्यपगत हो जाने के कारण भी रक्त के वर्गीकरण का अवधारण नहीं किया जा सकता । अतः अभियुक्त को किसी फायदे का दावा करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए कोई लाभ नहीं दिया जा सकता और रक्त आदि के वियोजन की रिपोर्ट को गायब कड़ी के रूप में नहीं कहा जा सकता जिसके आधार पर परिस्थितियों के कड़ी को टूटा हुआ अवधारित किया जाए ।

39. उक्त निष्कर्ष पर पहुंचते हुए **तेजाराम** (पूर्वोक्त) वाले मामले पर भी विचार किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सीरम के वियोजन और हथियार पर मानव रक्त की उपस्थिति के बारे में विनिर्दिष्ट रूप के अभाव में यह कल्पना नहीं की जा सकती कि रक्त का उद्भव किसी अन्य से हुआ होगा ।

40. दंड न्यायालय का प्रयास कल्पनात्मक संदेहों को खोजते रहना नहीं होना चाहिए जब तक संदेह का युक्तियुक्त आयाम न हो और न्यायिकतः विवेक सम्मत व्यक्ति इसे कुछ हद तक वास्तविक मानता हो, अभियुक्त द्वारा किसी फायदे का दावा नहीं किया जा सकता ।

41. इस मामले में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपराध कारित

¹ (2012) 11 एस. सी. सी. 205.

करने का ठोस हेतु था। यद्यपि अपीलार्थी ने घटना के लगभग 2 वर्ष पूर्व अपनी पूर्व पत्नी शन्नो का विवाह-विच्छेद कर दिया था और अलग-अलग रह रहा था फिर भी वह इत्तिलाकर्ता के मकान पर विवाह-विच्छेद के पश्चात् उत्पन्न अपनी पुत्री की अभिरक्षा पर जोर दे रहा था। स्वीकार्यतः उनके विवाह-बंधन से उत्पन्न 3 बच्चे अपीलार्थी के साथ रह रहे थे। इस प्रकार हेतु के अस्तित्व की बाबत संदेह की थोड़ी संभावना है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुतः अपीलार्थी किसी भी हालत में अपनी पुत्री को वापस लेना चाहता था।

42. उसकी पत्नी शन्नो का घोर विरोध था और वह अपनी लड़की रूबी की अभिरक्षा देने के लिए तैयार नहीं थी। इसके कारण, घटना के पूर्व उनके बीच कुछ कहासुनी हुई थी।

43. उच्चतम न्यायालय सुनील क्लिफोर्ड डैनियल (पूर्वोक्त) वाले मामले में सुरेश चन्द्र बाहरी बनाम बिहार राज्य¹ वाले मामले पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार किया कि अभिलेख का संपूर्ण साक्ष्य यह इंगित करता है कि अपीलार्थी के पास अपराध करने का पर्याप्त आवश्यक हेतु है।

44. बचाव पक्ष का यह सुझाव है कि इत्तिलाकर्ता चरित्रहीन प्रकृति की थी और पड़ोसियों द्वारा यह शिकायत की गई थी कि वह अपनी दो पुत्रियों के साथ वेश्यावृत्ति में लिप्त थी, अतः मकान की तीन महिलाओं के किसी उपभोक्त द्वारा अपराध किए जाने की ठोस संभावना है। उक्त सुझाव दूरस्थ संभाव्यता है और उक्त कथन करने का कोई आधार नहीं है। अभिलेख पर साक्ष्य से अन्यथा भी यह है कि घटना प्रातः लगभग 8 बजे हुई जैसा कि इत्तिलाकर्ता द्वारा कहा गया है। पड़ोसी मृतका और क्षतिग्रस्त की चीख पुकार सुनकर घटनास्थल पर आए यद्यपि कोई व्यक्ति ऐसा कथन करने के लिए सामने नहीं आया। एक पड़ोसी अभि. सा. 1 यद्यपि उसने अपनी परीक्षा में यह कहा कि उसने मृतक की गर्दन पर क्षति के साथ सड़क पर रक्त से सना हुआ पाया जब वह घटनास्थल पर दौड़ कर आई। तथापि, वह पक्षद्रोही हो गई और यह कहा कि उसने अपीलार्थी या उसके भाई को घटनास्थल पर नहीं देखा। घटना इत्तिलाकर्ता के रिहायशी मकान पर हुई और सर्वाधिक स्वाभाविक साक्षी मकान के निवासी हैं। मात्र इस कारण कि कुछ स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गए और अभियोजन मामले

¹ (1995) 1 एस. सी. सी. 80.

का समर्थन नहीं किया। न्यायालय अभियोजन को फटकार नहीं सकता क्योंकि किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा करना संभव नहीं जिन्होंने घटना को देखा था। सामान्यतः पड़ोसी और अन्य स्वतंत्र साक्षी ऐसे मामलों में सामने नहीं आते। हमारा यह अनुभव रहा है कि लोग सामान्यतः असंवेदनशील होते हैं चाहे अपराध उनकी उपस्थिति में ही हुआ हो। वे स्वयं को न्यायालय से दूर रखते हैं जब तक ऐसा अनिवार्य हो। किंतु अभियोजन पक्षकथन को अकेले इस आधार पर भी तिरस्कृत या संदेहास्पद नहीं ठहराया जा सकता। **अप्पाभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य** (पूर्वोक्त) वाला मामला देखिए।

45. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील कि घटना रात के समय हुई थी न कि 2 सितंबर, 1997 को प्रातःकाल से संबंध है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त दलील का आधार अभि. सा. 3 डा. टी. आर. शर्मा जिन्होंने मरणोत्तर परीक्षा की, का कथन है। अपनी प्रतिपरीक्षा में चिकित्सक ने यह प्रस्तुत किया है क्योंकि शव काठिन्य मृतक के ऊपरी भाग पर था अतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के वर्णित समय के 6 घंटे पूर्व घटना के होने की संभावना थी। अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के आवेदन पर विचार करते हुए हम मोदीकृत चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान पुस्तक 23 वां संस्करण के सुसंगत भाग को निर्दिष्ट कर रहा हूं जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

“स्वाभाविकतः मांसपेशियां में, शव काठिन्य निश्चित अनुक्रम में होता है। यह सबसे पहले पुतलियों के मांसपेशियों में, उसके बाद गर्दन और निचले जबड़े के पीछे मांसपेशियों में और तब गर्दन, चेहरा, छाती और ऊपरी अग्रगों के सामने वाले भाग में होता है और अंततः पेट निचले अग्रगों के मांसपेशियों के नीचे की ओर होता है।”

46. **मांगू खान बनाम राजस्थान राज्य**¹ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैरा 8 में यह मत व्यक्त किया कि :-

“ऐसा समय दर्शित करने के लिए कि न्यायालयिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रति निर्देश द्वारा दी गई दलील जिसके भीतर शव काठिन्य संपूर्ण शरीर पर विकसित होता हो, का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। यह मृतक की शरीर रचना, वर्ष का मौसम, क्षेत्र का

¹ (2005) 10 एस. सी. सी. 374.

तापमान और ऐसी स्थिति जिसमें शरीर को रखा गया है जैसे भिन्न कारकों पर निर्भर करती है। अभिलेख से यह उपदर्शित होता है कि शव को शव-गृह से प्राप्त किया गया था। हमने यह ध्यान दिया कि चिकित्सक से किसी प्रकार की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई जिससे ऐसे किसी सारवान् तथ्य को प्रकाश में लाया जाए इसके जिस पर संभाव्य तर्क आधारित हो सके। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं, स्वयं सारे शरीर पर शव काठिन्य उपस्थिति के आधार पर विद्वान् काउंसेल इस तर्क की उपेक्षा नहीं हो सकती कि मृत्यु पिछली रात के दौरान हुई होगी। स्वीकार्य प्रत्यक्ष साक्ष्य को ऐसे कल्पनात्मक आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता जिसके लिए कोई उचित आधार दिए गए हों।¹

47. फिर भी यह स्थिर विधिक प्रतिपादना है कि प्रत्येक साक्ष्य को तब तक प्राथमिकता दी जाएगी जब तक उपलब्ध मौखिक साक्ष्य बिल्कुल चिकित्सा साक्ष्य से असुधार्य न हो। किसी साक्षी के प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य की तुलना में अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य होगा और जब चिकित्सा साक्ष्य मौखिक परिसाक्ष्य को असंभाव्य ठहराता हो तो यह ऐसे साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुसंगत कारक होता है। जब दोनों के बीच विरोध इतना अधिक हो कि चिकित्सा साक्ष्य पूर्णतया प्रत्यक्ष साक्ष्य को कतई सत्य होने की पूरी संभावना से इनकार करता हो तो प्रत्यक्ष साक्ष्य अविश्वास किए जाने योग्य है।

48. जहां तक चिकित्सक की राय का संबंध है कि घटना प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के वर्णित समय अर्थात् प्रातः 8.00 बजे से पूर्व 6 घंटे पहले हुई होगी और अपीलार्थी का यह सुझाव है कि यह रात में हुई का यह अर्थ नहीं है कि डा. टी. आर. शर्मा अभि. सा. 3 मृत्यु का सही समय नियत करने में समर्थ था।

49. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में विचार किया गया और विनिश्चय किया गया। **बासो प्रसाद बनाम बिहार राज्य¹, राकेश और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य², दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य³, उमेश सिंह बनाम बिहार राज्य⁴** वाले

¹ (2006) 13 एस. सी. सी. 65.

² (2011) 9 एस. सी. सी. 698.

³ (2012) 10 एस. सी. सी. 476.

⁴ (2013) 4 एस. सी. सी. 360.

मामलों का निर्देश किया जा सकता है ।

50. इस मामले में चिकित्सक ने स्वयं द्वारा की गई मरणोत्तर परीक्षा के आधार पर ही यह सुझाव दिया कि घटना का समय प्रातः 8.00 बजे से पूर्व हो सकता है ।

51. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, घटना लगभग प्रातः 8.00 बजे के आस-पास हुई । क्षतिग्रस्त असगरी और शन्नो पुलिस थाने गए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक द्वारा उनकी परीक्षा की गई । स्वयं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हेतु को भी प्रकट किया गया था । अतः यह असंभाव्य है कि अपीलार्थी को निश्चित रूप से फंसाया गया है क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने की तत्परता से यह दर्शित होता है कि छल साधन का कोई समय नहीं था ।

52. इसके अतिरिक्त यह समझ में आता है कि क्षतिग्रस्त साक्षी अपीलार्थी को मिथ्या रूप से क्यों फंसाएंगे जब उसने पहले ही शन्नो को तलाक दे दिया था और वह घटना होने से लगभग 2 वर्ष पहले से अलग रह रहा था और वास्तविक दोषी को मुक्त हो जाने देंगे ।

53. दोनों क्षतिग्रस्त साक्षियों के कथन में कोई विसंगति नहीं है और साक्षियों के बयानों में जब उन्होंने विस्तार से बताया कुछ छुटपुट विसंगतियां हैं तो जब तक विरोध तात्त्विक विषयों पर न हो तब तक समग्रता साक्षियों को अस्वीकार करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

54. अन्य परिस्थितियों विशेषकर मृतका के शरीर पर पहुंचाई गई क्षतियों की प्रकृति, अभियुक्त की गिरफ्तारी, हथियार की बरामदगी, उसके प्रकटन कथन, अभियोजन पक्षकथन को साबित करती हैं । क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों पर विश्वास न होने का कोई कारण नहीं है ।

55. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल का यह कमज़ोर प्रयास है कि यह ऐसा मामला है जहां अपीलार्थी यदि कोई, द्वारा अपराध किया गया बताया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के परे नहीं जाता क्योंकि यह अचानक प्रकोपन का मामला था और अपीलार्थी का अपराध करने का कोई आशय नहीं था ।

56. उक्त संस्वीकृति का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी अपने साथ उस्तरा लिए हुए था जब वह शन्नो से मिलने गया और फिर भी उसने शन्नो पर ही हमला नहीं किया किंतु दो अन्य व्यक्तियों पर भी हमला किया जो उसे बचाने के लिए आए । वह शब्बो जो घटनास्थल पर ही मर गई पर गंभीर क्षतियां कारित करने के पश्चात् भाग गया । अपने साथ हथियार लिए रहने के तथ्य से स्पष्टतया यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी किसी भी कीमत पर हमेशा के लिए विवाद को सुलझाने का आशय रखता था ।

57. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हम इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलार्थी अपराध करने का दोषी है जिसके लिए इसे आरोपित किया गया है । हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते । अपील सारहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है ।

58. कठोर आजीवन कारावास से अभियुक्त अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट करने वाले निर्णय और आदेश तारीख 15 फरवरी, 2007 को अभिपुष्ट किया जाता है । अभियुक्त अपीलार्थी परवेज़ कारागार में है । उसे विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत और हमारे द्वारा अभिपुष्ट दण्डादेश को भुगतने के लिए वहां रखा जाए ।

59. निर्णय की प्रमाणित प्रति को 1 सप्ताह के भीतर भेजा जाए । मामले के अभिलेख को भी तत्काल निचले न्यायालय को भेजा जाए । इस आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर सहारनपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए ।

अपील खारिज की गई ।

पां.

विजय वासंत सावंत (श्रीमती)

बनाम

सुश्री शुभांगी शिवलिंग परब और अन्य

तारीख 1 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति श्रीमती आर. पी. सौन्दरबलदोता

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधि अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 19 – संरक्षण आदेश – जहां परिवादी-पत्नी द्वारा अपने पति और सास-ससुर के विरुद्ध उत्पीड़न और दहेज मांग से संबंधित अभिकथन वर्ष 2008 में पति द्वारा विवाह-विच्छेद अर्जी फाइल करने के पश्चात् किए गए तथा पत्नी के सभी अभिकथन सितंबर, 2004 जब से वह अपने ससुराल में नहीं रह रही है, से चार वर्ष पूर्व के हैं और अस्पष्ट तथा सतही हैं तथा समस्त दृष्टांत वर्ष 2004 का है जबकि अधिनियम, 2006 में प्रवर्तित हुआ, वहां परिवादी द्वारा फाइल किया गया परिवाद अस्वीकार किए जाने योग्य है।

याची ने अपने पति और प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4, जो उसकी सास ननद और देवर हैं, के विरुद्ध पोंडा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 2005 के घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अधीन 2009 का दांडिक मामला संख्या 150/डी. वी. ए. फाइल किया। उसने प्रत्यर्थियों और अपने पति को उसके और उसके बच्चे के विरुद्ध किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित करने, उनको बेदखल करने, बोरीवली स्थित उसकी ससुराल में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करने, उसको सूचित किए बिना बोरीवली स्थित उसके आवासीय घर (वैवाहिक घर) को हस्तांतरित या ऋणग्रस्त करने और प्रत्यर्थी संख्या 2 की अभिरक्षा वाले उसके जेवरात बेचने या उनको बंधक रखने से निषिद्ध किए जाने और धारा 19 के अधीन संरक्षण आदेश पारित किए जाने के लिए आवेदन फाइल किया। उसने अपने बच्चे की अभिरक्षा भी चाही। वह स्वीकृत रूप से अपने पति से पृथक् होकर रह रही है। पति ने विवाह-विच्छेद के लिए वर्ष 2008 में याचिका फाइल की थी। याची ने उसके लगभग एक वर्ष पश्चात् अर्थात् तारीख 16 फरवरी, 2009 के अपने पति और इसमें के प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल किया। विचारण न्यायालय ने तारीख 13 मई, 2009 के आदेश द्वारा आवेदन यह

अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकृत कर दिया कि याची द्वारा फाइल किए गए परिवाद के आधार पर प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है और आवेदन के माध्यम से दी गई दलील विचारण के समय याची के पक्षकथन के खण्डन में दी जा सकती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने सेशन न्यायालय के समक्ष 2009 की दांडिक अपील संख्या 89 फाइल करते हुए आवेदन को अस्वीकृत करने वाले आदेश को चुनौती दी। इस अपील को तारीख 6 मार्च, 2010 के आदेश द्वारा दांडिक पुनरीक्षण आवेदन द्वारा स्वीकार किया गया। इस आदेश को वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन द्वारा आक्षेपित किया गया। दांडिक पुनरीक्षण आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – सेशन न्यायालय ने अपने सुविचारित आदेश में उल्लेख किया है कि याची द्वारा इस मामले में फाइल किया गया परिवाद वर्ष 2008 में पति द्वारा फाइल की गई विवाह-विच्छेद कार्यवाही फाइल किए जाने के पश्चात् फाइल किया गया था। आवेदन में किए गए अनेक अभिकथन अस्पष्ट हैं और उनमें प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के विरुद्ध उत्पीड़न का प्रकट रूप से कोई कार्य समाविष्ट नहीं है। ये अभिकथन प्रत्यर्थी संख्या 1 के उकसाने और पति द्वारा याची का उत्पीड़न किए जाने और उससे दहेज की मांग किए जाने तक सीमित है। सेशन न्यायालय ने यह उल्लेख भी किया कि अभिकथित समस्त दृष्टांत सितंबर, 2004 के पूर्व की अवधि से संबंधित हैं जब याची ने अपने वैवाहिक घर को छोड़ा था। उसके पश्चात् का किसी भी प्रकार का कोई भी अभिकथन नहीं है। उसका (सेशन न्यायालय का) विचार है कि यद्यपि अधिनियम वर्ष 2006 में प्रवर्तित हुआ था, तब भी याची को अधिकार था कि वह सिविल या दांडिक कार्यवाहियों के माध्यम से सामान्य विधि के अधीन कार्यवाही का अवलंब लेती। इसके अलावा, परिवाद फाइल किए जाने में तीन वर्ष के विलंब का याची द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रकटतः, परिवाद फाइल किया जाना पति द्वारा आरंभ की गई विवाह-विच्छेद कार्यवाही का प्रत्याक्रमण (जवाबी हमला) था। परिवाद के परिशीलन से सेशन न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए इस विचार को बल मिलता है कि परिवाद में समाविष्ट अभिकथन अस्पष्ट है और आवश्यक विवरणों द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, याची परिवाद फाइल किए जाने के पूर्व अपने पति से चार वर्षों से अधिक समय से अलग होकर रह रही थी और विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया। जहां तक बोरीवली में प्रत्यर्थी संख्या 1 के स्वामित्व वाले मकान पर याची द्वारा किए गए दावे का संबंध है, सेशन न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि याची का

उस मकान पर कोई दावा नहीं हो सकता । चूंकि स्वयं उसके पति का ही उस मकान पर कोई अधिकार नहीं था । किसी भी लघु अवधि के लिए कोई भी निवास जो याची के कब्जे में उस मकान में था, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञा के कारणवश था । (पैरा 4 और 5)

दांडिक पुनरीक्षण अधिकारिता : 2011 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 41.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन आवेदन ।

याची की ओर से

सुश्री सी. कोल्लेस्सो

प्रत्यर्थियों की ओर से

सुश्री एम. पिंटो, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति श्रीमती आर. पी. सौन्दरबलदोता – इस मामले का पुनरीक्षणकर्ता याची दांडिक मामला संख्या 150/डी. वी. ए./2009 में परिवादी है जिसको उसके पति और इस मामले के प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध पोंडा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 2005 के घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (जिसको इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 12 के अधीन फाइल किया गया है । ये प्रत्यर्थी हैं उसकी सास, ननद और देवर । उसने प्रत्यर्थियों और अपने पति को उसके और उसके बच्चे के विरुद्ध किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित करने से निषिद्ध किए जाने और उसको बेदखल करने से निषिद्ध करने या बोरीवली स्थित उसके ससुराल घर में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करने से निषिद्ध किए जाने और साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 2 को उसको सूचित किए बिना बोरीवली स्थित उसके आवासीय घर (वैवाहिक घर) को हस्तांतरित करने या उसको ऋणग्रस्त करने से निषिद्ध किए जाने, प्रत्यर्थी संख्या 2 की अभिरक्षा वाले उसके जेवरतों को बेचे जाने या उनको बंधक रखे जाने से निषिद्ध किए जाने और उनको लौटाए जाने के प्रयोजनार्थ धारा 19 के अधीन संरक्षण आदेश पारित किए जाने के लिए आवेदन भी फाइल किया है । उसने अपने बच्चे की अभिरक्षा भी चाही है । यह स्वीकार किया गया है कि पुनरीक्षण याची अपने पति जो प्रस्तुत याचिका में तारीख 1 अप्रैल, 2004 से याची नहीं है, से पृथक् होकर रह रही है । पति ने वर्ष 2008 में विवाह-विच्छेद के लिए याचिका फाइल की थी । याची ने उसके लगभग एक वर्ष पश्चात् अर्थात् तारीख 16 फरवरी, 2009 को अपने पति और इसमें के प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल किया । इस अवधि के दौरान पारित आदेशों द्वारा पति द्वारा फाइल की गई

विवाह-विच्छेद की याचिका याची और उसके पति के मध्य विवाह बंधन समाप्त करने वाला आदेश पारित करते हुए स्वीकार की जा चुकी है ।

2. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने यह दलील देते हुए कि परिवार में उनके विरुद्ध किए गए अभिकथन अस्पष्ट हैं और परिवार चालू रखे जाने को न्यायसंगत नहीं ठहराते, उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ आवेदन फाइल किया गया जो प्रदर्श-6 है । जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 का संबंध है, उनके विरुद्ध एकमात्र यह अभिकथन किया गया है कि याची के पति और सास ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के उकसाने पर उसका उत्पीड़न किया था । विचारण न्यायालय के समक्ष यह दलील भी दी गई कि प्रत्यर्थियों के विरुद्ध परिवार का चालू रहना याची द्वारा विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा । यह दलील भी दी गई थी कि चूंकि याची वर्ष 2004 से अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों से पृथक् होकर रह रही है, कोई संरक्षण आदेश पारित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक याची के बोरीवली स्थित मकान, जो कि एक साझा मकान, जैसाकि अधिनियम के उपबंधों द्वारा अनुध्यात है, का संबंध है, प्रत्यर्थियों ने दलील दी कि यह मकान अनन्य रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1, जो कि सास है, का है । इसके अलावा क्योंकि याची उस मकान से हट चुकी है, इसको साझा मकान नहीं कहा जा सकता । विचारण न्यायालय ने अपने तारीख 13 मई, 2009 के आदेश द्वारा आवेदन, जो प्रदर्श 6 है, यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकृत कर दिया कि इसमें के याची द्वारा फाइल किए गए परिवार के आधार पर प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है और आवेदन के माध्यम से दी गई दलील विचारण के समय याची के पक्षकथन के खंडन में दी जा सकती है । प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने सेशन न्यायालय के समक्ष 2009 की दांडिक अपील संख्या 89 फाइल करते हुए आवेदन को अस्वीकृत करने वाले आदेश को चुनौती दी । इस अपील को तारीख 6 मार्च, 2010 के आदेश, जिसको वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन द्वारा आक्षेपित किया गया है, द्वारा स्वीकार कर लिया गया ।

3. दोनों पक्षों के काउंसिलों की सहायता से विचारण न्यायालय के आदेश, जो इस दांडिक पुनरीक्षण आवेदन का प्रदर्श-6 है और उसके विरुद्ध सेशन न्यायालय में फाइल की गई अपील में पारित आदेश और साथ ही याची द्वारा फाइल किए गए परिवार का भी परिशीलन किया ।

4. सेशन न्यायालय ने अपने सुविचारित आदेश में उल्लेख किया है कि याची द्वारा इस मामले में फाइल किया गया परिवार वर्ष 2008 में पति

द्वारा फाइल की गई विवाह-विच्छेद कार्यवाही फाइल किए जाने के पश्चात् फाइल किया गया था। आवेदन में किए गए अनेक अभिकथन अस्पष्ट हैं और उनमें प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के विरुद्ध उत्पीड़न का प्रकट रूप से कोई कार्य समाविष्ट नहीं है। ये अभिकथन प्रत्यर्थी संख्या 1 के उकसाने और पति द्वारा याची का उत्पीड़न किए जाने और उससे दहेज की मांग किए जाने तक सीमित है। सेशन न्यायालय ने यह उल्लेख भी किया कि अभिकथित समस्त दृष्टांत सितंबर, 2004 के पूर्व की अवधि से संबंधित हैं जब याची ने अपने वैवाहिक घर को छोड़ा था। उसके पश्चात् का किसी भी प्रकार का कोई भी अभिकथन नहीं है। उसका (सेशन न्यायालय का) विचार है कि यद्यपि अधिनियम वर्ष 2006 में प्रवर्तित हुआ था, तब भी याची को अधिकार था कि वह सिविल या दांडिक कार्यवाहियों के माध्यम से सामान्य विधि के अधीन कार्यवाही का अवलंब लेती। इसके अलावा, परिवाद फाइल किए जाने में तीन वर्ष के विलंब का याची द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रकटतः, परिवाद फाइल किया जाना पति द्वारा आरंभ की गई विवाह-विच्छेद कार्यवाही का प्रत्याक्रमण (जवाबी हमला) था।

5. परिवाद के परिशीलन से सेशन न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए इस विचार को बल मिलता है कि परिवाद में समाविष्ट अभिकथन अस्पष्ट हैं और आवश्यक विवरणों द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, याची परिवाद फाइल किए जाने के पूर्व अपने पति से चार वर्षों से अधिक समय से अलग होकर रह रही थी और विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया। जहां तक बोरीवली में प्रत्यर्थी संख्या 1 के स्वामित्व वाले मकान पर याची द्वारा किए गए दावे का संबंध है, सेशन न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि याची का उस मकान पर कोई दावा नहीं हो सकता। चूंकि स्वयं उसके पति का ही उस मकान पर कोई अधिकार नहीं था। किसी भी लघु अवधि के लिए कोई भी निवास जो याची के कब्जे में उस मकान में था, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञा के कारणवश था।

6. इन तथ्यों पर संपूर्णता में विचार करते हुए मेरा मत है कि सेशन न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए आक्षेपित आदेश पारित करके ठीक किया। इसलिए, पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया।

शु.

सचिन विट्ठल बोरहडे और एक अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

तारीख 11 जून, 2013

न्यायमूर्ति श्रीमती वी. के. ताहिलरमणी और न्यायमूर्ति पी. डी. कोडे

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – मृतका का यह कथन कि दोनों अभियुक्तों ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ोला और आग लगा दी और मृतका द्वारा अपनी माता को किया गया मौखिक मृत्युकालिक कथन कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और सास ने उसकी मृत्यु कारित की, कथन को सत्य, भरोसेमंद और स्वैच्छिक पाते हुए, अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायोचित और तर्कसंगत है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – मृतका द्वारा अपने मृत्युकालिक कथन में स्पष्ट किया जाना कि उसके पति और ससुर ने उसको जलाया – अन्य साक्षियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किया जाना कि मृतका को निरंतर उत्पीड़न और क्रूरता के अधीन रखा गया – यह सोचसमझकर किया गया अपराध है – विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को आजीवन कारावास द्वारा दंडित किया जाना उचित है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 – हत्या – वध करने के आशय से अचानक झगड़ा किया जाना – मृतका के पति द्वारा मृतका के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट किया जाना – उसके द्वारा किसी पराए व्यक्ति के घर में आने-जाने का प्रकटीकरण और यह घोषणा किया जाना कि वह मृतका के गर्भस्थ शिशु का पिता नहीं है – अभियुक्तों द्वारा मृतका की हत्या अकस्मात् प्रकोपनवश नहीं बल्कि सुनियोजित थी ।

मृतका का यह कथन कि दोनों अभियुक्तों ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ोला और आग लगा दी और मृतका द्वारा अपनी माता को किया गया मौखिक मृत्युकालिक कथन कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और सास ने उसकी मृत्यु कारित की, चिकित्सक की यह राय कि मृतका कथन करने की ठीक दशा में थी,

अतः, मृत्युकालिक कथन को सत्य, भरोसेमंद और स्वैच्छिक पाते हुए, अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायोचित और तर्कसंगत है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि आशाबाई की पुत्री सारिका का विवाह पुणे के नारायण अरुडे के साथ तारीख 14 मई, 2004 को सम्पन्न हुआ था । तत्पश्चात् सारिका अपने पति और सास-ससुर के साथ रहने लगी । विवाह के दो-तीन माह पश्चात् सारिका के पिता-माता ने नव-विवाहित दम्पति को दीपावली के अवसर पर आमंत्रित किया । परन्तु सारिका के पति और ससुर ने कहा कि वे दीपावली के अवसर पर सारिका का उसके मायके तभी जाने देंगे जब सारिका के पिता-माता कम से कम डेढ़ तोले की सोने की चेन/अंगूठी देंगे । सारिका ने अपने पति और ससुर को बताया कि उसके पिता-माता इस प्रकार से जेवरात का खर्च वहन नहीं कर सकते । चूंकि उन्होंने पहले ही उसके विवाह के लिए कर्ज ले रखा है । इस पर सारिका के पति और ससुर ने उसको गालियां देना और पीटना आरंभ कर दिया । उन्होंने उसके गर्भस्थ शिशु के पैतृत्व के बारे में भी शंका करना आरंभ कर दिया । तारीख 21 फरवरी, 2005 को घटना घटित होने वाले सोमवार को सारिका के पक्ष के लोग खेत पर गए थे और उसका पति भी अपराह्न लगभग 1.30 बजे से खेत पर ही था । प्रातःकाल लगभग 4.30 बजे पड़ोस का एक लड़का मुकुंद बोराडे सारिका के पास आया और उसने मिसरी (दंत पाउडर) की मांग की । वह मिसरी लेने के लिए घर के भीतर तक चला आया था । जब सारिका का पति वापस लौटा तो मुकुंद वापस जाने वाला था । सारिका के पति ने संदेह व्यक्त करते हुए सारिका से मुकुंद के आने का कारण पूछा । उसने सारिका को गालियां दीं और देर रात्रि तक उससे झगड़ा करता रहा । मध्य रात्रि लगभग 1.30 बजे उसने सारिका को मुक्कों से पीटना आरंभ कर दिया । शोर सुनकर सारिका का ससुर आ गया और उसने झगड़े का कारण पूछा । सारिका के पति ने उसको अपनी अनुपस्थिति में मुकुंद के आने के बारे में बताया । उसने सारिका के चरित्र के बारे में संदेह व्यक्त किया और कहा कि वह उस बच्चे का पिता नहीं है जो सारिका के गर्भ में है । तत्पश्चात् सारिका के ससुर ने भी सारिका को भद्दी-भद्दी गालियां दीं और अपने पुत्र और सारिका के पति से कहा कि वह सारिका को समाप्त कर दे । सारिका के पति ने उसको पीटना आरंभ कर दिया । सारिका ने रसोई से बाहर जाने का प्रयास किया किंतु उन लोगों ने उसको पकड़ लिया । सारिका के पति ने कैरोसिन उठाया और उसके दोनों कंधों पर डाल दिया । उसके ससुर ने उसके ऊपर जलती हुई माचिस की तीली फेंक दी और

रसोई का दरवाजा बंद करके बाहर खड़ा हो गया। जब सारिका की साड़ी ने आग पकड़ी और उसको महसूस हुआ कि उसका शरीर जल रहा है तो उसने चिल्लाना शुरू किया। जब उसने रसोई से बाहर आने का प्रयास किया तो उसके पति ने उसको वापस भीतर धकेल दिया। सारिका को वाई. सी. एम. अस्पताल और तत्पश्चात् ससून अस्पताल ले जाया गया। पुलिस उप-निरीक्षक यादव ने अस्पताल का दौरा किया और डा. वेंकट से पूछा कि क्या सारिका होश में है और कथन करने की स्थिति में है। डा. वेंकट ने सारिका का परीक्षण करने के उपरांत मत व्यक्त किया कि वह होश में है और कथन करने की स्थिति में है। उप-निरीक्षक यादव ने सारिका के कथन के आधार पर उसके पति और ससुर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क सपठित धारा 34 के अधीन अपराध कारित किए जाने के बाबत 2005 की अपराध संख्या 28 रजिस्ट्रीकृत की। उसने सारिका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्रीमती शोभा देशमुख को भी सूचित किया। कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्रीमती शोभा देशमुख तुरंत अस्पताल गईं और सारिका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया। पुणे के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने 2005 के सेशन मामला संख्या 452 में तारीख 18 दिसंबर, 2007 के निर्णय और आदेश पारित करते हुए अपीलार्थियों को सारिका की हत्या कारित करने के अपराध के बाबत दोषसिद्ध किया। आजीवन कारावास और जुर्माने द्वारा दंडादिष्ट किया। विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई। अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा बरदाश्त की गई क्षतियों की प्रकृति के अभिलेख पर लाने के प्रयोजनार्थ प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि अभि. सा. 4 ने शपथपूर्वक कथन किया था कि उसने उसको चिकित्सीय परीक्षण के लिए राजगुरु नगर के ग्रामीण अस्पताल भेजा था, अपीलार्थी संख्या 1 के चिकित्सीय प्रमाणपत्र को अभिलेख पर लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह चिकित्सीय प्रमाणपत्र इस तथ्य पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डाल सकता था कि क्या अपीलार्थी संख्या 1 ने वास्तव में आग बुझाने का प्रयास किया था और क्या उक्त प्रक्रिया में उसको उक्त क्षतियां कारित हुई थीं। प्रतिरक्षा पक्ष का उक्त आचरण के कारण उनके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना अपेक्षित है चूंकि इस साक्ष्य को जानबूझकर अभिलेख पर

नहीं लाया गया । चूंकि वह प्रतिरक्षा पक्ष के प्रतिकूल हो जाती । हमारा यह विचार इसलिए है कि चूंकि अपीलार्थी संख्या 1 की घटना के दौरान कुछ मामूली क्षतियां बरदाश्त करने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अभिलेख सिवाय अपीलार्थी संख्या 1 के कोरे शब्द, इस बात का प्रकटीकरण नहीं करते कि उसने कुछ जल जाने वाली क्षतियां बरदाश्त की थीं । परिणामतः, न्यायालय उक्त निवेदन में कोई गुणागुण नहीं पाता । (पैरा 19.1)

मृत्युकालिक कथनों, जिनको न्यायालय सत्य, विश्वसनीय और स्वैच्छिक पाता है, में समाविष्ट सामग्री पर सतर्कतापूर्वक विचार करने के पश्चात् न्यायालय उपरोक्त निवेदनों में कोई बल पाने में असमर्थ हैं । अपीलार्थी संख्या 2 के संबंध में न्यायालय ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाता कि वह किसी झगड़े का पक्षकार था । यहां तक कि अपीलार्थी संख्या 1 के संबंध में भी न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि साक्ष्य के आधार पर दर्शित होता है कि आहत उसके साथ झगड़ा नहीं कर रही थी । वास्तविकता यह है कि उक्त मृत्युकालिक कथनों में समाविष्ट सामग्री के आधार पर स्पष्ट शब्दों में यह प्रकटीकरण होता है कि यह अवेक्षित करने के पश्चात् कि मुकुंद बोराडे घर से निकला जा रहा है, अपीलार्थी संख्या 1 ने मृतक के साथ लड़ाई-झगड़ा करना आरंभ कर दिया था और वह उससे पूरे दिन झगड़ता रहा था । आगे यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि उक्त झगड़ा अकरस्मात् हुआ झगड़ा नहीं कहा जा सकता । मृतक के साथ गाली-गलौज किए जाने और उसको पीटे जाने का कार्य निरंतर चलता रहता था, यह तथ्य न केवल मृत्युकालिक कथनों में, समाविष्ट तथ्यों से बल्कि अभि. सा. 1 के साक्ष्य से भी स्पष्ट है । दोहराते हुए न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि उक्त दिवस को घटित हुई घटना पर विचार करने के पश्चात् यह महसूस किया जाना कठिन है कि इस घटना से आहत झगड़ा कर रही थी । इसके अतिरिक्त वे मामले जिनका प्रकटीकरण मृत्युकालिक कथनों से होता है, ये हैं कि अपीलार्थी सं. 2 के उक्त स्थान पर आने और लड़ाई-झगड़े का कारण पूछने और अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा मुकुंद के आगमन के बारे में प्रकटीकरण किए जाने और यह घोषणा किए जाने के पश्चात् कि वह सारिका के गर्भ में पलने वाले बच्चे का पिता नहीं है, अपीलार्थी संख्या 2 ने उसको आहत को समाप्त कर देने के लिए उकसाया था । साक्ष्य से प्रकट होता है कि उन लोगों द्वारा आहत को पकड़ लिया गया था, कैरोसिन लाया गया था और अपीलार्थी संख्या 1 ने आहत के शरीर पर कैरोसिन डाला था और अपीलार्थी संख्या 2 ने आहत

के शरीर पर जलती हुई माचिस की तीली फेंकी थीं । इसके विपरीत मृत्युकालिक कथन प्रदर्श-20 से प्रकट होता है कि अपीलार्थी संख्या 2 रसोई के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा था और उसने रसोई के दरवाजे को बंद कर दिया था जिससे कि मृतक को रसोई से बाहर आने से रोका जा सके । इससे प्रकट होता है कि आग को आहत द्वारा रजाई का प्रयोग करके बुझाया गया था न कि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा । यह समस्त साक्ष्य निश्चित रूप से दर्शित करते हैं कि अपीलार्थियों द्वारा कारित कार्य को ऐसा कार्य नहीं कहा जा सकता जो उनके हाथों से क्रोधवश घटित हो गया था । इसके विपरीत साक्ष्य से दर्शित होता है कि यह सभी कार्य सोच-समझकर किए गए कार्य थे । न्यायालय इन कार्यों और उनके द्वारा कारित कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार कर पाने में कठिनाई का अनुभव करता है कि अपीलार्थी मृतक की हत्या कारित किए जाने के आशय नहीं रखते थे । अतः, न्यायालय ऊपर वर्णित तर्कपूर्ण कारणोंवश विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाता । (पैरा 21)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

- [2007] 2007 (2) बाम्बे सी. आर. (क्रिमिनल) 332 =
2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4120 :
शेख बक्शन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ; 6, 17
- [1957] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614 :
वेलू थेवड़ बनाम मद्रास राज्य । 19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 264.

2005 के सेशन मामला संख्या 452 में पुणे के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 18 दिसंबर, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से

श्री डी. जी. खेमकर

प्रत्यर्थी की ओर से

श्रीमती एम. एम. देशमुख, सहायक
अभियोजन अधिकारी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी. डी. कोडे ने दिया ।

न्या. कोडे – अपीलार्थियों ने 2005 के सेशन मामला संख्या 452 में

पुणे के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 18 दिसंबर, 2007 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी है जिसके अन्तर्गत उनको अपीलार्थी संख्या 1 की पत्नी और अपीलार्थी संख्या 2 की बहू सारिका की हत्या कारित करने के अपराध में उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने और स्वर्णाभूषणों की उनकी अवैध मांग पूरा न कर पाने के कारण उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया। दोनों को आजीवन कारावास भोगने और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर उनमें से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क सपठित धारा 34 के अधीन एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना था। अधिरोपित किए गए सारवान् दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने के लिए आदेशित किया गया था।

2. अभियोजन के अनुसार अभि. सा. 1 आशाबाई की पुत्री सारिका और पुणे जिले के तालखेड के तिनेबाडी निवासी नारायण अरुडे का विवाह तारीख 14 मई, 2004 को हुआ था। अपीलार्थी संख्या 1 श्रमिक और ट्रैक्टर ड्राइवर के रूप में कार्य करता था। विवाह के पश्चात् सारिका अपने सास-ससुर और अपीलार्थी संख्या 1 के साथ ग्राम जुल्के में रहने लगी।

2.1 सारिका के पिता-माता ने दो-तीन माह के सुखद वैवाहिक जीवन के पश्चात् दम्पति को दीपावली के त्यौहार के अवसर पर अपने घर आमंत्रित किया था। इस पर अपीलार्थियों ने सारिका से कहा कि वह अपने पिता-माता से इस अवसर पर कम से कम डेढ़ तोले की सोने की चेन/अंगूठी दिलवाए अन्यथा वे त्यौहार के अवसर पर उसको नहीं भेजेंगे। सारिका ने उनको बताया कि उसके पिता-माता इस प्रकार के जेवरात का खर्च वहन नहीं कर सकते चूंकि उन्होंने पहले से ही उसके विवाह के लिए कर्ज ले रखा है। इस पर दोनों अपीलार्थियों ने उसको गालियां देना और पीटना आरंभ कर दिया। उन्होंने उसके गर्भस्थ शिशु की पैतृत्व के बारे में भी शंका करना आरंभ कर दिया।

2.2 शिल्पा और समीर जो सारिका के छोटे बहन भाई हैं, दम्पति को दीपावली के त्यौहार के अवसर पर आमंत्रित करने के लिए उसके घर आए, को भी अपीलार्थियों द्वारा जेवरों की मांग दोहराए जाने के पश्चात् वापस लौटा दिया गया। जैसा कि अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा बताया गया है, सारिका अकेले ही अपने पिता-माता के घर “भाऊ बीज” के दिन गई। उसने उनको अपीलार्थी संख्या 2 के संदेश से अवगत कराया कि वे जेवरों

की प्राप्ति के पश्चात् ही दोनों को एक साथ उनके घर भेजेंगे। सारिका ने उनको इस बात से भी अवगत कराया कि अपीलार्थी उसके गर्भस्थ शिशु की पैतृत्व पर शंका के कारण उसको गालियां देते हैं और मारते-पीटते हैं। दूसरे दिन सारिका अपनी ससुराल वापस लौट गई। उसके पश्चात् भी अपीलार्थियों ने उसके गर्भस्थ शिशु की पैतृत्व पर शंका करते हुए उसके साथ गाली-गलौज करना और मारना-पीटना जारी रखा।

2.3 सारिका ने अपने चचेरे ससुर अर्थात् प्रतिरक्षा साक्षी संख्या 1 श्री दत्तात्रेय बरोडे के घर पर लगे हुए फोन का प्रयोग करते हुए तिनेबाड़ी में अपने चचेरे भाई अनिल से सम्पर्क करके अपने पिता-माता को इन घटनाओं से अवगत कराया था। अपने पिता द्वारा आमंत्रित किए जाने पर सारिका और अपीलार्थी संख्या 1 सारिका के पिता के मकान पर दोपहर के भोजन के लिए आए थे। तब उसके पिता-माता ने अपीलार्थी संख्या 1 के लिए कपड़े खरीदने की योजना बनाई थी। फिर भी, अपीलार्थी संख्या 1 स्वर्णाभूषण न दिए जाने के कारण क्रोधित होकर सारिका के साथ वापस लौट आया था। तभी से सारिका पर स्वर्णाभूषण न दिए जाने और साथ ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता के बारे में संदेह का आरोप लगाया जा रहा था।

2.4 अभियोजन के अनुसार तारीख 21 फरवरी, 2005 को घटना घटित होने वाले सोमवार को उसके ससुराल पक्ष के लोग खेत पर गए थे और अपीलार्थी संख्या 1 अपराह्न लगभग 1.30 बजे खेत में था। प्रातःकाल लगभग 4.30 बजे पड़ोस का एक लड़का मुकुंद बोराडे आया और उसने मिसरी (दंत पाउडर) की मांग की। जैसा कि सारिका द्वारा बताया गया है, वह मिसरी लेने के लिए घर के भीतर चला गया था। जब अपीलार्थी संख्या 1 वापस लौटा तो मुकुंद वापस जाने वाला था।

2.5 अपीलार्थी संख्या 1 ने संदेह व्यक्त करते हुए सारिका से मुकुंद के आने के बारे में पूछताछ की। अपीलार्थी संख्या 1 ने उसको गालियां दीं और देर रात्रि तक उससे झगड़ा किया। मध्य रात्रि में लगभग 1.30 बजे उसने सारिका को मुक्कों से पीटना आरंभ कर दिया। शोर सुनने पर अपीलार्थी संख्या 2 ने उनसे लड़ाई-झगड़े का कारण पूछा। अपीलार्थी संख्या 1 ने उसको अपनी अनुपस्थिति में मुकुंद के आगमन के बारे में अवगत कराया। उसने सारिका के चरित्र के बारे में संदेह व्यक्त किया और कहा कि वह उस बच्चे का पिता नहीं है जो उसके गर्भ में है। तत्पश्चात् अपीलार्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी संख्या 1 से कहा कि वह

उसको (सारिका को) समाप्त कर दे और उसने भी (सारिका को) भद्दी-भद्दी गालियां दीं ।

2.6 अपीलार्थी ने उसको (सारिका को) पीटना आरंभ कर दिया । उसने रसोई से बाहर जाने का प्रयास किया किंतु उन लोगों ने उसको पकड़ लिया । अपीलार्थी संख्या 1 ने कैरोसिन उठाया और उसके दोनों कंधों पर डाल दिया । अपीलार्थी संख्या 2 ने उसके ऊपर जलती हुई माचिस की तीली फेंक दी और रसोई का दरवाजा बंद करके बाहर खड़ा हो गया । जैसे ही सारिका की साड़ी ने आग पकड़ी, उसको महसूस हुआ कि उसका शरीर जल रहा है और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया । जैसे ही उसने रसोई से बाहर आने का प्रयास किया अपीलार्थी संख्या 1 ने उसको वापस भीतर धकेल दिया । सारिका ने पलंग से रजाई उठाई और आग को बुझाया । उसकी चचेरी सास चंगुनाबाई और पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंच गए । चंगुनाबाई नंद सुरेखा, अपीलार्थी और उसके ससुर जीप द्वारा उसको वाई. सी. एम. अस्पताल और तत्पश्चात् ससून अस्पताल लाए ।

2.7 अभियोजन के अनुसार, अभि. सा. 4 पुलिस उप-निरीक्षक यादव वाई. सी. एम. अस्पताल से यह सूचना प्राप्त होने पर कि सारिका को जलाए जाने के मामले में अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसको प्राथमिक चिकित्सा प्रदान किए जाने के पश्चात् ससून अस्पताल को निर्दिष्ट कर दिया गया है, ससून अस्पताल गया । अभि. सा. 4 ने कार्य पर उपस्थित डाक्टर अर्थात् अभि. सा. 3 डा. वेंकट से पूछा कि क्या जलन वार्ड में पलंग संख्या 15 पर भर्ती उक्त मरीज होश में है और कथन करने में समर्थ है । अभि. सा. 3 ने परीक्षण करने के उपरांत मत व्यक्त किया कि मरीज होश में है और कथन करने में समर्थ है । तदनुसार, उसने इस तथ्य को दर्ज किया जो प्रदर्श-24 है । तत्पश्चात् अभि. सा. 4 ने ऊपरवर्णित तथ्यों का वर्णन प्रस्तुत करने वाली सारिका की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श-30) अभिलिखित किए । अभि. सा. 4 ने उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क सपठित धारा 34 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए 2005 की अपराध संख्या 28 रजिस्ट्रीकृत की । उसने आहत का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट अभि. सा. 2 श्रीमती शोभा देशमुख को पत्र भी जारी किया जो प्रदर्श-19 है ।

2.8 अभियोजन के अनुसार अभि. सा. 2 कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्रीमती

शोभा देखमुख, पत्र जो प्रदर्श-19 है, की प्राप्ति के पश्चात् तुरंत ससून अस्पताल गई और चिकित्सक से मिली। तत्पश्चात् अभि. सा. 2 ने वार्ड के बारे में पूछताछ की जिसमें सारिका भर्ती थी। अभि. सा. 3 ने सारिका को उसको दिखाया। अभि. सा. 3 ने परीक्षण किया और प्रमाणपत्र दिया कि वह विधिमान्य कथन करने की स्थिति में है। तत्पश्चात् अभि. सा. 2 ने इस बात को अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या सारिका कथन करने और समझ पाने की स्थिति में है, उससे कुछ प्रश्न पूछे और तत्पश्चात् उसने सारिका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया, जो प्रदर्श-20 है। अभि. सा. 3 ने पुनः सारिका का परीक्षण किया और सारिका द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन को प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र दिया। पृष्ठांकन किया। अभि. सा. 2 ने उसके द्वारा यह स्वीकार किए जाने के पश्चात् कि उसको पढ़कर सुनाए गए। उक्त कथन, को ठीक ही अभिलिखित किया गया है, उक्त कथन पर उसके बाएं पैर का अंगूठा निशान प्राप्त किया।

2.9 अभि. सा. 4 ने घटनास्थल का दौरा किया और वहां पर अभिभावी स्थिति को अभिलिखित किया और घटनास्थल पर पाई गई दस वस्तुओं जैसे कि (i) दस लीटर का कैन जिसमें आधा लीटर कैरोसिन था; (ii) माचिस की डिब्बी; (iii) एक लोहे का स्टोव; (iv) किसन का आई. एस. आई. चिन्ह वाला हीटर; (v) बंद हालत में एक कापर-पीतल का स्टोव; (vi) उसकी जली हुई माचिस की तीलियां; (vii) तीन हरे रंग के कंगन के टुकड़े; (viii) रजाई और विभिन्न रंगों के कपड़े जिनसे जले की महक आ रही थी; (ix) लाल रंग की साड़ी के जले हुए टुकड़े जिससे कैरोसिन, रसोई के फर्श पर पाया गया था, की महक आ रही थी, का अभिग्रहण किया।

2.10 अभि. सा. 4 ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और आहत के कपड़े अभिगृहीत किए। अभि. सा. 4 ने दोनों अपीलार्थियों को तारीख 25 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया और पंचनामा प्रदर्श-15 के अंतर्गत उनके कपड़ों को अभिगृहीत कर लिया। तारीख 25 फरवरी को अपराह्न 9.30 बजे ससून अस्पताल में सारिका की मृत्यु के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किए गए अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 498-क सपठित धारा 34 के अधीन अपराध में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सारिका के शव की शव-परीक्षा ससून अस्पताल में डा. मोहले द्वारा की गई थी। उसके द्वारा तैयार की गई उक्त शव-परीक्षा के मरणोत्तर परीक्षा टिप्पण में मृत्यु का कारण “जल जाने के कारण

विषाक्त प्रख्यात” (गर्भावस्था से सम्बद्ध) दर्ज किया गया है। अभि. सा. 4 ने मुदम्मल वस्तुओं को रसायनिक विश्लेषण को भेज दिया और अन्वेषण की समाप्ति पर उसने अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 498-क सपठित धारा 34 के अधीन अपराध के बाबत आरोप पत्र फाइल कर दिया।

3. अपीलार्थियों ने सुपुर्दगी न्यायालय द्वारा मामला उक्त न्यायालय के सुपुर्द किए जाने के पश्चात् पुणे के सेशन न्यायालय द्वारा इन अपराधों के बाबत उसके विरुद्ध विरचित आरोपों के संबंध में स्वयं के दोषी न होने का अभिवाक् किया। अभियोजन ने कुल मिलाकर चार साक्षियों का परीक्षण कराया जिनके ऊपर अभियोजन के पक्षकथन के समर्थन में निर्दिष्ट किया गया है। अपीलार्थियों की प्रतिरक्षा मामले में उनकी संलिप्तता से पूर्णतः इनकार और मामले में उनको असत्य रूप से अंतर्वलित किए जाने का था।

4. अपीलार्थी संख्या 1 ने लिखित कथन जो प्रदर्श-43 है, फाइल किए जाने के द्वारा दावा किया कि घटना की तारीख को सारिका सरदर्द और वायु विकार से पीड़ित थी और उसने चाय बनाने के लिए स्टोव जलाया था। चूंकि स्टोव पुराना था और उचित स्थिति में नहीं था, बर्नर से अतिरिक्त कैरोसिन बाहर निकल आया और स्टोव धधक पड़ा जिसके कारण सारिका आग में घिर गई। अपीलार्थी संख्या 1 ने उसके शरीर पर रजाई डालने के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया के दौरान उसके हाथ जल गए। दोनों जोर से चिल्लाए। अपीलार्थी संख्या 2 जो सारिका का ससुर है, उसके चचेरे ससुर और चचेरी सास उनको खेड़ स्थित डिस्पेंसरी लाए। क्योंकि सारिका की स्थिति नाजुक थी, उसको वाई. सी. एम. अस्पताल ले जाया गया। वहां भी उसका समुचित उपचार नहीं किया गया और वे उसको बोसारी स्थित निजी अस्पताल स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे थे। इसी बीच उसका निधन हो गया। यद्यपि उसके ससुराल पक्ष के लोग प्रातःकाल 6.00 से 6.30 बजे के मध्य अस्पताल आ गए थे, उन्होंने चचेरे ससुर के आगमन के पश्चात् दोपहर 12.00 से 12.30 बजे कलाबाजी खाई और मिलीभगत के पश्चात् विवाह में उपगत खर्च की मांग करने के पश्चात् उन्होंने असत्य मामला फाइल करने का निर्णय लिया। चूंकि वह निर्दोष था, वह शांत रहा। इसीलिए, असत्य मामला फाइल किए जाने के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था।

4.1 अपीलार्थी संख्या 2 ने लिखित कथन प्रदर्श-41 द्वारा दावा किया कि सारिका कभी-कभी सरदर्द से ग्रस्त होने के स्थित में चाय पीती थी। उसने दावा किया कि घटना के दिन भी वह सरदर्द से ग्रस्त थी, उसने चाय बनाने के लिए स्टोव जलाया था। स्टोव के धधक पड़ने के कारण उसको जलन वाली क्षतियां बरदाश्त करनी पड़ी थीं। अपीलार्थी संख्या 1 को जलन वाली क्षतियां तब कारित हुईं जब वह उसको (सारिका को) बचाने के लिए आग बुझाने गया था। वे उन दोनों को ही खेड़ स्थित डिस्पेंसरी ले गए थे। चूंकि सारिका की स्थिति नाजुक थी, उसको वाई. सी. एम. अस्पताल और तत्पश्चात् ससून अस्पताल ले जाया गया था। उसके पिता-माता प्रातःकाल आ गए थे, उन्होंने उनको सत्य घटनाओं के बारे में बताया था। तथापि, सारिका के पिता ने दोपहर तक बहुत से नातेदारों के आगमन के पश्चात् विवाह में लिए गए ऋण के बाबत धन की मांग की थी। उन्होंने यह कहते हुए सम्पूर्ण रकम की मांग की थी कि रकम का संदाय न किए जाने पर वह इस बाबत असत्य मामला फाइल कर देंगे कि उन्होंने ही सारिका की हत्या की है और तदनुसार उन्होंने असत्य मामला फाइल किया है। अपीलार्थियों ने अपीलार्थी संख्या 1 के चाचा दत्तात्रेय बरोड़े का परीक्षण प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ कराया।

5. विचारण न्यायालय साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन ने साबित कर दिया है कि सारिका की मृत्यु मानवहत्या थी और अपीलार्थियों ने सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके चरित्र पर शंका करते हुए और स्वर्णाभूषणों की मांग पूरी न किए जाने के लिए उसके साथ क्रूरता की थी और उसकी हत्या कारित कर दी थी। विचारण न्यायालय ने इन निष्कर्षों पर पहुंचते हुए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट कर दिया जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

6. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री खेमकर ने विचारण के समय प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की ओर अति सावधानीपूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए समर्थन किया कि विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि मुख्यतः मृतक के मृत्युकालिक कथन, जो अभिकथित रूप से अभि. सा. 4 और अभि. सा. 2 द्वारा अभिलिखित किया गया है और अभि. सा. 1 के समक्ष किया गया है, के आधार पर की है। साक्ष्य से कतिपय लक्षणों की ओर संकेत करते हुए यह समर्थन किया गया कि आहत का अभियोजन साक्ष्य कि आहत ने इस प्रकार का मृत्युकालिक कथन अभि. सा. 1 को दिया था, के आधार पर यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह कथन हितबद्ध व्यक्ति को

दिया गया था और/या स्वीकृततः, जब आहत अस्पताल में नातेदारों द्वारा घिरा हुआ था। यह दलील दी गई कि अभि. सा. 4 और अभि. सा. 2 द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन के संबंध में अभियोजन साक्ष्य भी उसमें विद्यमान मतभेद के कारण और/या समय के संबंध में किए गए अन्तर्वेक्षण और/या तर्कपूर्ण साक्ष्य की इस बाबत कमी के कारण कि उक्त मृत्युकालिक घोषणा में से किसी भी बात को सत्य नहीं कहा जा सकता और मृतक द्वारा की गई स्वैच्छिक मृत्युकालिक घोषणा जैसीकि विधि द्वारा अपेक्षित है, विश्वास सृजित नहीं करते। यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का अधिमूल्यन करने और त्रुटिपूर्ण विपरीत निष्कर्षों पर पहुंचने और अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने में प्रकट रूप से त्रुटि की है। यह समर्थन किया गया कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों की प्रतिरक्षा, जो अपीलार्थी संख्या 1 के हाथों में जलन क्षतियां हो जाने के द्वारा संभावित होती है, का अधिमूल्यन न करके गंभीर त्रुटि कारित की है। यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश विधितः मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है और अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने योग्य है या कम से कम संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं चूंकि अभियोजन साक्ष्य भी अपीलार्थियों के दोषी न होने की संभाव्यता का समर्थन करता है। विद्वान् काउंसिल ने भी अपने निवेदन के समर्थन में और विशेष रूप से इस संबंध में कि मृत्युकालिक घोषणा, जो प्रदर्श-30 और प्रदर्श-20 है, अस्वीकृत किए जाने योग्य है, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभि. सा. 4 और अभि. सा. 2 ने मृत्युकालिक घोषणा में इस बात का उल्लेख न किया जाना स्वीकार किया है कि उसको अभिलिखित किए जाने के पश्चात् आहत को पढ़कर सुनाया गया था और आहत ने स्वीकार किया था कि वह सही है, **शेख बक्शन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य¹** वाले मामले का अवलंब लिया।

7. इसके विपरीत विद्वान् सहायक लोक अभियोजक श्रीमती एम. एम. देशमुख ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने दलील दी कि विचारण न्यायालय ने मृतक के सत्य और स्वैच्छिक मृत्युकालिक कथनों का अवलंब लेने और उन पर कार्यवाही करने के

¹ 2007 (2) बाम्बे सी. आर. (क्रिमिनल) 332 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4120.

प्रयोजनार्थ अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर महत्वपूर्ण कारण दर्शित किए हैं जिनको अभियोजन द्वारा साबित किया गया है। यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए सकारण निर्णय में मध्यक्षेप किए जाने के लिए कोई मामला नहीं बनता और इसलिए गुणागुण रहित है और खारिज की जाती है।

8. हमारे समक्ष समर्थित किए गए निवेदनों की पुष्टि किए जाने के हेतु दोनों पक्षों के निवेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और अभिलेख का सतर्कतापूर्वक परिशीलन किया गया।

9. आरंभिकतः, यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों ने भी इस तथ्य को विवादित नहीं किया कि सारिका की मृत्यु उसके द्वारा जलन क्षतियां बरदाश्त करने के कारण हुई थी और विवाद इस बाबत किया जा रहा है कि क्या उसको अपीलार्थी द्वारा जलाया गया था, जैसा कि दावा अभियोजन द्वारा किया गया है या उसने दुर्घटनावश जलन क्षतियां बरदाश्त की थीं। अपीलार्थियों के विचार में सारिका की मृत्यु तारीख 21 फरवरी की रात जलन क्षतियों के कारण होने को विवादित न किए जाने और यह विवाद बनाए जाने कि उसने उक्त क्षतियां अपीलार्थियों के कार्यों के कारण बरदाश्त नहीं की थी बल्कि चाय तैयार करते समय स्टोव से लपटे उठ जाने के कारण घटित दुर्घटनावश हुई थी और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम इस समुचित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वप्रथम मृत्युकालिक कथन के संबंध में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार किया जाए जिसका अवलंब लिया गया है।

10. उक्त प्रकिया में हम समुचित समझते हैं कि सर्वप्रथम अभि. सा. 3 के साक्ष्य पर विचार किया जाए। चूंकि प्रकटतः अभियोजन के पक्षकथनानुसार वह मृतक के दोनों मृत्युकालिक कथन अर्थात् अभि. सा. 4 द्वारा प्रदर्श-30 और अभि. सा. 2 द्वारा प्रदर्श-20 अभिलिखित किए जाने और दोनों अवसरों पर आहत का परीक्षण किए जाने और उक्त दोनों साक्षियों, जो उसके मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने का दावा करते हैं, को प्रमाणपत्र/स्वीकृति दिए जाने का पक्ष था।

11. अभि. सा. 3 के साक्ष्य को निर्दिष्ट किए जाने पर यह प्रकट होता है कि वह पुणे के ससून अस्पताल के चिकित्साधिकारी के रूप में कार्य करते हुए तारीख 23 फरवरी, 2005 को जलन वार्ड में उपस्थित था और सारिका को उसी वार्ड में जलन मामले के रूप में भर्ती किया गया

था । यह भी प्रकट होता है कि राजगुरु नगर (खेड़) पुलिस थाना की पुलिस द्वारा उसके विचार जानने के लिए उससे सम्पर्क किए जाने के पश्चात् वह पुलिस के साथ गया और सारिका का परीक्षण किया । इससे यह भी प्रकट होता है कि तब सारिका बोलने की स्थिति में थी और वह अपने होशोहवास में थी और सब कुछ बता सकने की स्थिति में थी । यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 3 ने भी तदनुसार पुलिस अधिकारी को जानकारी दी थी । तत्पश्चात् पुलिस अधिकारी ने अभि. सा. 3 की उपस्थिति में उसका कथन अभिलिखित किया और तत्पश्चात् अभि. सा. 3 ने उसके कथन के आधार पर पृष्ठांकन किया जो प्रदर्श-41 है । प्रदर्श-24 इस प्रकार है :-

“तारीख 23 फरवरी, 2005

14.10 बजे से 14.45 बजे अपराह्न

श्रीमती सारिका बरोड़े

पी-108/आर

बी. पी. 100/70

सी. एन. एस. – होशोहवास में है,

समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में बता सकती है ।”

मरीज वर्तमान में विधिमान्य कथन करने की स्थिति में है ।

अभि. सा. 3 के साक्ष्य का अनुमोदन किए जाने की सीमा तक अनुमोदन प्रदर्श-24 द्वारा सम्यक् रूप से सम्पुष्ट पाया जाता है जिसको इसमें इसके ऊपर प्रत्युत्पादित किया गया है ।

11.1 अभि. सा. 3 ने आगे सशपथ कथन किया कि उसी दिन कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् कार्यकारी मजिस्ट्रेट सारिका का कथन अभिलिखित करने के लिए अस्पताल आए और अभि. सा. 3 ने उसका परीक्षण किया और उसके कथन प्रदर्श-20 के आरंभ में इस बात का अनुमोदन दर्ज किया । उसने सशपथ कथन किया कि वह कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा उसका कथन अभिलिखित किए जाने के दौरान उपस्थित था और कथन की समाप्ति के पश्चात् उसने पुनः प्रदर्श-20 के अंत में अपने हस्ताक्षर किए थे । प्रदर्श-20 के परिशीलन से प्रकट होता है कि प्रथम अनुमोदन इस प्रकार है :-

“तारीख 22 फरवरी, 2005

4.00 बजे अपराह्न – श्रीमती सारिका बरोड़े,

पी-108/आर

बी. पी. 100/70

सी. एन. एस. – होशोहवास में है,

समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में बता सकती है ।

मरीज वर्तमान में विधिमान्य कथन करने की स्थिति में है ।”

तारीख 23 फरवरी, 2005

समय 4.55 बजे अपराह्न

11.2 अभि. सा. 3 के साक्ष्य के संबंध में अभि. सा. 4 पुलिस उप-निरीक्षक श्री यादव और अभि. सा. 2 श्रीमती शोभा के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 3 द्वारा दिया गया साक्ष्य इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने के उनके साक्ष्य द्वारा पूर्णतः सुस्पष्ट है जैसे कि उनमें से दोनों ने भिन्न-भिन्न समय पर ससून अस्पताल की शरण ली थी और अभि. सा. 3 से मुलाकात की थी और अभि. सा. 3 ने परीक्षण के पश्चात् उनमें से प्रत्येक द्वारा कथन/मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के लिए यह प्रमाणपत्र दिए थे ।

11.3 प्रतिपरीक्षा के दौरान प्राप्त उत्तरों के प्रकाश में अभि. सा. 3 के साक्ष्य की गहराई से संवीक्षा किए जाने पर हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि उसके साक्ष्य में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है । श्री खेमकर ने दृढ़तापूर्वक दलील दी कि अभि. सा. 3 के साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता कि उसने शपथपूर्वक उस समय के बारे में बताया था कि जिस पर अभि. सा. 4 और अभि. सा. 2 ने उससे सम्पर्क किया था । यह दलील दी गई कि अभि. सा. 3 का साक्ष्य सारिका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने की घटना के समय के संबंध में अस्पष्ट है जैसा कि दावा उनके द्वारा किया गया है । यह दलील भी दी गई कि अभि. सा. 3 ने अपने दावे के संपुष्टिकरण के बाबत कोई चिकित्सा दस्तावेज पेश नहीं किया है कि अभि. सा. 4 और अभि. सा. 2 ने सुसंगत दिवस पर जलन वार्ड में उससे सम्पर्क किया था, जैसा कि दावा उसके द्वारा किया गया है ।

11.4 हम उक्त निवेदन में कोई बल पाने में असमर्थ हैं । चूंकि अभि. सा. 3 के साक्ष्य से प्रकट होता है कि वह अत्यधिक सूक्ष्मतापूर्वक अपीलार्थियों की ओर से प्रतिपरीक्षा कर रहा था और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया पुलिस का कथन अपराह्न लगभग 2.00 बजे अभिलिखित किया था और पुलिस द्वारा कथन अभिलिखित किए जाने में लगभग 45 मिनट लगे थे । इसी प्रकार से

अभिलेख पर यह तथ्य लाया गया कि अभि. सा. 2 जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट है, अपराहन लगभग 4.00 बजे अभि. सा. 3 के पास गया था। हम अभि. सा. 3 द्वारा किए गए दावे के पुष्टिकरण के लिए सारिका के मामले के कागजात प्रस्तुत न किए जाने के बारे में निवेदन में कोई सार पाने में भी असमर्थ हैं। जैसा कि किए गए हमारे द्वारा पहले भी संकेत दिया गया है, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 2 द्वारा अलग-अलग अभिलिखित मृत्युकालिक कथन प्रदर्श-30 और प्रदर्श-20 पर प्रकट होने वाले सुसंगत अनुमोदनों द्वारा उसके साक्ष्य का पुष्टिकरण किया गया है। इसलिए, हम उक्त निवेदन, जो प्रकट रूप से उक्त मामले के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की विद्यमान आवश्यकता की गलत धारणा पर आधारित है, में कोई सार नहीं पाते। इसके अतिरिक्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विचारण के समय पर प्रतिरक्षा पक्ष ने किसी भी प्रकार से यह साबित नहीं किया है कि उक्त मामले के दस्तावेजों में उक्त साक्षियों की मुलाकातों की प्रविष्टियां समाविष्ट नहीं हैं।

11.5 इसी संदर्भ में, पूर्वाहन 2.10 से 2.45 बजे के मध्य प्रदर्श-24 में दिए गए समयक्रम को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान् काउंसिल ने निवेदन किया कि अंक 1 पूर्व के अंक 4 में जोड़ा गया है कि मृत्युकालिक कथन अपराहन 4.10 से 4.45 बजे के मध्य अभिलिखित नहीं किया गया था जैसा कि मूल अनुमोदन में समाविष्ट है और इसके बजाय 2.10 से 2.45 बजे के मध्य अभिलिखित किया गया था। हम इस निवेदन में कोई बल नहीं पाते जो प्रकटतः अंक के लिए प्रयोग की गई स्याही के आधार पर किया गया है जो अनुमोदनों के दूसरे भाग में प्रकट होने वाली स्याही से अधिक गहरी थी क्योंकि इसके लिए अनेक कारण हो सकते हैं और किए गए निवेदन का समर्थन नहीं करते, अभि. सा. 3 के शपथपूर्वक कथन में पाया जाता है या इसके बाद भी हम उक्त पहलू को कोई अनुचित महत्व देने में असमर्थ हैं।

11.6 इसके अतिरिक्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त अनुमोदन का रचयिता अर्थात् अभि. सा. 3 से उक्त पहलू के संबंध में प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई पूछताछ नहीं की गई थी, यहां तक कि उसको इस संबंध में कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था। इस बात पर विचार करते हुए कि अभि. सा. 4 सारिका का कथन अभिलिखित किए जाने के लिए उससे सम्पर्क करने वाला प्रथम व्यक्ति था और अभि. सा. 2 ने स्वीकृततः उससे बाद में सम्पर्क स्थापित किया, हम इस बात का मूल्यांकन

कर पाने में असमर्थ हैं कि ऐसा कोई भी अन्तरगणन, जैसा कि अभिकथित किया गया है, पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अर्थपूर्ण प्रयोजन के लिए किया जा सकता था। अतः, प्रकटतः उक्त अनुमोदन में उत्पन्न होने वाली इंक में भिन्नता के आधार पर एक तिल से पहाड़ बनाने का प्रयास किया गया है।

11.7 पूर्वोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभि. सा. 3 के साक्ष्य की संवीक्षा किए जाने पर वही भरोसा सृजित होता है जो उसको स्वीकार किए जाने और उसका अवलंब लेने के लिए आवश्यक होता है। उक्त साक्ष्य द्वारा अभियोजन ने सम्यक रूप से इस तथ्य को साबित कर दिया है कि सारिका को ससून अस्पताल में भर्ती किया गया था, अभि. सा. 4 ने अभि. सा. 3 से सम्पर्क किया था और स्वयं ही इस बात को प्रमाणित करने के पश्चात् कि वह कथन करने के लिए उपयुक्त थी, उसने उसका कथन अभिलिखित किया था। इसी प्रकार से अभियोजन ने इस बात को भी साबित किया है कि अभि. सा. 2 ने अभि. सा. 3 से सम्पर्क किया था और समान रीति में अभि. सा. 3 ने प्रमाणित करने के पश्चात् कि सारिका कथन करने की स्थिति में है, उसने उसका मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया था। हमारा ऐसा विचार इसलिए है चूंकि हम अभि. सा. 3 के साक्ष्य में उसके द्वारा किए गए दावे को स्वीकार न किए जाने के लिए कोई बनावट नहीं पाते। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अभि. सा. 3 के एक स्वतंत्र व्यक्ति होने के कारण इस प्रकार के असत्य दावे करने के लिए शायद ही कोई कारण उत्पन्न हुआ था।

12. अभि. सा. 3 के साक्ष्य पर विचारोपरांत अब हम अभि. सा. 4 के साक्ष्य पर विचार करते हैं, जिसके शपथपूर्वक कथन को निर्दिष्ट करने पर उस तरीके का प्रकटीकरण होता है कि जिसमें वह सारिका को प्राथमिक उपचार प्रदान किए जाने के पश्चात् ससून अस्पताल भेजे जाने के संबंध में वाई. सी. एम. अस्पताल से सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ससून अस्पताल गया था। इससे प्रकट होता है कि उसने अभि. सा. 3 से सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उक्त अस्पताल में सारिका का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श-30 अभिलिखित किए जाने के लिए अभि. सा. 2 को उसके द्वारा दी अपेक्षा के बारे में प्रकटीकरण होता है। उसके साक्ष्य का अन्य भाग उसके द्वारा किए गए अन्वेषण तक सीमित है क्योंकि अभि. सा. 4 का उक्त साक्ष्य अभियोजन पक्षकथन, जिसको इसमें इसके ऊपर वर्जित किया गया है, के

सामंजस्य में है और चूंकि हम उक्त साक्ष्य में कोई शैथिल्य नहीं पाते, हम उसको प्रत्युत्पादित करने का कोई प्रयोजन नहीं पाते ।

12.1 विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल श्री खेमकर ने अभि. सा. 4 के साक्ष्य के संदर्भ में हमारा ध्यान प्रदर्श-30 की ओर आकर्षित करते हुए दलील दी कि उक्त प्रदर्श स्वयमेव ही निर्दिष्ट करता है कि वह सत्य नहीं है और सारिका द्वारा की गई स्वैच्छिक घोषणा है । उन्होंने यह दलील दी कि इस प्रदर्श के अंतर्गत अभिलिखित कथन छलरचना उपदर्शित करता है कि हम उक्त आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हैं चूंकि अभि. सा. 4 के साक्ष्य को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने प्रदर्श-30 अस्पताल में भर्ती आहत के कथन के रूप में अभिलिखित किया था, न कि कड़ाईपूर्वक उसका मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के लिए । यह बात अभि. सा. 4 जिसने मांग-पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी प्रति प्रदर्श-19 है और जिसको अभि. सा. 2 को मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के लिए भेजा गया था, द्वारा दिए गए कथन से सुव्यक्त है । अतिरिक्त स्वीकृत दस्तावेज अर्थात् मरणोत्तर परीक्षा टिप्पण प्रदर्श-20 के निदेश से यह प्रकट होता है कि सारिका 63 प्रतिशत जल गई थी । इससे यह प्रकट नहीं होता है कि कोई बड़ी क्षति कारित हुई थी जिसके कारण उसके वाक्तन्तु अंग शिथिल हो गए थे । अभि. सा. 3 के साक्ष्य के अलावा उक्त तथ्य प्रतिरक्षा पक्ष के इस निवेदन के विरुद्ध उक्त तथ्य को खारिज करता है कि सारिका इतना लंबा कथन नहीं दे सकती थी । आगे यह भी कहा जा सकता है कि हमारे ज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया था कि सारिका की उस समय की स्थिति इतनी अस्थिर थी कि वह इतना लंबा कथन नहीं कर सकती थी । यद्यपि यह सत्य है कि उक्त कथन प्रदर्श-30 उस सीमा तक है जैसा कि विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा बताया गया है, फिर भी उसको उसके कथन के रूप में अभिलिखित किए जाने वाला कार्य मृत्युकालिक कथन के पहलू तक सीमित न होने के कारण इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता । वह मनगढ़ंत कथन होने का सुझाव मात्र है ।

12.2 अभि. सा. 4 द्वारा की गई स्वीकारोक्ति की ओर संकेत करते हुए कि वार्ड में अन्य मरीज भी थे, मृतक के नातेदारों के साथ कुछ व्यक्ति भी उपस्थित थे । विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने दलील दी कि वह स्वीकारोक्ति इस बात का सुझाव है कि सारिका का कथन अभिलिखित किए जाने के पूर्व सिखलाया गया था । हम इस निवेदन में इस साधारण

कारणवश कोई बल नहीं पाते । चूंकि प्रश्नगत घटना मध्यरात्रि में लगभग 1.30 बजे घटित हुई थी और इसलिए घटना घटित हो जाने के पश्चात् समय व्यतीत हो जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए मरीज के नातेदारों के लिए यह असंभाव्य नहीं था कि वे अस्पताल में उपस्थित न होते । फिर भी, मात्र अस्पताल में मृतका के नातेदारों की उपस्थिति के आधार पर दिए गए निवेदनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता । अभि. सा. 1 के साक्ष्य, जो सारिका को कारित उत्पीड़न और क्रूरता के संबंध में निरंतरता को दर्शित करता है, पर विचारोपरांत इस प्रकार का निष्कर्ष सुस्पष्ट है । उक्त पहलू ऐसे किसी मामले के विरुद्ध कार्य करता है जो अभियुक्त द्वारा सिखलाए जाने के कारण बताया गया हो और इसके विपरीत मृतक द्वारा की गई घोषणा के पूर्णतया सुझाव होने के कारण सत्य और स्वैच्छिक हो । अभि. सा. 4 के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा इस बात पर विश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं करती कि उसके द्वारा अभिलिखित कथन प्रदर्श-30 सिखलाए जाने के परिणामस्वरूप था ।

12.3 विद्वान् काउंसेल ने इसी संदर्भ में अभि. सा. 4 द्वारा की गई स्वीकृति कि उसने इस बात का समर्थन नहीं किया है कि कथन आहत को पढ़कर सुनाया गया था और उसने इस बात को सही अभिलिखित किया या, सही रूप में स्वीकार किया और आगे की गई स्वीकृति कि उसने इस प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं की है चूंकि इस प्रकार की कोई विधिक अपेक्षा नहीं है, की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए दलील दी कि वह भी प्रकटीकरण करता है कि प्रदर्श-30 मृतक का कथन/मृत्युकालिक कथन नहीं है जिसको उस रीति में अभिलिखित किया गया है जिसका दावा अभि. सा. 4 द्वारा किया गया है । हम उक्त निवेदन में कोई गुणागुण नहीं पाते । हमारा भी यही विचार है चूंकि उक्त स्वीकृति पर संपूर्णता में विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि वह अभि. सा. 4 द्वारा अभिलिखित कथन स्वीकार किए जाने के संबंध में है और वह इस तथ्य के संबंध में नहीं था कि ऐसी किसी घटना का घटित होना अर्थात् अभि. सा. 4 द्वारा आहत का कथन पढ़ा जाना और मृतक द्वारा उसको सही रूप में स्वीकृत किया जाना और तत्पश्चात् उसके बाएं पैर के अंगूठे का निशान अभिप्राप्त किया जाना । प्रदर्श-30 के निदेश से इस प्रकार के अनुमोदन का प्रकटीकरण होता है जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि उक्त कथन उसको पढ़कर सुनाया गया था और वह उसी के द्वारा कहे अनुसार लिखा गया था । तथ्यों के अनुसार उक्त पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रतिपरीक्षा में इस प्रकार प्रश्न करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जानी चाहिए थी अर्थात्

लिखित अभिलेख से संबंधित प्रश्न किए जाने की अनुज्ञा किसी भी दृष्टिकोण से अभि. सा. 4 का सारभूत साक्ष्य आहत को कथन पढ़कर कर सुनाया जाना और आहत द्वारा उसको सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना और उसका अनुमोदन, जिसको प्रदर्श-30 में पाया गया, द्वारा पुष्टिकरण किया जाना अभिलेख के विरुद्ध प्राप्त की गई स्वीकृति के आधार पर किए गए निष्कपट निवेदनों का गुणागुण रहित होने के कारण अनदेखा किया जाना अपेक्षित होगा ।

12.4 अभि. सा. 4 के साक्ष्य के संदर्भ में अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसिल ने दलील दी कि जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से प्रकट होता है कि उसने प्रदर्श-30 अभिलिखित किया था और अपराध रजिस्ट्रीकृत किया था और उसके हितबद्ध साक्षी के रूप में प्रतीत किया जाना अपेक्षित होगा और इस प्रकार उसको मामले का अन्वेषण नहीं करना चाहिए था । हम इस दलील में जो इस साधारण कारणवश दी गई है कि प्रकटतः मामले को रजिस्ट्रीकृत करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ऐसा कोई वर्जन विद्यमान नहीं है जो उसको उक्त मामले का अन्वेषण करने से वर्जित करता हो, कोई सार पाने में असमर्थ हैं । हमारा ऐसा विचार है चूंकि उक्त कारणवश पुलिस अधिकारी को हितबद्ध व्यक्ति के रूप में नहीं बुलाया जा सकता । हमारा यह विचार इस कारणवश है कि अनेक निर्णयों द्वारा यह सुस्थापित हो चुका है कि किसी व्यक्ति को हितबद्ध साक्षी केवल उसी परिस्थिति में कहा जा सकता है जब उसके द्वारा किए गए कार्य से कोई लाभ उसके लाभान्वित होने की संभाव्यता हो । उक्त परीक्षण को लागू करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित करने वाले स्वतंत्र अभिकरण के किसी अधिकारी को हितबद्ध व्यक्ति नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त यह धारणा करते हुए कि अभि. सा. 4 हितबद्ध साक्षी है फिर भी मात्र इस कारणवश उसका साक्ष्य अस्वीकृत किए जाने योग्य नहीं होगा । चूंकि यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि यद्यपि जाल बिछाने वाले पुलिस अधिकारियों को हितबद्ध साक्षी कहा जाता है, किन्तु मात्र इस कारणवश उनका साक्ष्य अस्वीकृत किए जाने योग्य नहीं होता और उक्त पहलू ऐसे किसी पुलिस अधिकारी जिसने जाल बिछाया, के साक्ष्य की मात्र सूक्ष्म संवीक्षा किए जाने की अनुज्ञा की जा सकती है । हम उक्त परीक्षण को लागू किए जाने और अभि. सा. 4 के साक्ष्य की सूक्ष्म रूप से संवीक्षा किए जाने पर उसके साक्ष्य में कोई अलंकरण नहीं पाते, इसलिए, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसिल द्वारा किए गए निवेदन में कोई सार पाने में असमर्थ हैं ।

13. अब मृत्युकालिक कथन प्रदर्श-20 से संबंधित अभियोजन के साक्ष्य पर विचार करते हुए अभि. सा. 2 कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्रीमती शोभा के साक्ष्य को निर्दिष्ट करने पर प्रकट होता है कि अभि. सा. 4 से प्राप्त अपेक्षा पत्र, जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श-19 है, की प्राप्ति के पश्चात् वह ससून अस्पताल गई थी और सारिका का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श-20 अभिलिखित किया था। चूंकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्होंने उक्त मृत्युकालिक कथन, जिसको पहले भी वर्णित किया गया है, अभिलिखित किए जाने के संबंध में अभियोजन पक्षकथन के साथ शपथपूर्वक असंगत किया है। हम नहीं चाहते कि उनके साक्ष्य को दोहराया जाए। विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा किए गए निवेदन, कि यद्यपि उन्होंने (अभि. सा. 2 कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्रीमती शोभा) मूल अपेक्षा पत्र, जिसकी प्रति प्रदर्श-19 है, प्राप्त करने का दावा किया था, के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उन्होंने उक्त पत्र अपने साक्ष्य के समय प्रस्तुत नहीं किया। यह दलील देने का प्रयास किया गया कि इससे निर्दिष्ट होता है कि अभियोजन के लिए कपटजाल तैयार किया गया है। हम उक्त दलील को उक्त पत्र की कार्बन प्रति, जो पहले से अभिलेख पर उपलब्ध है, को ध्यान में रखते हुए अस्वीकृत करते हैं और इस प्रकार के किसी मांग-पत्र को प्राप्त किए जाने के बारे में अभि. सा. 4 या अभि. सा. 3 का साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने के बारे में किसी अन्य परिस्थिति की ओर संकेत नहीं किया गया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभि. सा. 3 ने मरीज अर्थात् अभि. सा. 3 को परिचर्या करने वाले चिकित्सक की राय अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरती है। इससे आगे यह भी प्रकट होता है कि उसने भी स्वयं को संतुष्ट करने के बावत कि मरीज कथन करने की स्थिति में था और आरंभिक प्रश्न पूछे जाने के द्वारा समझ पाने की स्थिति में थी, सावधानी बरती थी और तत्पश्चात् ही मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया था। उसके साक्ष्य से प्रकट होता है कि अभिलिखित किए जाने के पूर्व और पश्चात् अभि. सा. 3 ने मरीज का परीक्षण किया था और उसके द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक कथन के शीर्ष और अंत में अनुमोदन दिया था। हम इस निवेदन में कि अभि. सा. 2 द्वारा की गई स्वीकृति कि उसने स्वयं मृत्युकालिक कथन में इस तथ्य को नहीं लिखा है कि उसने आरंभिक प्रश्न पूछे थे, निर्दिष्ट करता है कि अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य को मजबूत करने के प्रयोजनार्थ इस प्रकार की कहानी गढ़ी है। हमारा ऐसा मत इसलिए है चूंकि प्रदर्श-20 के कोरे परिशीलन से ही छह प्रश्न अभिलिखित किए जाने का प्रकटीकरण होता है जो आरंभिक प्रकृति

के हैं और इस समाधान पर पहुंचने के लिए कि आहत की मानसिक स्थिति स्थिर थी, अभि. सा. 2 के लिए उनके पर्याप्त होने को उपदर्शित करते हैं। अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य के दौरान इस सुझाव से विनिर्दिष्ट रूप से इनकार किया है कि मरीजों के नातेदार उसका कथन अभिलिखित किए जाते समय वार्ड में उपस्थित थे। अतः, उसके साक्ष्य की सूक्ष्मतापूर्वक संवीक्षा किए जाने के बाद भी हम अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं पाते जो उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बना दे। हम पुनः दोहराते हैं कि अभि. सा. 2 का साक्ष्य अभि. सा. 3 के साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से पुष्ट है और इसलिए भी किसी सीमा तक अभि. सा. 4 का साक्ष्य भी है। अतः, अभियोजन ने उसके साक्ष्य द्वारा अभिलेख पर सम्यक् रूप से साबित किया है कि उसके द्वारा अभिलिखित प्रदर्श-20 सत्य है और आहत द्वारा उसके समक्ष किए गए स्वैच्छिक मृत्युकालिक कथन है।

14. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने मृतक द्वारा किया गया सत्य स्वैच्छिक और विश्वसनीय मृत्युकालिक कथन प्रदर्श-20 और मृत्युकालिक कथन प्रदर्श-30 को निर्दिष्ट करते हुए दलील दी कि उनमें से किसी को भी नहीं माना जा सकता चूंकि वे अपीलार्थियों द्वारा निभाई गई किसी भूमिका में टकराव का प्रकटीकरण करते हैं। यह दलील दी गई कि प्रदर्श-20 प्रकट करता है कि मिट्टी के तेल का कैन अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा खरीदा गया था जबकि प्रदर्श-30 प्रकट करता है कि अपीलार्थी संख्या 1 ने अलमारी से रोकेल कैन उठाया था। दोनों मृत्युकालिक कथनों की सूक्ष्मतापूर्वक संवीक्षा किए जाने पर हम स्वयं को संतुष्ट कर पाने में असमर्थ हैं कि इस घटना में दोनों अपीलार्थियों द्वारा निभाई गई भूमिका के मध्य कोई अन्य बातों के साथ-साथ कोई टकराव विद्यमान है। हमारा यह विचार इसलिए है चूंकि यद्यपि मृत्युकालिक कथन, प्रदर्श-20 को निर्दिष्ट करने से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी संख्या 2 ने आरंभिकतः कैन क्रय की थी और इसके आगे के भाग से यह प्रकट होता है कि उससे कैरोसिन अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा आहत के कंधों पर डाला गया था और तत्पश्चात् अपीलार्थी संख्या 2 ने माचिस जलाई थी और उसके शरीर पर फेंक दी थी। मृत्युकालिक कथन, प्रदर्श-30 से प्रकट होता है कि इस मामले में इसी प्रकार की भूमिका अपीलार्थी संख्या 1 और अपीलार्थी संख्या 2 को इस अपवाद के साथ अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए की गई है कि वह इस बाबत मौन है कि आरंभिकतः किसने कैन को अलमारी से उठाया था। अतः दोनों मृत्युकालिक कथनों पर संपूर्णता में विचार करते हुए हम इस बाबत दी गई

दलीलों में कोई सार नहीं पाते कि इस घटना में दोनों मृत्युकालिक कथनों में अपीलार्थियों द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में टकराव, यहां तक कि अयुक्तियुक्त टकराव भी, जो उक्त मृत्युकालिक कथनों में से प्रत्येक के प्रभाव को नष्ट करने वाला था, समाविष्ट था। दोहराते हुए हम आगे कहते हैं कि दोनों मृत्युकालिक कथनों के आधार पर मामले पर विचार करते हुए यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि दोनों अपीलार्थी आहत के शरीर पर कैरोसिन डाले जाने के द्वारा और उसको जलाने के द्वारा उसको समाप्त करने के उनके सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य कर रहे थे। उक्त मृत्युकालिक कथन प्रकट करता है कि उक्त प्रक्रिया में आहत पर कैरोसिन अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा डाला गया था जबकि आहत के शरीर पर आग अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा जलती हुई माचिस की तीली फेंककर लगाई गई थी।

15. अब आहत द्वारा उसकी माता अर्थात् अभि. सा. 1 के समक्ष साक्ष्य किए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य पर विचार करते हुए उसके साक्ष्य को निर्दिष्ट करने पर प्रकट होता है कि उसके अभियोजन के पक्षकथन के सामंजस्य में अपीलार्थी संख्या 1 के साथ विवाह संपन्न होने की तारीख से शपथपूर्वक कथन किया है। चूंकि अभि. सा. 1 का साक्ष्य अभियोजन पक्षकथन के सामंजस्य में है जैसा कि पूर्व में वर्णित किया गया है। हम उक्त साक्ष्य को, सिवाय यह कहने के, कि अभि. सा. 1 ने विवाद जो उनके द्वारा आहत और अपीलार्थी संख्या 1 को दीपावली के त्यौहार के अवसर पर उनके घर आमंत्रित किए जाने के पश्चात् उत्पन्न हुआ था जब अपीलार्थियों द्वारा लगभग डेढ़ तोले के स्वर्णाभूषणों की मांग की गई थी, के बारे में शपथपूर्वक कथन किया है, दोहराना नहीं चाहते। ऐसा प्रकट होता है कि इस प्रकार की कोई मांग आहत के भाई और बहन, जो अपीलार्थियों के घर उनको दीपावली के त्यौहार के अवसर पर आमंत्रित करने के लिए गए थे, के समक्ष दोहराई गई थी। यह प्रकट होता है कि उक्त स्वर्णाभूषणों की मांग पूरी न किए जाने के कारण आहत को दीपावली के त्यौहार के अवसर पर अकेले ही भेज दिया गया था। यह प्रकट होता है कि उसके पश्चात् भी अपीलार्थी संख्या 1, जब उसको अभि. सा. 1 के घर आमंत्रित किया गया था और आहत के पिता-माता द्वारा उसको कपड़े देने का प्रयास किया गया था, आहत के साथ वापस लौट आया था। यह प्रकट होता है कि तब अपीलार्थी संख्या 1 स्वर्णाभूषण न दिए जाने के कारण वापस लौट आया था। उक्त साक्ष्य का विस्तारपूर्वक वर्णन किए बिना यह कहा जा सकता है कि उक्त मांग के पश्चात् अभि.

सा. 1 द्वारा मृतक का निरंतर उत्पीड़न किए जाने वाले वृत्तांत का प्रकटीकरण किया और सारिका के गर्भ में पलने वाले बच्चे के पैतृत्व के बारे में भी शंका उत्पन्न की गई थी। अभि. सा. 1 का साक्ष्य प्रकट करता है कि अभि. सा. 1 तारीख 22 फरवरी, 2005 को आहत को, चूंकि वह जल गई थी, ससून अस्पताल ले जाए जाने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अपने पति के साथ उक्त अस्पताल गई थी और तब आहत ने उसको बताया था कि उसके पति ने उसके शरीर पर कैरोसिन डाला और उसकी सास ने उसको जला दिया। हम संवीक्षा के पश्चात् इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि उक्त साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा है।

16. आहत के मृत्युकालिक कथन अर्थात् प्रदर्श-30, 20 और अभि. सा. 1 के समक्ष किए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य के अतिरिक्त हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं कि इस घटना में अपीलार्थियों द्वारा निर्वाह की गई भूमिका के संबंध में निरंतरता, जैसा कि प्रकटीकरण उक्त मृत्युकालिक कथन से होता है, के अतिरिक्त इस मामले में ऐसे अन्य साक्ष्य भी पाए गए हैं जिनका पुष्टिकरण स्थल पंचनामा और मृत्यु समीक्षा पंचनामा के रूप में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य पारिस्थितिक साक्ष्यों से होता है। मृत्यु समीक्षा पंचनामा के रूप में और साथ ही अपीलार्थी अर्थात् प्रतिरक्षा साक्षी 1 द्वारा दिया गया प्रतिरक्षा साक्ष्य के संदर्भ में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विचारण न्यायालय ने मृत्यु समीक्षा पंचनामा के विवरणों को नकारे जाने के लिए पैराग्राफ 16 से 18 में तर्कपूर्ण कारण दिए हैं कि स्टोव की लपटों के भड़क जाने के कारण सारिका जल गई थी और यह प्रतिरक्षा साक्षी 1 द्वारा दिया गया प्रतिरक्षा पक्ष का साक्ष्य है। उक्त विवेचन पर सतर्कतापूर्वक विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत्यु समीक्षा पंचनामा से उक्त विवरण उक्त पंचनामा के आधार पर ठीक ही अस्वीकृत किया गया था चूंकि उक्त पंचनामा उक्त विवरण के बारे में पुलिस की जानकारी का स्रोत प्रकट करने में विफल रही। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतिरक्षा साक्षी 1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को अभिलेख पर लाए कि प्रतिरक्षा साक्षी 1 ने, जब घटना के दिन तुरंत अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान उसका कथन अभिलिखित किया गया था, इस तथ्य से पुलिस को अवगत नहीं कराया था कि सारिका ने दुर्घटनावश जल जाने वाली क्षतियां बरदाश्त की थीं। हम विचारण न्यायालय द्वारा सारिका के दुर्घटनावश जल जाने वाली क्षतियां

बरदाश्त किए जाने वाले मत को नकारे जाने के प्रयोजनार्थ अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित विवेचना में कोई त्रुटि पाने में असमर्थ हैं ।

17. अब हम **शेख बक्शन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**¹ वाले मामले को निर्दिष्ट करते हैं जिसका अवलंब अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा लिया गया है और पैराग्राफ 8 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि “मृत्युकालिक कथन में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि वह मृतक को पढ़कर सुनाया गया था । विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि यह अभिकथित नहीं किया गया है, यह धारणा की जाती है कि इसको पढ़कर सुनाया और समझाया गया था । यह विचार स्पष्टतः अस्वीकार्य है ।” तथापि, यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त मताभिव्यक्ति से अपीलार्थियों को उक्त पहलुओं, जिन पर ऊपर चर्चा की गई है, के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में कोई सहायता प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त उक्त विनिश्चय से यह प्रकट नहीं होता कि मात्र उक्त आधार पर ही उक्त मामले में मृत्युकालिक कथन स्वीकार नहीं किए गए थे । वास्तविकता यह है कि पैराग्राफ 9 में किए गए विवेचन के परिशीलन से उस मामले में अन्तर्वलित मृत्युकालिक कथन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित शिथिलताओं की संख्या प्रकट होती है और इन शिथिलताओं के कारण यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियोजन ने मामले को साबित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति वर्तमान मामले में अन्तर्वलित मृत्युकालिक कथन के साथ न पाए जाने के कारण उक्त विनिश्चय में किया गया निदेश अपीलार्थियों के लिए किसी उद्देश्यपूर्ण प्रयोजन की प्राप्ति हेतु सहायक नहीं है ।

18. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील देने का प्रयास किया कि चूंकि सम्पूर्ण घटना में मुकुंद बोराड़े का आहत के घर मिलने आने का तथ्य सुसंगत था, उक्त साक्षी और/या सारिका के भाई और बहन अर्थात् समीर और शिल्पा, जो दीपावली के त्यौहार के अवसर पर आमंत्रित करने के लिए अपीलार्थियों के घर गए थे और चचेरी सास गंगूबाई जो आहत के साथ अस्पताल गई थी, का परीक्षण न कराए जाने के द्वारा अभियोजन ने तात्त्विक साक्ष्य को छिपाया है और मृतक के पिता-माता की

¹ 2007 (2) बम्बे सी. आर. (क्रिमिनल) 332 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4120.

एक तरफा कहानी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उनके द्वारा यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने उक्त संदर्भ में इस तथ्य से भी अनदेखा किया कि अपीलार्थी संख्या 1 भी घटना के दौरान जल गया था। उनके द्वारा यह दलील दी गई कि उक्त साक्षी का परीक्षण न किए जाने के कारण प्रतिरक्षा पक्ष अभिलेख पर यह साबित कर पाने में वंचित हो गया है कि मृतक के मृत्युकालिक कथन सिखलाया गया वृत्तांत है और सत्य और विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने यह दलील दी कि यह तथ्य कि अपीलार्थी सं. 2 आहत को अस्पताल ले गया था और उसने स्वयं भी जलन की क्षतियां बरदाश्त की थीं, भी अभियोजन पक्षकथनानुसार उसके द्वारा निर्वाह की गई भूमिका, जिसका दावा अभियोजन द्वारा किया गया है, के प्रतिकूल है।

19. यह वास्तव में सत्य है कि अभियोजन ने उन साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया है जिनकी ओर विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा संकेत किया गया है। तथापि, वर्ष 1957 में वादी **वेलू थेवड़** बनाम **मद्रास राज्य**¹ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया विनिश्चय पैराग्राफ 11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की :—

“11. विवेचना को दृष्टि में रखते हुए हमको यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह दलील कि न्यायालय को हत्या के किसी मामले में साक्षियों की बहुसंख्या पर जोर देना चाहिए, अत्यधिक बढ़ाचढ़ा कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अधीन सुस्पष्टतया अधिकथित किया गया है कि “किसी मामले में किसी विशिष्ट संख्या में साक्षी किसी तथ्य को साबित किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे,” विधान-मंडल ने काफी पहले अर्थात् 1872 में संभाव्यतः समस्त पहलुओं पर विचारोपरांत अभिनिर्धारित कर दिया था कि किसी तथ्य को साबित या नासाबित किए जाने के लिए आवश्यक नहीं होगा कि किसी विशिष्ट संख्या में साक्षियों को बुलाया जाए। इंग्लैंड में 1972 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किए जाने के पूर्व और पश्चात् अनेक कानून बनाए गए जैसा कि सरकार के “ला आफ इविडेन्स” 9वां संस्करण पृष्ठ 1100-1101 पर किसी एकल साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि किए जाने से इनकार किए जाने को वर्णित किया गया है। भारतीय विधान-मण्डल

¹ ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614.

ने भी ऊपर धारा 134 के अधीन सामान्य नियम में ऐसा कोई अपवाद अधिकथित किए जाने पर जोर नहीं दिया है। यह धारा इस सुस्थापित सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करती है कि “साक्ष्य को अस्पष्ट होना चाहिए और गणना किए जाने योग्य नहीं होना चाहिए।” हमारे विधान-मंडल ने इस तथ्य को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की है कि न्याय का प्रशासन बाधित हो सकता है यदि किसी विशिष्ट संख्या में साक्षियों पर जोर दिया जाता है। यह अनायास नहीं है कि कोई अपराध, उन मामलों को छोड़ते हुए जो असामान्य रूप से घटित होने वाले नहीं हैं और जहां दोषिता का विनिर्धारण पूर्णतया पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर होता है, मात्र एक साक्षी की उपस्थिति में कारित किया गया हो। यदि विधान-मंडल का आशय साक्षियों की बहुसंख्या पर जोर देना होता तो वे मामले जिनमें मात्र एक साक्षी का परिसाक्ष्य अपराध के सबूत के रूप में उपलब्ध हो सकता, दंडित नहीं किए जा सकेंगे। यही वह स्थिति है जिसमें पीठासीन न्यायाधीश का विवेकाधिकार महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः साक्ष्य प्रत्येक मामले की परिस्थिति और एकल साक्षी जिसका परिसाक्ष्य या तो स्वीकार किया जाना है या अस्वीकृत किया जाना है, के साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर होना चाहिए। यदि ऐसे किसी परिसाक्ष्य को न्यायालय द्वारा पूर्णतया विश्वसनीय पाया जाता है, तो ऐसे सबूत के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि में कोई विधिक बाधा नहीं होती। यहां तक कि किसी अभियुक्त की दोषिता किसी एकल साक्षी के परिसाक्ष्य द्वारा भी साबित की जा सकती है, किसी अभियुक्त की निर्दोषिता किसी एकल साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर भी स्थापित की जा सकती है, चाहे बड़ी संख्या में साक्षी अभियोजन की ओर से मामले की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए पेश किए गए हों। इसलिए, हमारे विचार में यह विधि का ठोस और सुस्थापित नियम है कि न्यायालय किसी तथ्य को साबित या नासाबित किए जाने के लिए आवश्यक साक्ष्य की गुणवत्ता से सम्बद्ध होती है कि साक्ष्य की प्रमात्रा से इस संदर्भ में मौखिक परिसाक्ष्य को सामान्यतया तीन कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् –

- (1) पूर्णतया विश्वसनीय,
- (2) पूर्णतया अविश्वसनीय,

(3) न तो पूर्णतया विश्वसनीय और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय ।’

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया)

पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों के प्रकाश में उन घटनाओं पर विचार करते हुए जिनमें उक्त साक्षियों, जिनकी ओर विद्वान् काउंसेल द्वारा संकेत किए गए पक्ष थे, हम यह स्वीकार कर पाने में असमर्थ हैं कि उक्त साक्षियों, जिनका परीक्षण घटना को साबित किए जाने के लिए अभियोजन द्वारा किया जाना आवश्यक था और परिणामस्वरूप अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे, को महत्वपूर्ण साक्षी कहा जा सकता है। हमारा ऐसा विचार इसलिए है चूंकि विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल हमको संतुष्ट कर पाने में असमर्थ हैं कि अभियोजन के वृत्तांत का कौन सा भाग उक्त साक्षियों के परीक्षण द्वारा विचारण के समय अप्रकटित रह गया था। अतः, हम उक्त दलील को अस्वीकृत करते हैं।

19.1 अपीलार्थी संख्या 1 के संबंध में दी गई दलील कि उसे दाह क्षतियां पहुंचने के संबंध में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा बरदाश्त की गई क्षतियों की प्रकृति के अभिलेख पर लाने के प्रयोजनार्थ प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि अभि. सा. 4 ने शपथपूर्वक कथन किया था कि उसने उसको चिकित्सीय परीक्षण के लिए राजगुरु नगर के ग्रामीण अस्पताल भेजा था, अपीलार्थी संख्या 1 के चिकित्सीय प्रमाणपत्र को अभिलेख पर लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह चिकित्सीय प्रमाणपत्र इस तथ्य पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डाल सकता था कि क्या अपीलार्थी संख्या 1 ने वास्तव में आग बुझाने का प्रयास किया था और क्या उक्त प्रक्रिया में उसको उक्त क्षतियां कारित हुई थीं। प्रतिरक्षा पक्ष का उक्त आचरण के कारण उनके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना अपेक्षित है चूंकि इस साक्ष्य को जानबूझकर अभिलेख पर नहीं लाया गया। चूंकि वह प्रतिरक्षा पक्ष के प्रतिकूल हो जाती। हमारा यह विचार इसलिए है कि चूंकि अपीलार्थी संख्या 1 की घटना के दौरान कुछ मामूली क्षतियां बरदाश्त करने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अभिलेख सिवाय अपीलार्थी संख्या 1 के कोरे शब्द, इस बात का प्रकटीकरण नहीं करते कि उसने कुछ जल जाने वाली क्षतियां बरदाश्त की थीं। परिणामतः, हम उक्त निवेदन में कोई गुणागुण नहीं पाते।

20. अंततः, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि घटना पति और पत्नी के मध्य अचानक हुए लड़ाई-झगड़े के कारण घटित हुई थी। उन्होंने यह दलील दी कि साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि दोनों अपीलार्थियों ने झगड़े के दौरान क्रोधवश कार्य किए थे। उन्होंने दलील दी कि उन दोनों में से किसी का आशय सारिका की हत्या कारित करने का था। उन्होंने दलील दी कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों के द्वारा क्रोधवश कार्रवाई किए जाने के पश्चात् स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो गई और सारिका को जल जाने वाली क्षतियां कारित हो गई। उन्होंने दलील दी कि सारिका को अस्पताल ले जाने का आगे का कार्य इस बात का सूचक है कि उसका आशय सारिका की हत्या कारित करने का नहीं था। उन्होंने दलील दी कि इसीलिए अपीलार्थी के हाथों घटित हुआ अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 या भाग-1 के अधीन अपराध से बढ़कर नहीं होगा।

21. मृत्युकालिक कथनों, जिनको हम सत्य, विश्वसनीय और स्वैच्छिक पाते हैं, में समाविष्ट सामग्री पर सतर्कतापूर्वक विचार करने के पश्चात् हम उपरोक्त निवेदनों में कोई बल पाने में असमर्थ हैं। अपीलार्थी संख्या 2 के संबंध में हम ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाते कि वह किसी झगड़े की पक्षकार थी। यहां तक कि अपीलार्थी संख्या 1 के संबंध में भी हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि साक्ष्य के आधार पर दर्शित होता है कि आहत उसके साथ झगड़ा नहीं कर रही थी। वास्तविकता यह है कि उक्त मृत्युकालिक कथनों में समाविष्ट सामग्री के आधार पर स्पष्ट शब्दों में यह प्रकटीकरण होता है कि यह अवेक्षित करने के पश्चात् कि मुकुंद बोराडे घर से निकला जा रहा है, अपीलार्थी संख्या 1 ने मृतक के साथ लड़ाई-झगड़ा करना आरंभ कर दिया था और वह उससे पूरे दिन झगड़ता रहा था। आगे यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि उक्त झगड़ा अकस्मात् हुआ झगड़ा नहीं कहा जा सकता। मृतक के साथ गाली-गलौज किए जाने और उसको पीटे जाने का कार्य निरंतर चलता रहता था, यह तथ्य न केवल मृत्युकालिक कथनों में, समाविष्ट तथ्यों से बल्कि अभि. सा. 1 के साक्ष्य से भी स्पष्ट है। दोहराते हुए हम अभिनिर्धारित करते हैं कि उक्त दिवस को घटित हुई घटना पर विचार करने के पश्चात् यह महसूस किया जाना कठिन है कि इस घटना से आहत झगड़ा कर रही थी। इसके अतिरिक्त वे मामले जिनका प्रकटीकरण मृत्युकालिक कथनों से होता है, ये हैं कि अपीलार्थी सं. 2 के उक्त स्थान पर आने और लड़ाई-झगड़े का कारण

पूछने और अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा मुकुंद के आगमन के बारे में प्रकटीकरण किए जाने और यह घोषणा किए जाने के पश्चात् कि वह सारिका के गर्भ में पलने वाले बच्चे का पिता नहीं है, अपीलार्थी संख्या 2 ने उसको आहत को समाप्त कर देने के लिए उकसाया था। साक्ष्य से प्रकट होता है कि उन लोगों द्वारा आहत को पकड़ लिया गया था, कैरोसिन लाया गया था और अपीलार्थी संख्या 1 ने आहत के शरीर पर कैरोसिन डाला था और अपीलार्थी संख्या 2 ने आहत के शरीर पर जलती हुई माचिस की तीली फेंकी थीं। इसके विपरीत मृत्युकालिक कथन प्रदर्श-20 से प्रकट होता है कि अपीलार्थी संख्या 2 रसोई के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा था और उसने रसोई के दरवाजे को बंद कर दिया था जिससे कि मृतक को रसोई से बाहर आने से रोका जा सके। इससे प्रकट होता है कि आग को आहत द्वारा रजाई का प्रयोग करके बुझाया गया था न कि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा। यह समस्त साक्ष्य निश्चित रूप से दर्शित करते हैं कि अपीलार्थियों द्वारा कारित कार्य को ऐसा कार्य नहीं कहा जा सकता जो उनके हाथों से क्रोधवश घटित हो गया था। इसके विपरीत साक्ष्य से दर्शित होता है कि यह सभी कार्य सोच-समझकर किए गए कार्य थे। हम इन कार्यों और उनके द्वारा कारित कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार कर पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं कि अपीलार्थी मृतक की हत्या कारित किए जाने के आशय नहीं रखते थे। अतः, हम ऊपर वर्णित तर्कपूर्ण कारणोंवश विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाते।

22. परिणामस्वरूप, हम इस अपील में गुणागुण नहीं पाते और इसको खारिज करते हैं।

अपील खारिज की गई।

शु.

सीताराम हीरामन जोपाले

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

तारीख 20 जून, 2013

न्यायमूर्ति (श्रीमती) वी. के. ताहिलरमानी और न्यायमूर्ति पी. डी. कोडे

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 84 – विकृत चित्तता – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने के पूर्ववर्ती और पश्चात्पूर्वक समय के आचरण, की गहनतापूर्वक संवीक्षा से यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त, वह कार्य जो वह कर रहा है की प्रकृति दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, वहां अभियुक्त विकृत चित्तता का फायदा पाने का दायी होगा ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 106 – सबूत का भार – जब अभियुक्त को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया हो और अभियुक्त हत्या के ठीक पश्चात् घटनास्थल से भाग गया तथा मृतक के रक्त के धब्बे अभियुक्त के कपड़ों पर पाए गए हों तो उक्त धारा के अधीन अपनी निर्दोषिता सिद्ध न कर पाने की दशा में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित और तर्क संगत है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक भारती का विवाह अपीलार्थी के साथ घटना के 15 वर्ष पूर्व हुआ था । उनके दो पुत्रियां और एक पुत्र है । अपीलार्थी बेरोजगार था । उसके पास जमीन का एक टुकड़ा था किंतु वह उस पर खेतीबाड़ी नहीं कर रहा था । अतः भारती अपने पिता पालवी को जमीन पर खेतीबाड़ी में सहायता के लिए बुलाती रहती थी । वह अपने पिता को यह भी बताती रहती थी कि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और उसको जान से मार देने की धमकी देता रहता है । तारीख 7 जुलाई, 2005 को पालवी अपनी पुत्री भारती और अपीलार्थी के घर आया था । रात्रि भोजन के पश्चात् भारती, उसके अवयस्क बच्चे, अपीलार्थी और पालवी एक ही कमरे में सो गए थे । पालवी अपने बेटी दामाद से कुछ दूरी पर सो रहा था । प्रातः काल 4.30 बजे भारती की बेटी मंगल जोर से चीखी जिस पर पालवी की नींद टूट गई । उसने देखा कि भारती के गले के दाहिनी ओर क्षति है जिससे रक्त बह रहा है और उसके

पास एक रक्तरंजित कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। उसने यह भी देखा कि उसका दामाद दरवाजे की ओर जा रहा है। उसने यह भी पाया कि भारती की मृत्यु हो चुकी है। तत्पश्चात् उसने अपीलार्थी का पीछा किया और उसको खोजने का प्रयास किया, किंतु वह उसको खोज नहीं सका। तत्पश्चात् उसने घटना के बारे में अपीलार्थी के पिता हीरामन को सूचित किया और मामले की सूचना पुलिस को दी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई। अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए। अपीलार्थी ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण का सामना करने का दावा किया। अपीलार्थी की प्रतिरक्षा का मुख्य आधार यह था कि वह घटना के समय उन्मत्त था। आनुकल्पिक रूप से उसकी प्रतिरक्षा का आधार यह भी था कि किसी अन्य व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया और उसकी पत्नी भारती की हत्या कर दी। विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने तारीख 30 जून, 2009 का आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट कर दिया। उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील फाइल की गई। उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपराध कारित किए जाने के समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति के बाबत विश्वसनीय साक्ष्य की अनुपस्थिति में विक्षिप्त होने के अभिवाक् का कोई महत्व नहीं है। समान रूप से यह तथ्य कि अभियुक्त-घटना के पश्चात् स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं था का यह अर्थ नहीं है कि वह घटना के समय विकृत चित्त का था। किसी भी स्थिति में सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती परिस्थितियों और वे परिस्थितियां जो बाद में उत्पन्न हुईं पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में यह देखा गया है कि अपीलार्थी ने घटना के पूर्व विकृतचित्त का व्यक्ति होने का कोई लक्षण दर्शित नहीं किया था। अभि. सा. 2 पालवी अपीलार्थी के घर में निवास कर रहा था। यदि अपीलार्थी ने विकृत चित्त का व्यक्ति होने का कोई लक्षण दर्शित किया था, तो अभि. सा. 2 पालवी को इसके बाबत शपथपूर्वक कथन करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, किसी भी ग्रामीण ने, जिसका परीक्षण किया गया है, ने अभि-कथित नहीं किया है कि अपीलार्थी घटना के तुरंत पहले अस्वस्थ चित्त का व्यक्ति था। एक अन्य तथ्य जिसको ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, यह है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से आक्रमण करने के तुरंत पश्चात् घर से भाग गया था और गायब हो गया था। अपीलार्थी को उसका ससुर अभि. सा. 2 पालवी नहीं खोज सका था। घटना के तुरंत

पश्चात् भाग जाने का कार्य दर्शित करता है कि अपीलार्थी स्वयं द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति और उसके परिणामों के बारे में जानता था। जब यह दर्शित किए जाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभियुक्त की ज्ञानात्मक क्षमताएं दुर्बल हो गई हैं जिस कारणवश वह इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि उस कार्य के परिणाम क्या होंगे जो वह कर रहा है, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 अनुप्रयोज्य हो जाएंगी। अपराध के किए जाने के समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति के संबंध में सबूत का भार अभियुक्त पर ही होता है। यह भार उसकी स्वस्थचितता के बारे में संदेह के सृजन भाव द्वारा उन्मोचित नहीं हो सकता। अभियुक्त को उन तथ्यों और परिस्थितियों को साबित करना चाहिए जिनके आधार पर यह न्यायालय युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगा सके कि अभियुक्त अपराध के किए जाने के समय अस्वस्थचितता के कारणवश कार्य की प्रकृति, कार्य की वैधता या इस बात को कि उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य गलत है या सही, जानने में असमर्थ था। यह प्रस्तुत मामले में नहीं किया गया। जैसा कि पहले अभिकथित किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का अनुपालन करने के लिए जिससे कि किसी व्यक्ति को दांडिक दायित्व से मुक्त किया जा सके, वह कार्य जिसकी शिकायत की गई है, की पूर्ववर्ती और पश्चात्वर्ती अवधि में अभियुक्त का आचरण और साथ ही कार्य के दौरान और पश्चात् आचरण, सभी की सूक्ष्मतापूर्वक संवीक्षा की जानी चाहिए। जय लाल बनाम दिल्ली प्रशासन वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 84 का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त द्वारा निश्चायक रूप से यह साबित किया जाना चाहिए कि वह घटना के समय उन्मत्त था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने, अपीलार्थी की ओर से किए गए निवेदनों और हत्या की घटना के घटित होने और बाद वाली सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत हम यह विचार कर पाने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी अधिसंभाव्यता की गुरुता को स्थापित किए जाने के द्वारा उसके ऊपर अधिरोपित इस भार का निर्वहन कर पाने में सफल रहा है कि वह अपराध कारित करते समय विधिक अस्वस्थचितता से ग्रसित था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य इस मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलार्थी ने उन्मत्तता को प्रतिरक्षा, जिसका आशय उसी के द्वारा लिया गया है, को साबित नहीं किया है। (पैरा 11, 12, 13 और 14)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2006]	(2006) 12 ए. सी. सी. 254 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 144 : राजस्थान राज्य बनाम काशीराम ;	7
[1969]	ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 15 : जय लाल बनाम दिल्ली प्रशासन ।	13

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील संख्या 873.

2005 के सेशन मामला संख्या 181 में नासिक के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 30 जून, 2009 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्रीमती नसरीन एस. के. अयूबी
राज्य की ओर से	पी. एस. हीगोरानी, (सहायक अभियोजक अधिकारी)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) वी. के. ताहिलरमानी ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) ताहिलरमानी – अपीलार्थी-मूल अभियुक्त ने यह अपील 2005 के सेशन मामला संख्या 181 में नासिक के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 30 जून, 2009 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की । उक्त निर्णय और आदेश द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के द्वारा दंडादिष्ट किया और जुर्माने के संदाय से चूक होने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना था ।

2. संक्षेप में अभियोजक का पक्षकथन इस प्रकार है :-

“मृतक भारती अभि. सा. 2 पालवी की पुत्री है । भारती का विवाह अपीलार्थी के साथ घटना के 15 वर्ष पूर्व हुआ था । उनके 2 पुत्रियां और एक पुत्र हैं । अपीलार्थी कुछ नहीं कर रहा था और वह बेरोज़गार था । अपीलार्थी के पास जमीन का एक टुकड़ा था किंतु वह उस पर खेतीबाड़ी नहीं कर रहा था । अतः अपीलार्थी की पत्नी भारती अपने पिता अभि. सा. 2 पालवी को जमीन पर खेतीबाड़ी में

उसकी सहायता के लिए बुलाती रहती थी। भारती अपने पिता अभि. सा. 2 पालवी को बताती रहती थी कि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है वह उसको जूतों से पीटता है और उसे जान से मारने की धमती देता है।

तारीख 7 जुलाई, 2005 को अभि. सा. 2 पालवी अपनी पुत्री भारती और अपीलार्थी के घर आया था चूंकि भारती ने उसको खेतीबाड़ी में सहायता के लिए बुलाया था। उस दिन भारती और अभि. सा. 2 पालवी ने खेत में चावल बोए थे। वे लगभग 7 बजे सायं घर वापस आ गए थे। भोजन करने के पश्चात् वे सभी अर्थात् भारती, उसके अवयस्क बच्चे, अपीलार्थी और अभि. सा. 2 पालवी एक कमरे में सो गए। अभि. सा. 2 पालवी अपनी बेटी और दामाद से कुछ दूरी पर सो रहा था।”

3. प्रातः काल लगभग 4.30 बजे अभि. सा. 2 की नातिन मंगल जोर से चीखी, इस पर अभि. सा. 2 की नींद टूट गई। उसने देखा कि उसकी पुत्री भारती के गले के दाहिने ओर क्षति पहुंची थी जिससे रक्त बह रहा था और उसके पास एक रक्तरंजित कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। उसी समय अभि. सा. 2 पालवी ने देखा कि उसका दामाद दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। अभि. सा. 2 ने पाया कि उसकी पुत्री भारती की मृत्यु हो चुकी है। तत्पश्चात् उसने अपीलार्थी का पीछा किया और उसको खोजने का प्रयास किया किंतु वह उसको खोज नहीं सका। तत्पश्चात् अभि. सा. 2 पालवी ने घटना की सूचना हीरामन जो अपीलार्थी का पिता है, और पुलिस को दी। पुलिस थाना गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जो प्रदर्श 32 है। अन्वेषण आरंभ हुआ। शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेज दिया गया। अभि. सा. 7 डा. मोहनदास ने भारती के शव की मरणोत्तर परीक्षा की। भारती के शरीर पर निम्नलिखित बाह्य क्षतियां पाई गई :-

“(i) ग्रीवा के बाईं ओर गुमटायुक्त विदीर्ण घाव है जो अधोहनु के मध्य भाग से लेकर हंसुली के पार्श्विक भाग तक फैला हुआ है जिसकी दिशा तिरही और तर्कुवाकार है। घाव के किनारे विदीर्ण हैं जिसकी माप 13 से. मी. X 5 से. मी. है और इस घाव की गहराई कशेरुका तक है तथा इसमें रक्त का थक्का मौजूद है। माजका धमनी और अन्य धमनियां कटी हुई हैं।

(ii) अधोहनु के मध्य भाग में 3 से. मी. X 1 से. मी. माप का अस्थिभंग है।

(iii) ग्रैव कशेरुका में अस्थिभंग है ।

चिकित्सक की राय में मृत्यु का कारण रक्तस्राव से होने वाला आघात है और यह रक्तस्राव ग्रीवा में गहरी क्षति पहुंचने से और ग्रैव कशेरुका में अस्थिभंग होने के परिणामस्वरूप हुआ है । अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया ।’

3क. अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए । अपीलार्थी ने निर्दोष होने का अभिवाक् और विचारण का सामना करने का दावा किया । अपीलार्थी की प्रतिरक्षा सम्पूर्ण इनकारी और उसको मामले में असत्य रूप से संलिप्त किए जाने की है । अपीलार्थी की आगे प्रतिरक्षा यह है कि वह घटना के समय उन्मत्त था । अपीलार्थी द्वारा आनुकल्पिक प्रतिरक्षा यह भी की गई है कि किसी अन्य व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया और भारती की हत्या कर दी । इस मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रतिरक्षा कथन का परिशीलन करने के पश्चात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट कर दिया जैसाकि ऊपरी पैरा में अभिलिखित है, अतः यह अपील फाइल की गई ।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य के विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना । हमने विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश और इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य का सतर्कतापूर्वक परिशीलन किया । मामले पर सतर्कतापूर्वक विचार करने के पश्चात् हमारा मत है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी भारती के गले पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया था और उसकी मृत्यु कारित कर दी थी ।

5. आरंभतः हम अभिकथित करते हैं कि इस तथ्य को कि भारती की हत्या मानव वध थी, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा विवादित नहीं किया गया है । इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और मामला मुख्यतः अभि. सा. 2 पालवी के साक्ष्य पर निर्भर है जो अपीलार्थी का ससुर और मृतक भारती का पिता है । अभि. सा. 2 पालवी ने अभिकथित किया है कि मृतक भारती उसकी पुत्री थी । भारती का विवाह घटना के लगभग 15 वर्ष पूर्व अपीलार्थी के साथ हुआ था । उनकी 2 पुत्रियां और एक पुत्र थे । अपीलार्थी कुछ नहीं कर रहा था और बेरोज़गार था । अपीलार्थी के पास कुछ भूमि थी किंतु वह उस पर खेतीबाड़ी नहीं कर रहा था । अतः,

इसलिए अपीलार्थी की पत्नी भारती अपने पिता अभि. सा. 2 पालवी को भूमि पर खेतीबाड़ी में सहायता करने के लिए बुलाती रहती थी। भारती अपने पिता अभि. सा. 2 पालवी से कहती रहती थी कि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। वह उसको जूतों से पीटता है और उसको जान से मारने की धमकी देता है। तारीख 7 जुलाई, 2005 को अभि. सा. 2 पालवी अपनी पुत्री भारती और अपीलार्थी के घर आया था चूंकि भारती ने उसको खेतीबाड़ी में सहायता के लिए बुलाया था। उस दिन भारती और अभि. सा. 2 पालवी ने खेत में चावल की बुआई की थी। अभि. सा. 2 पालवी सायं काल लगभग 7 बजे वापस आ गया था। भोजन करने के पश्चात् वे सभी अर्थात् भारती, उसके अव्यस्क बच्चे, अपीलार्थी और अभि. सा. 2 पालवी एक ही कमरे में सो गए थे। अभि. सा. 2 पालवी अपीलार्थी और भारती से कुछ दूरी पर सो रहा था। प्रातः काल 4.30 बजे अभि. सा. 2 पालवी की नातिन मंगल जोर से चीखी जिससे अभि. सा. 2 पालवी जाग गया उसने देखा कि उसकी पुत्री भारती के गले के दाहिनी ओर क्षति है जिससे रक्त बह रहा है और उसके निकट एक रक्तरंजित कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। उसी समय अभि. सा. 2 पालवी ने देखा कि उसका दामाद दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। अभि. सा. 2 ने पाया कि उसकी पुत्री भारती की मृत्यु हो चुकी है। अभि. सा. 2 पालवी ने अपीलार्थी का पीछा किया और उसको खोजने का प्रयास किया किंतु वह अपीलार्थी को नहीं पा सका। तत्पश्चात् अभि. सा. 2 पालवी ने घटना की सूचना प्रतिरक्षा साक्षी 1 हीरामन को दी जो अपीलार्थी का पिता है और पुलिस को भी घटना की सूचना दी। तत्पश्चात् अभि. सा. 2 पालवी पुलिस थाना गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जो प्रदर्श 32 है।

6. अतः, अभि. सा. 2 पालवी के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि घटना की रात भारती, अपीलार्थी, भारती के अव्यस्क बच्चे और अभि. सा. 2 पालवी घर में थे। उसके साक्ष्य से दर्शित होता है कि प्रातःकाल लगभग 4.30 बजे जब वह शोर सुनकर जागा तो देखा कि भारती के गले के दाहिने ओर क्षति कारित हुई है और रक्तरंजित कुल्हाड़ी उसके पास पड़ी हुई है। उसी समय उसने देखा कि अपीलार्थी दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। अभि. सा. 2 पालवी ने देखा कि उसकी पुत्री भारती की मृत्यु हो चुकी है। तत्पश्चात् उसने अपीलार्थी का पीछा किया और उसको खोजने का प्रयास किया किंतु वह अपीलार्थी को खोज नहीं पा सका। अतः अभि. सा. 2 पालवी के साक्ष्य से दर्शित होता है कि घटना के समय अपीलार्थी और

मृतक घर में थे और उसके तुरंत पश्चात् भारती गले पर क्षति के साथ मृत पाई गई थी, अपीलार्थी घर से भाग गया था और उसको खोजा नहीं जा सका था। मामले को इस दृष्टि से देखते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रभाव में आती है।

7. अभि. सा. 2 पालवी के साक्ष्य से दर्शित होता है कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी के साथ उनके घर में जीवित देखा गया था ऐसे मामले में अपीलार्थी-अभियुक्त को स्पष्ट करना था कि भारती को क्षतियां कैसे कारित हुईं और उसकी मृत्यु कैसे हुई। इस संबंध में हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को निर्दिष्ट करेंगे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उपबंधित करती है कि जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति की जानकारी में विशेष रूप से आता है तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है। उनके नवीनतम विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वे सिद्धान्त जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को रेखांकित करते हैं, अंतिम बार देखे जाने के सिद्धान्त के संबंध में लागू किए जा सकते हैं जब कतिपय तथ्य व्यक्ति की जानकारी में विशेष रूप से हों। **राजस्थान राज्य बनाम काशीराम¹** वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की कि यदि अभियुक्त अपनी जानकारी मामले के तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 द्वारा अधिरोपित भार का निर्वहन करने में विफल होता है। कोई ऐसा मामला जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो, यदि अभियुक्त उसके ऊपर लागू साबित करने के भार का निर्वहन करने में विफल होता है। कोई ऐसा मामला जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो, यदि अभियुक्त उसके ऊपर लागू भार में निर्वहन में युक्ति संगत स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो इससे स्वतः उसके विरुद्ध साबित परिस्थितियों की शृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी सम्मिलित हो जाती है। धारा 106 किसी दांडिक विचारण में सबूत के भार को अंतरित नहीं करती, यह सदैव अभियोजन पर होता है। यह धारा इस नियम को अधिकथित करती है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर प्रकाश नहीं डालता जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं और जो उसकी निर्दोषिता के साथ संगत किसी सिद्धान्त या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकते, तो न्यायालय किसी अतिरिक्त कड़ी, जो शृंखला को पूर्ण करती हो, के रूप में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न कर पाने में उसकी विफलता पर विचार कर सकता है।

¹ (2006) 12 एस. सी. सी. 254 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 144.

8. अपीलार्थी का घटना के पश्चात् भाग जाने का आचरण भी उसकी दोषिता को दर्शित करता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन अभि. सा. 5 जो पंच साक्षी गोविन्द बर्डे है, के साक्ष्य का अवलंब ले रहा है। इस साक्षी ने शपथपूर्वक रक्तरंजित कमीज़ के अभिग्रहण के बारे में कथन किया है जिसको गिरफ्तारी के समय अपीलार्थी ने पहन रखा था। उक्त कमीज़ के अभिग्रहण के संबंध में पंचनामा प्रदर्श 40 है। इस कमीज़ पर रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट के अनुसार समूह 'ओ' के रक्त के निशान पाए गए थे इससे दर्शित होता है कि मृतका के रक्त के समूह का रक्त के निशान अपीलार्थी के कपड़ों पर पाए गए थे। यह अत्यधिक फंसाने वाली परिस्थितियां हैं जो मजबूती के साथ अपीलार्थी के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त अभियोजन ने अभिलेख पर हत्या कारित करने के अपीलार्थी के आशय को भी प्रस्तुत किया गया है। अभि. सा. 2 पालवी जो मृतक भारती का पिता है ने अभिकथित किया है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी भारती के साथ दुर्व्यवहार करता था। अपीलार्थी भारती को मारता पीटता था और उसे उसको जान से मारने की धमकी देता था।

9. अपीलार्थी द्वारा ली गई एक प्रतिरक्षा यह है कि कोई अन्य व्यक्ति मकान में प्रविष्ट हुआ और उसकी पत्नी भारती की हत्या कर दी। जहां तक इस प्रतिरक्षा का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि अभि. सा. 2 पालवी के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी, अभि. सा. 2 पालवी, अपीलार्थी के अव्यस्क बच्चे और मृतक घर में थे। वे घर के एक ही कमरे में सो रहे थे। यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी के घर में कोई डकैती हुई थी या डकैती करने का कोई प्रयास किया गया था। इसके अतिरिक्त अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि भारती की किसी के साथ दुश्मनी थी जिसके कारण वह व्यक्ति उसकी हत्या कर देता। यदि कोई घुसपैठिया अपीलार्थी के घर में प्रविष्ट हुआ था तो घर के सदस्यों को इस बारे में पता चलना चाहिए था। घर के सदस्य दरवाज़े को खुला छोड़ कर सोने के लिए नहीं आ सकते थे। जब वह सोने के लिए जाते तो नैसर्गिक रूप से दरवाज़े को बंद कर देते। ऐसी स्थिति में यह असंभव है कि कोई तीसरा व्यक्ति घर में प्रवेश करता है और भारती की हत्या करता। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह प्रतिरक्षा सत्याभासी प्रतीत नहीं होती।

10. आपीलार्थी द्वारा उठाया गया द्वितीय प्रतिरक्षा बिंदु यह है कि वह

घटना के समय स्वस्थ नहीं था। उसने अभिलेख पर अभि. सा. 1 डाक्टर दिवाकर के साक्ष्य का अवलंब लिया। डा. दिवाकर ने अभिकथित किया कि अपीलार्थी को तारीख 9 अगस्त, 2008 को मनोरोग अस्पताल में भर्ती किया गया था और तारीख 12 जून, 2009 को अस्पताल से मुक्त कर दिया गया था। चिकित्सीय दस्तावेजों से यह दर्शित होता है कि वह पैरानाइज़ स्किज़ोफ़िनया से ग्रसित था। तथापि, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि अभि. सा. 1 डाक्टर दिवाकर ने तारीख 9 अगस्त, 2008 से आगे की अवधि के बारे में लिखा है, जबकि घटना तारीख 8 जुलाई, 2005 को घटित हुई थी। घटना अपीलार्थी के मनोरोग अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 वर्ष पहले घटित हुई थी। प्रतिरक्षा साक्षी हीरामन, के साक्ष्य का अवलंब लेने का भी प्रयास किया है। इस साक्षी ने अभिकथित किया है कि मानसिक बीमारी के कारण 4 वर्ष पहले अपीलार्थी असंगत रूप से बातें किया करता था। अपीलार्थी को मानसिक बीमारी के कारण थाणे स्थित अस्पताल ले जाया गया था। प्रतिरक्षा साक्षी हीरामन ने अपीलार्थी से संबंधित कोई चिकित्सीय दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है। वह ये नहीं बता सका कि अपीलार्थी की बीमारी की प्रकृति क्या थी। वह चिकित्सक का नाम भी नहीं बता सका जिसने उसका इलाज़ किया था। वह यह भी नहीं बता सका कि अपीलार्थी का इलाज़ कहां हुआ था। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पास यह दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी को थाणे स्थित अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसने आगे स्वीकार किया है कि वह अपीलार्थी की मानसिक बीमारी के बारे में निश्चित तारीख नहीं बता सकता और न ही थाणे स्थित अस्पताल जाने की तारीख बता सकता है। प्रतिरक्षा साक्षी हीरामन का साक्ष्य यह दर्शित नहीं करता है कि घटना के समय अपीलार्थी मानसिक अस्थिरता के कारण उस कार्य की प्रकृति के बारे में जानने में असमर्थ था जो वह कर रहा था कि वह गलत है या विधिविरुद्ध है। प्रतिरक्षा साक्षी हीरामन के साक्ष्य की सूक्ष्मतापूर्वक संवीक्षा करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह प्रतिरक्षा पक्ष के किसी प्रयोग का नहीं है।

11. अपराध कारित किए जाने के समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति के बाबत विश्वसनीय साक्ष्य की अनुपस्थिति में विक्षिप्त होने के अभिवाक् का कोई महत्व नहीं है। समान रूप से यह तथ्य कि अभियुक्त घटना के पश्चात् स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं था का यह अर्थ नहीं है कि वह घटना के समय विकृत चित्त का था। किसी भी स्थिति में सम्पूर्ण

परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए । पूर्ववर्ती परिस्थितियों और वे परिस्थितियां जो बाद में उत्पन्न हुईं पर भी विचार किया जाना चाहिए । प्रस्तुत मामले में यह देखा गया है कि अपीलार्थी ने घटना के पूर्व विकृत-चित्त का व्यक्ति होने का कोई लक्षण दर्शित नहीं किया था । अभि. सा. 2 पालवी अपीलार्थी के घर में निवास कर रहा था । यदि अपीलार्थी ने विकृत चित्त का व्यक्ति होने का कोई लक्षण दर्शित किया था, तो अभि. सा. 2 पालवी को इसके बाबत शपथपूर्वक कथन करना चाहिए था । इसके अतिरिक्त, किसी भी ग्रामीण ने, जिसका परीक्षण किया गया है, ने अभिकथित नहीं किया है कि अपीलार्थी घटना के तुरंत पहले अस्वस्थ चित्त का व्यक्ति था । एक अन्य तथ्य जिसको ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, यह है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से आक्रमण करने के तुरंत पश्चात् घर से भाग गया था और गायब हो गया था । अपीलार्थी को उसका ससुर अभि. सा. 2 पालवी नहीं खोज सका था । घटना के तुरंत पश्चात् भाग जाने का कार्य दर्शित करता है कि अपीलार्थी स्वयं द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति और उसके परिणामों के बारे में जानता था ।

12. जब यह दर्शित किए जाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभियुक्त की ज्ञानात्मक क्षमताएं दुर्बल हो गई हैं जिस कारणवश वह इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि उस कार्य के परिणाम क्या होंगे जो वह कर रहा है, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 अनुप्रोज्य हो जाएंगी । अपराध किए जाने के समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति के संबंध में सबूत का भार अभियुक्त पर ही होता है । यह भार उसकी स्वस्थचितता के बारे में संदेह के सृजन भाव द्वारा उन्मोचित नहीं हो सकता । अभियुक्त को उन तथ्यों और परिस्थितियों को साबित करना चाहिए जिनके आधार पर यह न्यायालय युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगा सके कि अभियुक्त अपराध किए जाने के समय अस्वस्थचितता के कारणवश कार्य की प्रकृति, कार्य की वैधता या इस बात को कि उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य गलत है या सही, जानने में असमर्थ था । यह प्रस्तुत मामले में नहीं किया गया ।

13. जैसा कि पहले अभिकथित किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का अनुपालन करने के लिए जिससे कि किसी व्यक्ति को दांडिक दायित्व से मुक्त किया जा सके, वह कार्य जिसकी शिकायत की गई है, की पूर्ववर्ती और पश्चात्वर्ती अवधि में अभियुक्त का आचरण और साथ ही कार्य के दौरान और पश्चात् आचरण, सभी की सूक्ष्मतापूर्वक

संवीक्षा की जानी चाहिए। **जय लाल** बनाम **दिल्ली प्रशासन**¹ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 84 का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त द्वारा निश्चायक रूप से यह साबित किया जाना चाहिए कि वह घटना के समय उन्मत्त था।

14. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने, अपीलार्थी की ओर से किए गए निवेदनों और हत्या की घटना के घटित होने और बाद वाली सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत हम यह विचार कर पाने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी अधिसंभाव्यता की गुरुत्ता को स्थापित किए जाने के द्वारा उसके ऊपर अधिरोपित इस भार का निर्वहन कर पाने में सफल रहा है कि वह अपराध कारित करते समय विधिक अस्वस्थचितता से ग्रसित था। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य इस मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलार्थी ने उन्मत्तता की प्रतिरक्षा, जिसका आशय उसी के द्वारा लिया गया है, को साबित नहीं किया है।

15. अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलार्थी को अपराध के साथ सम्बद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। अतः हम अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते। अपील खारिज की जाती है।

16. इस प्रक्रम पर हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती नसरीन अयूबी द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। हम उनका शुल्क 2,500/- रुपए निर्धारित करते हैं जिसका संदाय उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति द्वारा किया जाएगा।

अपील खारिज की गई।

शु.

¹ ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 15.

सरस्मिथा शर्मा (श्रीमती)

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 5 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति महेन्द्र माहेश्वरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 406, 498-क और 323 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 468] – यदि मामले में परिसीमा की अवधि समाप्त हो गई है तो उस मामले का संज्ञान लेना वर्जित है – मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406 व 323 के अधीन अपराध हेतु अधिकतम सजा तीन वर्ष है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में उपबंधित परिसीमा की दृष्टि से इन अपराधों के लिए संज्ञान तीन वर्ष समाप्ति के पश्चात् नहीं लिया जा सकता है अतः लिया गया संज्ञान परिसीमा से परे होने के कारण अपास्त किया जाता है ।

बहस सुनी गई । विद्वान् अधिवक्ता याची का तर्क रहा कि अयाची सं. 2/परिवादिया की ओर से प्रस्तुत इस्तगासा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन अनुसंधान हेतु थाने पर भेजे जाने पर पुलिस द्वारा याची के विरुद्ध किसी प्रकार का जुर्म साबित नहीं होने पर और याची का जुर्म में शामिल नहीं होने की बाबत चार्जशीट में तथ्य अंकित किए गए हैं, उसके आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 28 सितंबर, 2007 को पारित संज्ञान आदेश के अधीन बिना किसी उचित आधार के याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406 और 323 के अधीन आरोप बनना पाते हुए उक्त अपराध का संज्ञान लिया है, वह विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है । उनका यह भी कथन रहा कि प्रथमदृष्ट्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406, और 323 के अधीन क्रमशः जो भी आरोप याची के विरुद्ध लगाए गए हैं, वे वर्ष 2003 की अवधि के पूर्व के हैं तथा विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अयाची सं. 2/परिवादिया द्वारा इस्तगासा अगस्त, 2006 में पेश किया गया है, जो प्रथमदृष्ट्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अधीन मियाद के बाहर है तथा उनका कथन रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन

क्रम में याची के विरुद्ध न तो सम्पत्ति को न्यस्त किया जाना, न उसकी मांग किया जाना तथा न ही मांगने के बाद बदनीयतीपूर्वक मना किए जाने के तथ्य विद्यमान हैं। उनका यह भी कथन रहा कि पति (याची के भाई) व पत्नी के मध्य वर्ष 2003 में विवाह-विच्छेद की याचिका प्रस्तुत हो चुकी थी, जिसका जवाब अयाची सं. 2/परिवादिया की ओर से पेश किया गया, लेकिन उसमें तनिक मात्र भी कथन याची के विरुद्ध लिया गया संज्ञान आदेश विधि सम्मत नहीं है और इन तथ्यों के आधार पर संज्ञान आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406 और 323 के अधीन अधिक से अधिक कृत्य याची का वर्ष 2003 के पूर्व का बताया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अधीन प्रावधानों के अधीन समस्त तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करते हुए एवं कानूनी बिन्दुओं पर मनन करते हुए संज्ञान का आदेश पारित करें। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 इस प्रकार है “468. परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्णन – (1) इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात् नहीं करेगा। (2) परिसीमा काल – (क) छह मास होगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। (ख) एक वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। (ग) तीन वर्ष का होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है।” स्वीकृत रूप से जो मियाद का प्रावधान है, उसके तहत धारा 323, 498-क और 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध में धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन तीन वर्ष के बाद संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उपरोक्त तीन धाराओं (498-क, 323 और 406) में अधिकतम तीन वर्ष तक की ही सजा का प्रावधान है तथा धारा 468(सी) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान में एक वर्ष से अधिक व तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तीन वर्ष ही संज्ञान हेतु समयावधि निर्धारित है। इन परिस्थितियों में स्वयं अयाची सं. 2/परिवादिया ने जुलाई, 2003 के पूर्व की घटना के संबंध में वर्तमान प्रकरण में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा

लिया गया संज्ञान मियाद के बाहर है । विद्वान् अधिवक्ता अयाची सं. 2/ परिवादिया ने जून, 2006 से भी बेसिक टेलीफोन पर अयाची सं. 2/ परिवादिया को तलाक दिए जाने के क्रम में धमकी दिए जाने का तर्क दिया है । इस क्रम में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो न तो संबंधित बेसिक टेलीफोन के नम्बर अंकित किए गए हैं तथा वर्तमान याची द्वारा व्यक्तिगत रूप से धमकी दी गई हो, ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है । जुलाई, 2003 में अयाची सं. 2/परिवादिया द्वारा जो विवाह-विच्छेद की याचिका का जवाब पेश किया गया है, उसमें पूर्व का याची के किसी प्रकार के कृत्य बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किया है । उपरोक्तानुसार न्यायालय की विनम्र राय में पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान याची के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध बनना नहीं माना है, उसके विपरीत जाकर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा मात्र गवाहान के बयानों को यथावत् मानते हुए मियाद के बिन्दु को नजरअंदाज कर एवं धारा 406 भारतीय दंड संहिता के आवश्यक घटकों के बाबत तथ्यात्मक स्थिति उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी संज्ञान आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतः विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है । परिणामतः याची की ओर से प्रस्तुत यह फौजदारी विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा फौजदारी प्रकरण सं. 385/2007 “सरकार बनाम हिमांशु शर्मा व अन्य” में पारित आदेश तारीख 28 सितंबर, 2007 एवं तत्पश्चात् पुनरीक्षण न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, सं. 1, श्रीगंगानगर द्वारा फौजदारी प्रकरण सं. 60/2008 “श्रीमती शर्मिष्ठा शर्मा बनाम राजस्थान” में पारित आदेश तारीख 3 मार्च, 2009 अपास्त किया जाता है । इस याचिका की रेशनी में स्थगन याचिका भी निस्तारित मानी जाती है । (पैरा 12, 13, 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2012] 2012 क्रिमिनल एल. आर. (एस. सी.) 929 =

2013 (2) आर. एल. डब्ल्यू. 1087 (एस. सी.) :

गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ;

[2008] (2008) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 463 :

प्रियावृत्त सिंह और अन्य बनाम श्यामजी शाही ; 2

[1991] ए. आई. आर. 1991 राजस्थान 33 :

नरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और
अन्य । 17

न्यायमूर्ति महेन्द्र माहेश्वरी – याची की ओर से विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा फौजदारी प्रकरण सं. 385/2007 “राजस्थान बनाम हिमांशु शर्मा” में पारित आदेश तारीख 28 सितंबर, 2007 एवं तत्पश्चात् पुनरीक्षण न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, सं. 1, श्रीगंगानगर द्वारा फौजदारी निगरानी प्रकरण सं. 60/2008 “श्रीमती शर्मिष्ठा शर्मा बनाम राजस्थान” में पारित आदेश तारीख 3 मार्च, 2009 के विरुद्ध यह विविध फौजदारी याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन पेश की गई है, जिसके द्वारा विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 498-क और 323 के अधीन अपराध में संज्ञान लिया है ।

2. बहस सुनी गई । विद्वान् अधिवक्ता याची का तर्क रहा कि अयाची सं. 2/परिवादिया की ओर से प्रस्तुत इस्तगासा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन अनुसंधान हेतु थाने पर भेजे जाने पर पुलिस द्वारा याची के विरुद्ध किसी प्रकार का जुर्म साबित नहीं होने पर और याची का जुर्म में शामिल नहीं होने की बाबत चार्जशीट में तथ्य अंकित किए गए हैं, उसके आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 28 सितंबर, 2007 को पारित संज्ञान आदेश के अधीन बिना किसी उचित आधार के याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406 और 323 के अधीन आरोप बनना पाते हुए उक्त अपराध का संज्ञान लिया है, वह विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है । उनका यह भी कथन रहा कि प्रथमदृष्ट्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406, और 323 के अधीन क्रमशः जो भी आरोप याची के विरुद्ध लगाए गए हैं, वे वर्ष 2003 की अवधि के पूर्व के हैं तथा विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अयाची सं. 2/परिवादिया द्वारा इस्तगासा अगस्त, 2006 में पेश किया गया है, जो प्रथमदृष्ट्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अधीन मियाद के बाहर है तथा उनका कथन रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन क्रम में याची के विरुद्ध न तो सम्पत्ति को न्यस्त किया जाना, न उसकी

मांग किया जाना तथा न ही मांगने के बाद बदनीयतीपूर्वक मना किए जाने के तथ्य विद्यमान हैं। उनका यह भी कथन रहा कि पति (याची के भाई) व पत्नी के मध्य वर्ष 2003 में विवाह-विच्छेद की याचिका प्रस्तुत हो चुकी थी, जिसका जवाब अयाची सं. 2/परिवादिया की ओर से पेश किया गया, लेकिन उसमें तनिक मात्र भी कथन याची के विरुद्ध लिया गया संज्ञान आदेश विधिसम्मत नहीं है और इन तथ्यों के आधार पर संज्ञान आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्याय दृष्टांत पेश किए गए।

1. प्रियावृत सिंह और अन्य बनाम श्यामजी शाही¹

2. गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य²

3. इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता अयाची सं. 2/परिवादिया ने तर्क दिया कि विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अनुसंधान के पश्चात् तथ्यात्मक स्थिति प्रकट हुई है, उसमें मूल रूप से अयाची सं. 2/परिवादिया, उसके पिता व रमेश चन्द्र के बयानों में याची के अपने पति यानि अपने ससुराल को छोड़कर अपने पीहर आना, समय-समय पर रुपयों की मांग करना, तंग व परेशान करना, व विवाह-विच्छेद की याचिका के पश्चात् बेसिक टेलीफोन पर अपने भाई को तलाक देने की धमकी देने की बाबत तथ्य पत्रावली पर हैं और उनको ध्यान में रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय एवं पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतः न्यायोचित है। उनका कथन रहा कि उक्त दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष समानान्तर हैं, इस कारण उसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के उपबंधों के अधीन हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा कि विवाह-विच्छेद में प्रस्तुत याचिका का जवाब एक सिविल प्रक्रिया है, जिसको इस फौजदारी याचिका का भाग नहीं माना जा सकता है तथा चार्जशीट के साथ उक्त जवाब पत्रावली पर नहीं है, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया संज्ञान आदेश समुचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। उनका कथन रहा कि याची की इस याचिका में कोई सार नहीं है, अतः उसे खारिज किया जाए।

¹ (2008) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 463.

² 2012 क्रिमिनल एल. आर. (एस. सी.) 929 = 2013 (2) आर. एल. डब्ल्यू. 1087 (एस. सी.).

4. राज्य की ओर से विद्वान् लोक अभियोजक की दलील कि विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष संज्ञान लेने के समय मियाद का बिन्दु नहीं था तथा उनका कथन यह कि समस्त तथ्यात्मक स्थिति साक्ष्य का विषय है । उन्होंने वर्तमान याचिका अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया ।

5. दलीलों पर विचार किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय एवं पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश, चालान संबंधी दस्तावेज एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सामग्री का अवलोकन किया गया है ।

6. जहां तक तथ्यात्मक स्थिति का प्रश्न है, अयाची सं. 2/परिवादिया श्री वंदना शर्मा ने याची के भाई हिमांशु शर्मा के साथ तारीख 8 मई, 1995 को विवाह होना बताया है तथा विवाह के 13 माह के बाद याची का चंडीगढ़ से अपना ससुराल छोड़कर स्थायी रूप से अपने पीहर संगरिया में आना एवं तत्पश्चात् याची द्वारा मारपीट, प्रताड़ित इत्यादि से आरोप अपने बयानों में अयाची सं. 2/परिवादिया द्वारा वर्ष 2003 के पूर्व समयवधि के लगाए गए हैं । अप्रैल, 2003 में याची के भाई यानि अयाची सं. 2/परिवादिया के पति द्वारा विवाह-विच्छेद की याचिका प्रस्तुत होने पर जुलाई, 2003 में इसकी जानकारी अयाची सं. 2/परिवादिया को होना प्रकट हुआ है एवं उसके बाद अक्टूबर, 2005 में दीपावली की छुट्टियों में अयाची सं. 2/परिवादिया ने अपने पति के साथ सीकर में रहना बताया है एवं सीकर से पति द्वारा मारपीट कर निकालने के पश्चात् अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ याची पर भी बेसिक टेलीफोन पर तलाक देने की बाबत धमकी दिया जाना प्रकट किया गया है ।

7. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में अयाची सं. 2/परिवादिया एवं अन्य गवाहों के कथनों का हवाला देते हुए सास-ससुर व ननद के द्वारा मारपीट करने व घर से निकालने के संबंध में तथ्यों एवं अनुसंधान सामग्री को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406 और 323 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है । इस क्रम में जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के संबंध में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए संज्ञान के आदेश का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन अपराध में जो दंडात्मक प्रावधान हैं, उसकी परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में दी हुई है जो निम्न प्रकार है :-

“405. **आपराधिक न्यासभंग** – जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर

कोई भी अखत्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह 'आपराधिक न्यास भंग' करता है।'

8. उपरोक्त विधि के प्रावधान का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि किसी भी संपत्ति के संबंध में आपराधिक न्यास भंग तब माना जाता है, जब सर्वप्रथम संबंधित संपत्ति अमानत के रूप में किसी व्यक्ति को न्यस्त करते हुए उसका कब्जा सौंपा गया हो या उस पर अधिकार बनाए रखने की अनुमति दी गई हो, लेकिन वह व्यक्ति उक्त करार व विधि की शर्तों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भंग करते हुए दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के क्रम में नुकसान पहुंचाता है तो वह कृत्य आपराधिक न्यास भंग माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संपत्ति के न्यस्त होने के साथ-साथ उसकी मांग किए जाने, मांग करने पर भी बेईमानीपूर्वक संपत्ति को लौटाने से इनकार करने के तथ्य विद्यमान होने पर ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के अधीन अपराध के घटक उपलब्ध होना मानकर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन संज्ञान में लिया जा सकता है।

9. इस संबंध में विद्वान् विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर ऐसे किसी साक्ष्य का विवेचन नहीं किया है, जिससे यह प्रकट हो कि विवाह के समय या विवाह के पश्चात् कौन-कौन सी संपत्ति भौतिक रूप से कब्जा संभलाकर व कब न्यस्त की गई व कब मांग की गई और कब बेईमानी के उद्देश्य से देने से इनकार किया गया। हमारी विनम्र राय यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन न्यायालय को संज्ञान लेने के पूर्व तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान देकर यह विचार करना आवश्यक है जिस संपत्ति के संबंध में किसी भी पक्ष पर आरोप लगाया गया है, वह संपत्ति प्रथमतः उस पक्ष को न्यस्त होना पाया जाता है या नहीं। मात्र विवाह के संबंध में किसी विवाहिता द्वारा यदि कोई सम्पत्ति अपने साथ लाई गई है अथवा उपहार के रूप में प्राप्त हुई है, वह संपत्ति संबंधित व्यक्ति को न्यस्त

होना नहीं माना जा सकता है, मात्र आपसी मनमुटाव व वैवाहिक विवाद के कारण संबंधित स्त्री को घर से निकाल दिया जाता है या वह स्वयं ससुराल छोड़कर चली जाती है ऐसी स्थिति में पक्षों के मध्य हुए वैवाहिक विवाद के संबंध में जो कोई भी सामान/संपत्ति विवाहिता स्त्री का ससुराल में रह गया है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन न्यस्त होना नहीं माना जा सकता है बल्कि संपत्ति के न्यस्त होने के अतिरिक्त संपत्ति की नियमानुसार मांग किया जाना व मांग करने के पश्चात् बिना किसी औचित्य के संपत्ति को लौटाने से इनकार करना तथा इनकार करने में बदनीयता का होना भी एक आवश्यक तथ्य है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान के क्रम में भारतीय दंड संहिता की धारा 405 की परिधि में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया है एवं न ही इस क्रम में वर्तमान प्रकरण में इस प्रकार की स्थिति दृष्टिगत होती है। अतः याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन विद्वान् विचारण न्यायालय का संज्ञान आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

10. जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 498-क के अधीन अपराध में संज्ञान लेने का प्रश्न है, स्वीकृत रूप से उक्त धाराओं के अधीन लगाए गए सभी आरोप याची के माता-पिता के साथ-साथ याची, जो अपने ससुराल को छोड़कर पीहर में आई है, पर भी समान रूप से लगाए हैं, कोई सक्रिय कृत्य नहीं बताया है तथा इस क्रम में जो दैनिक व्यवहार एक-दूसरे के प्रति रहा है, उस संबंध में वर्ष 2003 तक आरोप लगाया जाना प्रकट होता है एवं वर्ष 2003 के पश्चात् पुनः मात्र वर्ष 2006 में बेसिक टेलीफोन से तलाक देने के बाबत धमकी दिए जाने के आरोप याची पर हैं। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि स्वयं अयाची सं. 2/परिवादिया ने अपने पति द्वारा दायर की गई विवाह-विच्छेद की याचिका के जवाब में याची के माता-पिता पर ही आरोप अवश्य लगाए हैं, लेकिन वर्तमान याची के विरुद्ध मारपीट, दहेज की मांग इत्यादि के आरोप, जो क्रूरता व मारपीट दर्शित करते हैं, लेशमात्र भी प्रकट नहीं किए हैं। इस न्यायालय की विनम्र राय में, जहां वर्ष 2003 के पूर्व की अवधि के संबंध में अयाची सं. 2/परिवादिया द्वारा याची पर क्रूरता संबंधी आरोप के बाबत तथ्यात्मक स्थिति के दौरान अनुसंधान अपने बयानों में प्रकट की गई है, वह स्थिति अयाची सं. 2/परिवादिया द्वारा अपने पति की विवाह-विच्छेद की याचिका के जवाब में अंकित तथ्यात्मक स्थिति व अतिरिक्त कथनों के

विपरीत है। अयाची सं. 2/परिवादिया ने विवाह-विच्छेद की याचिका के जवाब में याची के माता-पिता के विरुद्ध जो तथ्य प्रकट किए हैं, उसमें वर्तमान याची के संबंध में क्रूरता संबंधी कोई आरोप होना प्रकट नहीं होता है। जबकि अयाची सं. 2/परिवादिया को विवाह-विच्छेद की याचिका के जवाब में समस्त आरोप, जो कि उसके द्वारा पुलिस बयानों में वर्ष 2003 के पूर्व की घटना के क्रम में वर्ष 2006 में लगाए गए हैं, को प्रकट करने का पूर्ण अवसर था।

11. विद्वान् अधिवक्ता अयाची सं. 2/परिवादिया का कथन रहा कि विवाह-विच्छेद की याचिका का जवाब एक सिविल कार्यवाही है, उसे फौजदारी कार्यवाही का भाग नहीं माना जा सकता है तथा उनका कथन रहा कि विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त जवाब याचिका पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थी। हमारी विनम्र राय में जहां अयाची सं. 2/परिवादिया के कथन लिखित रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं एवं उन कथनों में तनिक मात्र भी कोई आरोप याची के विरुद्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में यह न्यायालय मात्र विद्वान् विचारण न्यायालय में विवाह-विच्छेद की याचिका के जवाब की प्रति प्रस्तुत नहीं होने से बिना किसी आधार के किसी व्यक्ति को विचारण के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन वर्तमान प्रकरण में दखल किया जाना न्यायोचित है।

12. भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 406 और 323 के अधीन अधिक से अधिक कृत्य याची का वर्ष 2003 के पूर्व का बताया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अधीन प्रावधानों के अधीन समस्त तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करते हुए एवं कानूनी बिन्दुओं पर मनन करते हुए संज्ञान का आदेश पारित करें। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 निम्न प्रकार है :-

“468. परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्णन –

(1) इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात् नहीं करेगा।

(2) परिसीमा काल –

(क) छह मास होगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है ।

(ख) एक वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है ।

(ग) तीन वर्ष का होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है ।”

13. स्वीकृत रूप से उपरोक्तानुसार जो मियाद का प्रावधान है, उसके तहत धारा 323, 498-क और 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध में धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन तीन वर्ष के बाद संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उपरोक्त तीन धाराओं (498-क, 323 और 406) में अधिकतम तीन वर्ष तक की ही सजा का प्रावधान है तथा धारा 468(सी) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान में एक वर्ष से अधिक व तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए तीन वर्ष ही संज्ञान हेतु समयावधि निर्धारित है । इन परिस्थितियों में स्वयं अयाची सं. 2/परिवादिया ने जुलाई, 2003 के पूर्व की घटना के संबंध में वर्तमान प्रकरण में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया संज्ञान मियाद के बाहर है ।

14. विद्वान् अधिवक्ता अयाची सं. 2/परिवादिया ने जून, 2006 से भी बेसिक टेलीफोन पर अयाची सं. 2/परिवादिया को तलाक दिए जाने के क्रम में धमकी दिए जाने का तर्क दिया है । इस क्रम में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो न तो संबंधित बेसिक टेलीफोन के नम्बर अंकित किए गए हैं तथा वर्तमान याची द्वारा व्यक्तिगत रूप से धमकी दी गई हो, ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है । जुलाई, 2003 में अयाची सं. 2/परिवादिया द्वारा जो विवाह-विच्छेद की याचिका का जवाब पेश किया गया है, उसमें पूर्व का याची के किसी प्रकार के कृत्य बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किया है । उपरोक्तानुसार हमारी विनम्र राय में पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद याची के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध बनना नहीं माना है, उसके विपरीत जाकर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा मात्र गवाहान के बयानों को यथावत् मानते हुए मियाद के बिन्दु को नजरअंदाज कर एवं धारा 406 भारतीय दंड संहिता के आवश्यक घटकों के बाबत तथ्यात्मक स्थिति उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी संज्ञान आदेश पारित किया गया है, वह

पूर्णतः विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

15. परिणामतः याची की ओर से प्रस्तुत यह फौजदारी विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा फौजदारी प्रकरण सं. 385/2007 “सरकार बनाम हिमांशु शर्मा व अन्य” में पारित आदेश तारीख 28 सितंबर, 2007 एवं तत्पश्चात् पुनरीक्षण न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, सं. 1, श्रीगंगानगर द्वारा फौजदारी प्रकरण सं. 60/2008 “श्रीमती शर्मिष्ठा शर्मा बनाम राजस्थान” में पारित आदेश तारीख 3 मार्च, 2009 अपास्त किया जाता है । इस याचिका की रेशनी में स्थगन याचिका भी निस्तारित मानी जाती है ।

16. सुनवाई के दौरान विद्वान् लोक अभियोजक व विद्वान् अधिवक्ता याची द्वारा न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि अधिकांशतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मात्र परिवाद व पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान पर बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए संज्ञान का आदेश पारित किया जाता है, जिससे न केवल अधीनस्थ न्यायालय में संबंधित व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल संज्ञान लिया गया है, के धन व समय की बर्बादी होती है, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय के कार्यभार के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय व उच्च न्यायालय में भी इसी प्रकार के प्रकरणों के क्रम में संबंधित कानून के तहत कार्यवाही की जाकर कार्यभार बढ़ता है । ऐसी स्थिति में संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों में संज्ञान लेने से पूर्व कानून के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाए ।

17. इस तथ्य पर विचार किया गया । वर्तमान प्रकरण की रेशनी में अन्य इसी प्रकार के प्रकरण जो धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मियाद के बिन्दु के साथ-साथ धारा 498-क, 406 व 323 भारतीय दंड संहिता से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत परिवाद व चालान के आधार पर प्रस्तुत होने पर अनावश्यक रूप से विचारण न्यायालय, निगरानी न्यायालय व उच्च न्यायालय में मुकदमे की अधिकता न हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कानूनी प्रावधानों की परिधि में कार्यवाही करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को इस आदेश की प्रति भेजकर उपरोक्त कानूनी स्थिति से अवगत कराने हेतु सूचित कराएं तथा **नरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान**

उच्च न्यायालय और अन्य¹ वाले मामले में अंकित निम्न निर्देश :-

“उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि अर्हित व्यक्तियों को नियुक्त करते हुए अनुवाद विभाग का सृजन करें और उच्च न्यायालय प्राधिकारी अपने अधिकारी के साथ अनुवाद को प्रमाणित करें और ऐसा अनुवाद किया जाना राजभाषा अधिनियम की धारा 7 के उपबंध के अनुपालन के लिए पर्याप्त होगा।”

के अधीन उच्च न्यायालय में कार्यरत अनुवादक से इस आदेश का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया जाकर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस आदेश को पालनार्थ परिचालित किया जाए।

याचिका मंजूर की गई।

आर्य

¹ ए. आई. आर. 1991 राजस्थान 33.

संसद् के अधिनियम
भविष्य निधि अधिनियम, 1925
(1925 का अधिनियम संख्यांक 19)¹

[27 अगस्त, 1925]

**सरकारी भविष्य निधियों और अन्य भविष्य निधियों से
संबंधित विधि को संशोधित और समेकित
करने के लिए
अधिनियम**

सरकारी भविष्य निधियों और अन्य भविष्य निधियों से संबंधित विधि को संशोधित और समेकित करना समीचीन है ;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ — (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भविष्य निधि अधिनियम, 1925 है ।

(2) इसका विस्तार ²[जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय] ^{3****} संपूर्ण भारत पर है ।

¹ उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1924, भाग 5, पृ. 122 । इस अधिनियम को 1936 के विनियम सं. 4 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोण्डमाल जिले में, 1936 के विनियम सं. 5 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में तथा 1941 के मध्य प्रान्त तथा बरार अधिनियम सं 4 द्वारा आंशिक रूप में बरार में भी प्रवृत्त घोषित किया गया है ; इसका आंशिक रूप में संशोधन उत्तर प्रदेश राज्य में 1953 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 19 द्वारा किया गया है ।

इस अधिनियम का 1962 के विनियम सं. 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर ; 1963 के विनियम सं. 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर ; 1063 के विनियम सं. 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर और 1965 के विनियम सं. 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्काद्वीप, मिनीकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह पर विस्तार किया गया ।

² 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “भाग ख राज्यों को छोड़ कर” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियमों तथा अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा “ब्रिटिश बलूचिस्तान सहित” शब्दों का लोप किया गया ।

(3) यह उस तारीख¹ को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो, –

(क) “अनिवार्य निक्षेप” से किसी भविष्य निधि में ऐसा अभिदाय या निक्षेप अभिप्रेत है जो उस निधि के नियमों के अधीन, जीवन बीमा की किसी पालिसी के संबंध में प्रीमियम के संदाय² [या किसी कुटुम्ब पेंशन निधि के संबंध में अभिदाय या प्रीमियम के संदाय] के प्रयोजन से अन्यथा, मांग पर तब तक प्रतिसंदेय नहीं है जब तक कोई विनिर्दिष्ट घटना न हो जाए और कोई अंशदान³ तथा कोई ऐसा ब्याज या वृद्धि जो किसी ऐसे अभिदाय, निक्षेप या अंशदान पर निधि के नियमों के अधीन प्रोद्भूत हो जाती है और कोई ऐसा अभिदाय, निक्षेप, अंशदान, ब्याज या वृद्धि भी जो ऐसी किसी घटना के होने के पश्चात् अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में बाकी बच जाती है, इसके अंतर्गत है ;

(ख) “अंशदान” से कोई ऐसी रकम अभिप्रेत है जो किसी भविष्य निधि में⁴ [उस निधि का प्रबंध करने वाले किसी प्राधिकारी] द्वारा, उस निधि में⁵ [किसी खाते में जमा अभिदाय, या निक्षेप या अतिशेष] के परिवर्धन के तौर पर जमा की गई है ; और “अंशदायी भविष्य निधि” से ऐसी भविष्य निधि अभिप्रेत है जिसके नियम अंशदानों को जमा करने के लिए उपबंध करते हैं ;

(ग) “आश्रित” से किसी भविष्य निधि में अभिदाय या निक्षेप करने वाले किसी मृत व्यक्ति के निम्नलिखित नातेदार अभिप्रेत हैं, अर्थात् पत्नी, पति, माता-पिता, संतान, अवयस्क भाई, अविवाहित बहिन और मृत पुत्र की विधवा तथा संतान, और जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के माता-पिता में

¹ 1 अप्रैल, 1926, भारत का राजपत्र, 1925 भाग 1, पृ. 1182 ।

² 1930 के अधिनियम सं. 1 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

³ 1930 के अधिनियम सं. 1 की धारा 2 द्वारा “ऐसे किसी अभिदाय या निक्षेप की बाबत जमा” शब्दों का लोप किया गया ।

⁴ 1925 के अधिनियम सं. 28 की धारा 2 द्वारा “प्राधिकार जिसके अधीन निधि गठित की गई है” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ 1930 के अधिनियम सं. 1 की धारा 2 द्वारा “या, अभिदाय या निक्षेप की बाबत से अन्यथा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

से कोई भी जीवित नहीं है वहां पितामह-पितामही ;

(घ) “सरकारी भविष्य निधि” से ऐसी कोई भविष्य निधि अभिप्रेत है जो रेल भविष्य निधि से भिन्न है और जो ¹[सेक्रेटरी आफ स्टेट, केन्द्रीय सरकार, क्राउन रिप्रिजेंटेटिव या किसी राज्य सरकार] के प्राधिकार से, उस ²[सरकार की सेवा में व्यक्तियों] के अथवा ³[शैक्षिक संस्थाओं में नियोजित अथवा केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान निकायों द्वारा नियोजित] किसी वर्ग के व्यक्तियों या किन्हीं वर्गों के व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, ⁴[तथा इस अधिनियम में सरकार के प्रति निर्देशों को तदनुसार अर्थ किया जाएगा];

(ङ) “भविष्य निधि” से ऐसी निधि अभिप्रेत है जिसमें किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के अभिदाय या निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं और उनके पृथक् खातों में रखे जाते हैं, और कोई अंशदान तथा कोई ऐसा ब्याज या वृद्धि जो ऐसे ⁵*** अभिदाय, निक्षेप या अंशदान पर निधि के नियमों के अधीन प्रोद्भूत होती है इसके अंतर्गत है ;

⁶[च) “रेल प्रशासन” से अभिप्रेत है –

(i) ⁷[भारत के किसी भाग में] या तो ⁸[यूनाइटेड किंगडम की] पार्लियामेंट के किसी विशेष अधिनियम या किसी भारतीय विधि के अधीन अथवा सरकार के साथ की गई किसी संविदा के अधीन किसी रेल

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1942 के अधिनियम सं. 25 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “इसके कर्मचारी” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1927 के अधिनियम सं. 7 की धारा 2 द्वारा “शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों के लिए” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁵ 1930 के अधिनियम सं. 1 की धारा 2 द्वारा “ऐसे अभिदायों या निक्षेपों की बाबत जमा” शब्दों का लोप किया गया ।

⁶ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल खंड (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁷ 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “भाग क राज्य या भाग ग राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁸ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंतःस्थापित ।

या ट्राम का प्रशासन करने वाली कोई कंपनी, या

(ii) ¹[केन्द्रीय सरकार] द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किसी रेल या ट्राम का प्रबंधक,

और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी दशा में, यथास्थिति, ¹[केन्द्रीय सरकार] या वह राज्य सरकार इसके अंतर्गत है ;]

(छ) “रेल भविष्य निधि” से किसी रेल प्रशासन के प्राधिकार से उसके किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के लिए बनाई गई भविष्य निधि अभिप्रेत है ।

3. अनिवार्य निक्षेप का संरक्षण – (1) किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि का कोई अनिवार्य निक्षेप किसी भी प्रकार से समनुदेशित या भारित नहीं किया जा सकेगा और अभिदायकर्ता अथवा निक्षेपकर्ता द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी सिविल, राजस्व या दांडिक न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकेगा तथा न तो कोई शासकीय समुदेशिनी और न कोई रिसीवर ही, जो प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) के अधीन नियुक्त किया गया हो, किसी ऐसे अनिवार्य निक्षेप का हकदार होगा और न उसका उस पर कोई दावा ही होगा ।

(2) किसी ऐसी निधि में किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के समय जमा कोई राशि, जो निधि के नियमों के अधीन उस अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के किसी आश्रित को अथवा ऐसे व्यक्ति को संदेय है जो इस निमित्त संदाय प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती के अधीन रहते हुए और उस दशा को छोड़कर जब आश्रित अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की विधवा या संतान है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किए गए किसी समनुदेशन के अधीन, किसी समनुदेशिनी के अधिकारों के भी अधीन रहते हुए, आश्रित में निहित होगी और मृत व्यक्ति द्वारा उपगत अथवा उस अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की मृत्यु से पूर्व आश्रित द्वारा उपगत किसी

¹ भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा “संघीय रेल प्राधिकरण” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

ऋण या अन्य दायित्व से, यथापूर्वोक्त अधीन रहते हुए, मुक्त होगी ।

4. **प्रतिसंदायों के बारे में उपबंध** – (1) जब किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के नियमों के अधीन किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि या उसका अतिशेष इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई कटौती करने के पश्चात्, संदेय हो गया है तब वह अधिकारी, जिसका कर्तव्य उसका संदाय करना है, यथास्थिति, उस राशि या अतिशेष का अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता को संदाय करेगा अथवा यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो –

(क) यदि वह राशि या अतिशेष अथवा उसका कोई भाग धारा 3 के उपबंधों के अधीन किसी आश्रित में निहित है तो उसका संदाय उस आश्रित को या ऐसे व्यक्ति को करेगा जो उसके निमित्त संदाय प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है ; या

(ख) यदि सम्पूर्ण राशि या अतिशेष पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है तो उसका या उसके किसी भाग का संदाय, जो खंड (क) के अधीन संदेय नहीं है, निधि के नियमों के अधीन उसे प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किसी व्यक्ति को अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नामनिर्देशित नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को करेगा जो उसे प्राप्त करने के लिए, अन्यथा उसका हकदार प्रतीत हो ; या

(ग) यदि ऐसी राशि या अतिशेष या उसका कोई भाग खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय नहीं है, तो उसका संदाय –

(i) निधि के नियमों के अधीन उसे प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति द्वारा मृत व्यक्ति की संपदा का प्रबंध उसे देना साक्षित करने वाला प्रोबेट या प्रशासन पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अधिनियम, 1889¹ (1889 का 7) के अधीन या 1827 के मुम्बई विनियम 8 के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र, जो उसके धारक को ऐसी राशि, अतिशेष या भाग का संदाय प्राप्त करने का हकदार बनाता हो, पेश किए जाने पर करेगा, या

¹ अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) देखिए ।

(ii) यदि कोई नामनिर्देशित व्यक्ति नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को करेगा जो ऐसा प्रोबेट, प्रशासन पत्र या प्रमाणपत्र पेश करे :

परन्तु जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा संपूर्ण राशि या उसका कोई भाग इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित किया गया है, और समनुदेशन की लिखित सूचना अधिकारी को समनुदेशिनी से मिल चुकी है, वहां वह अधिकारी इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई कटौती तथा अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की विधवा या संतान को या उनके निमित्त खंड (क) के अधीन देय कोई संदाय करने के पश्चात् –

(i) यदि अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता, अथवा यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो वह व्यक्ति, जिसको किसी विधिमान्य समनुदेशन के अभाव में वह राशि या अतिशेष उस उपधारा के अधीन संदेय होता, अपनी लिखित सहमति दे देता है तो, यथास्थिति, उस राशि या भाग का या उसके अतिशेष का संदाय समनुदेशिनी को करेगा, या

(ii) यदि ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होती है तो, यथास्थिति, उस राशि, भाग या अतिशेष का संदाय, उसे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के बारे में किसी सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय तक के लिए, रोक रखेगा ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत संदाय करने पर, यथास्थिति, सरकार या रेल प्रशासन, अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि में से इतनी राशि के संबंध में, जितनी इस प्रकार संदत्त की गई रकम के बराबर है समस्त दायित्व से पूर्ण रूप से उन्मोचित हो जाएगा ।

5. नामनिर्देशितियों के अधिकार – ¹[(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता द्वारा उस निधि में अपने खाते में जमा राशि या उसके किसी भाग के, वसीयती या अन्य, किसी व्ययन में से किसी बात के होते हुए भी, जहां निधि के नियमों के अनुसार सम्यक् रूप से किया गया कोई नामनिर्देशन, उस राशि के संदेय हो जाने के पूर्व, अथवा उस राशि के संदेय हो जाने पर उसका संदाय किए जाने के पूर्व अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की मृत्यु पर ऐसी संपूर्ण राशि या उसके किसी भाग को प्राप्त

¹ 1946 के अधिनियम सं. 11 की धारा 2 द्वारा मूल उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करना तात्पर्यित करता है वहां उक्त व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए, उस अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की यथापूर्वोक्त मृत्यु पर, यथास्थिति, ऐसी राशि या उसके किसी भाग को प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा, किन्तु यदि –

(क) ऐसा नामनिर्देशन उसी प्रकार किए गए दूसरे नामनिर्देशन से किसी समय परिवर्तित किया गया है अथवा उन नियमों द्वारा विहित रीति से और प्राधिकारी को दी गई सूचना से अभिव्यक्ततः रद्द कर दिया गया है ; अथवा

(ख) ऐसा नामनिर्देशन किसी समय उसमें विनिर्दिष्ट किसी घटना के होने के कारण अविधिमान्य हो गया है,

तो वह व्यक्ति हकदार नहीं होगा, और यदि उक्त व्यक्ति, अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता से पहले मर जाता है तो नामनिर्देशन, जहां तक वह उक्त व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार से संबंधित है, शून्य और प्रभावहीन हो जाएगा :

परन्तु जहां निधि के नियमों के अनुसार, नामनिर्देशन में मृत व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्रदान करने के लिए सम्यक् रूप से उपबंध किया गया है वहां ऐसा अधिकार, उक्त व्यक्ति की यथापूर्वोक्त मृत्यु हो जाने पर ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा ।।

¹(2) ²[भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39)] या 1827 के मुम्बई विनियम 8 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को जो यथापूर्वोक्त हकदार हो जाता है, ऐसी राशि या भाग का संदाय प्राप्त करने का हकदार बनाने वाला एक प्रमाणपत्र, यथास्थिति, उस अधिनियम या उस विनियम के अधीन ³[दिया जा सकेगा] और ऐसा प्रमाणपत्र मृत व्यक्ति की सम्पदा के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रोबेट या प्रशासन पत्र दिए जाने से अविधिमान्य या अधिक्रान्त हुआ नहीं समझा जाएगा ।

¹ अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) देखिए ।

² 1950 के अधिनियम सं. 35 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अधिनियम, 1889” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1946 के अधिनियम सं. 11 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹[(3) भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1946 (1946 का 2) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंध उस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किए गए ऐसे नामनिर्देशनों को भी लागू होंगे :

परंतु इस प्रकार संशोधित इस उपधारा के उपबंध किसी ऐसे मामले पर प्रभाव नहीं डालेंगे जिसमें उक्त तारीख से पूर्व, किन्हीं नियमों के अनुसार सम्यक्तः किए गए किसी नामनिर्देशन के अनुसरण में किसी राशि का संदाय कर दिया गया है या निधि के नियमों के अधीन वह संदेय हो गई है ॥

6. कटौतियां करने की शक्ति – जब किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के, जो अंशदायी भविष्य निधि है, किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि संदेय हो जाती है तब, यदि ²[निधि के नियमों में उस निमित्त विनिर्दिष्ट] प्राधिकारी निदेश देता है तो उसमें से निम्नलिखित रकम काट ली जाएगी, और, ³[यथास्थिति, सरकार या रेल प्रशासन] को संदत्त कर दी जाएगी –

(क) अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता द्वारा उपगत किसी दायित्व के अधीन ³[सरकार या रेल प्रशासन] को देय कोई रकम किन्तु जो किसी भी दशा में अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा किन्हीं अंशदानों की तथा किसी ऐसे ब्याज या वृद्धि की, जो ऐसे अंशदानों पर प्रोद्भूत हो गई है, कुल रकम से अधिक नहीं होगी ; या

(ख) जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता को ⁴[उसके नियोजन से] किन्हीं ऐसे कारणों से, जो निधि के नियमों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट हैं, पदच्युत कर दिया गया है अथवा जहां उसने ऐसे नियोजन को उसके प्रारंभ के पांच वर्ष के अन्दर त्याग दिया है, वहां

¹ 1946 के अधिनियम सं. 11 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।

² 1925 के अधिनियम सं. 28 की धारा 3 द्वारा “जिससे कि निधि गठित हुई है” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1925 के अधिनियम सं. 28 की धारा 3 द्वारा “उस प्राधिकरण” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ 1925 के अधिनियम सं. 28 की धारा 3 द्वारा “उस प्राधिकरण के नियोजन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

किन्हीं ऐसे अंशदानों, ब्याज और वृद्धि की संपूर्ण रकम या उसका कोई भाग ।

¹[6क. सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के भीतर पूर्व अनुज्ञा के बिना वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की दशा में सरकारी अंशदानों को रोक लेना या उनकी वसूली – (1) इस धारा में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) “केन्द्रीय सरकार का अधिकारी” से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई अंशदायी भविष्य निधि में कोई ऐसा अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता अभिप्रेत है, जो अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 का सदस्य है, किन्तु किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी सेवा-संविदा के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी इसके अंतर्गत नहीं है ;

(ख) “वाणिज्यिक नियोजन” से व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या वृत्तिक कारबार में लगी हुई किसी कंपनी, सहकारी सोसाइटी, फर्म या व्यष्टि के अधीन (अभिकर्ता की हैसियत सहित) किसी भी हैसियत में नियोजन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

(i) किसी कंपनी का निदेशक पद ;

(ii) किसी सहकारी सोसाइटी में अध्यक्ष, सभापति, प्रबंधक, सचिव, कोषपाल जैसे किसी भी नाम से ज्ञात किसी पद को, चाहे वह निर्वाचित हो या न हो, धारण करना ; और

(iii) ऐसे विषयों में सलाहकार या परामर्शी के तौर पर या तो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में व्यवसाय प्रारम्भ करना, जिनकी बाबत –

(क) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के पास कोई वृत्तिक अर्हताएं नहीं हैं और वे विषय, जिनकी बाबत ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना है या चलाया जाता है, उसकी शासकीय जानकारी या अनुभव से संबद्ध हैं, या

¹ 1975 के अधिनियम सं. 46 की धारा 2 द्वारा (7-2-1977 से) अंतःस्थापित ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के पास वृत्तिक अर्हताएं हैं, किन्तु वे विषय, जिनकी बाबत ऐसा व्यवसाय प्रारंभ किया जाना है, ऐसे हैं जिनसे यह संभव है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन उसके द्वारा धारित पदों के कारण उसके व्यवहारियों को नावाजिब फायदा हो ; या

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को ऐसे कार्य का भार ग्रहण करना है जिसमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों या अधिकारियों से संपर्क या संबंध अंतर्ग्रस्त है ;

किन्तु किसी ऐसे निगम या कंपनी में या उसके अधीन नियोजन, जो पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है अथवा किसी ऐसे निकाय में या उसके अधीन नियोजन, जो पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से सरकार के नियंत्रण में है या उसके द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, इसके अंतर्गत नहीं है ;

(ग) “सरकारी अंशदान” से भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 46) के प्रारंभ होने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम, 1914 (1914 का 9) के अर्थ में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किसी अवधि की बाबत किए गए अंशदान अभिप्रेत हैं ;

(घ) “विहित” से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी को, उस दशा में जब वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है, किसी अंशदायी भविष्य निधि में उसके नाम में जमा किए गए, सरकारी अंशदानों के संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा ।

क्रमशः.....